R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 05

01 से 15 दिसम्बर 2021

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.

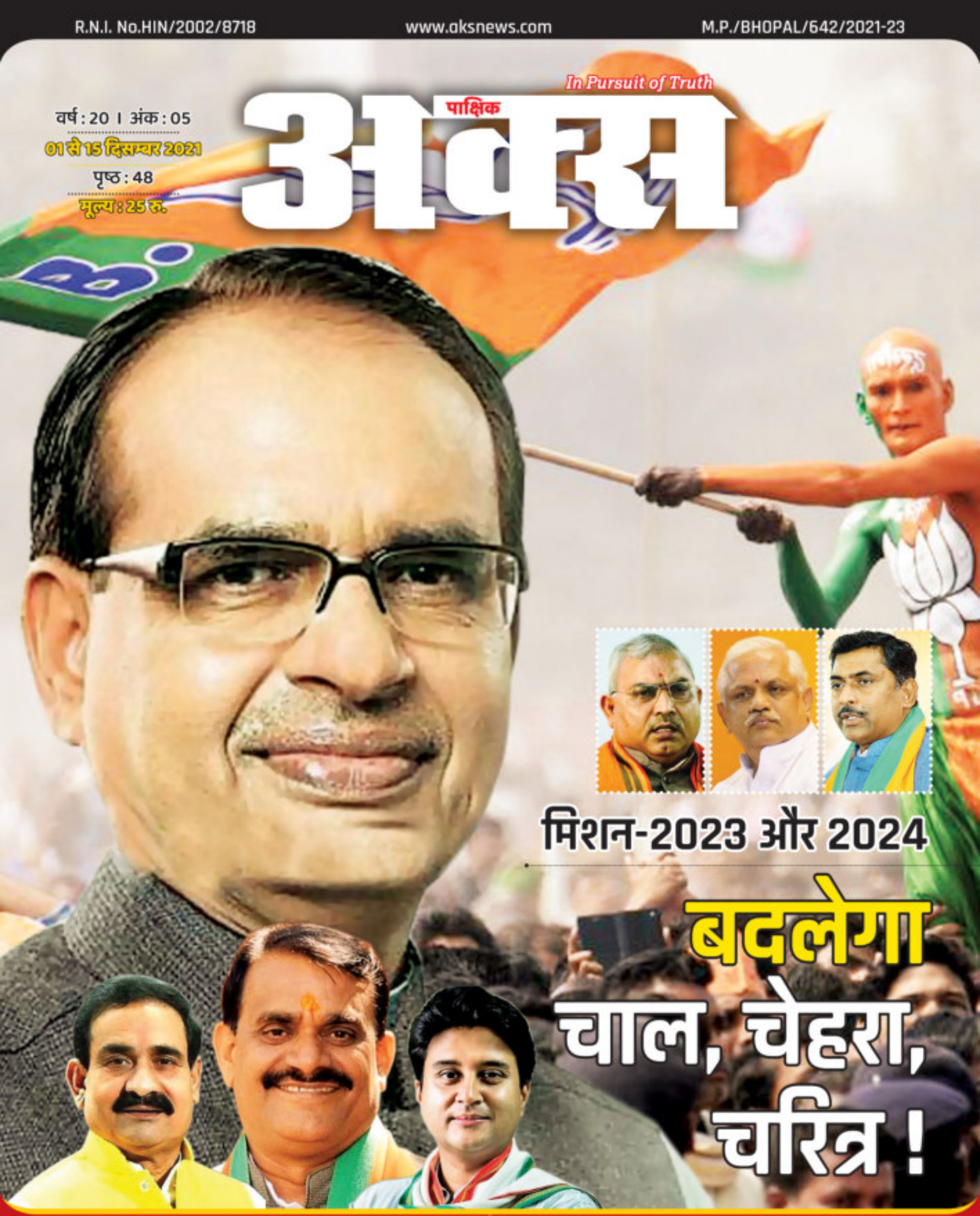

मिशन-2023 और 2024

बदलेगा चाल, चेहरा, चरित्र !

आधे से अधिक मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहद खराब

भाजपा का मप्र सहित देशभर में 51 फीसदी वोट का टारगेट

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजकाज

9 | सियासत में सिंधिया घराने की चौथी पीढ़ी!

ग्वालियर राजघराने की चौथी पीढ़ी सियासत में आने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन ने जिस तरह से अपना 26वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं के साथ मनाया, उससे साफ संकेत है कि...

राजपथ

10-11 | चुनौती के लिए भरपूर तैयारी

2018 की रणनीति पर कांग्रेस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी संगठित होकर भाजपा की खामियों को जनता के बीच ले जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं।

खेती किसानी

19 | धान की खरीद में कालाबाजारी

देश के किसान इन दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सरकार मौखिक रूप से कई बार कह चुकी है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। लेकिन क्या यह सत्य है? शायद नहीं। क्योंकि हर छमाही रबी...

बुंदेलखंड

23 | बुंदेलखंड की सियासी बयार

उप्र में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, शहरों से लेकर गांवों तक के मतदाताओं में सियासी दल गुणा-भाग कर अपना-अपना जनाधार मजबूत करने की जुगत में लगे हैं। ऐसे में बुंदेलखंड में एक बार फिर से सियासी बयार तेज हो गई है। सूखे, गरीबी से बेहाल लोगों...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

चाल, चेहरा और चरित्र वाली भाजपा में बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। शायद इसकी वजह है मिशन-2023 और 2024। मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा ने मप्र सहित देशभर में 51 फीसदी वोट का टारगेट रखा है। इस टारगेट को पाने के लिए मप्र में सत्ता और संगठन को कसौटी पर परखा जा रहा है। इसके लिए विगत दिनों विधायकों से दो दिनों तक वन-टू-वन की गई, उसके बाद कार्यसमिति में टारगेट तय किया गया, फिर मंत्रियों, पदाधिकारियों से उनके कार्यकाल का हिसाब लिया गया।

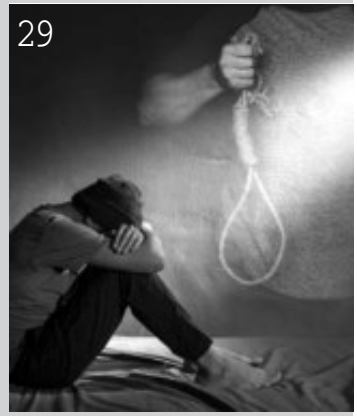

राजनीति

30-31 | पांच राज्यों का घमासान

पश्चिम बंगाल के बाद उपचुनावों में भाजपा को आशातीत सफलता नहीं मिली है। ऐसे में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव भाजपा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं हैं। वहीं कांग्रेस, आप, टीएमसी, सपा, बसपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां भाजपा के खिलाफ...

महाराष्ट्र

35 | अंतिम सांसें गिन रहा माओवादी...

महाराष्ट्र पुलिस के सी-60 दस्ते ने छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे गढ़चिरौली में दो-तीन शीर्ष कमांडरों सहित 26 नक्सलियों को मार गिराया। यह जवाबी कार्रवाई पिछले दिनों 15 पुलिस कमांडों की शहादत के बाद की गई थी। इस ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सी-60 दस्ते के सदस्य...

बिहार

38 | नई जोड़ी क्या गुल खिलाएगी ?

बिहार का तापमान इस वक्त भले ही कम हो, लेकिन सियासी पारा रोज बढ़ रहा है। दिल्ली में नेताओं की भेंट-मुलाकात ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय जनता दल के बीच आगामी विधान परिषद् चुनाव...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

पीटना ही है लकीर, तो खींचों नई लकीर...

विनोद बक्सरी का एक शेर है....

व्यथा सुनाने से नहीं बदलती कभी तकदीर
पीटना ही है लकीर, तो खींचों नई लकीर...

इन दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत अक्सर विभाजन के दर्द को बयां करते सुने जा सकते हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार 74 साल पुराने घाव को संघ प्रमुख क्यों कुरेद रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भागवत की फिक्र वाजिब है, लेकिन विभाजन के दर्द की दवा नहीं, बीमारी लाइलाज है! ऐसे में लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। अब जरूरत है, नई लकीर खींचने की। लेकिन यह सभी जानते हैं कि संघ या संघ प्रमुख मोहन भागवत बेवजह कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। उसके पीछे सोची-समझी रणनीति होती है। दरअसल, मोहन भागवत हिंदुत्व को भी संघ और भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे में ही पिरोकर प्रोजेक्ट करते हैं और लगे हाथ उसे देश के विभाजन से भी जोड़ देते हैं। बात विभाजन की हो तो पाकिस्तान का नाम आना ही है, जो चुनावों में हमेशा ही भाजपा के कैंपेन को कुछ ज्यादा ही धारदार बना देता है। संघ प्रमुख हाल फिलहाल विभाजन की विभीषिका की बार-बार याद दिला रहे हैं और समाधान तलाशने की बात भी करते हैं, समाधान, विभाजन को निरस्त करने में ही है। मोहन भागवत को जो भी लगता हो। ये भी सही है कि सत्ता और चुनावी राजनीति के लिए भी ये असरदार हथियार है, लेकिन दूर-दूर तक ऐसी कोई संभावना तो लगती ही नहीं, जिसमें विभाजन को निरस्त करने का कोई तरीका बना हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत विभाजन को निरस्त करना देश के बंटवारे के दर्द का समाधान बता रहे हैं। राजनीतिक मतलब और भाव पक्ष को अलग रखकर देखें तो ये भारत और पाकिस्तान को मिलाकर पुराना हिंदुस्तान बनाने जैसी कल्पना ही लगती है। पहले भी कई नेता ऐसा प्रस्ताव रख चुके हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पहले की तरह भौगोलिक तौर पर भारत बनाने की बात होती है। मोहन भागवत के मुताबिक, विभाजन कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व का प्रश्न है। कहते हैं, खून की नदियां ना बहें इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया और नहीं करते तो उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। मोहन भागवत की सलाह है, देश का विभाजन कभी ना मिटने वाली वेदना है। इसका निराकण तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये विभाजन निरस्त भला कैसे होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लायक सामान्य माहौल तो बन नहीं पा रहा है। जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक तरीके से संसद के जरिए धारा 370 खत्म की जा चुकी है। पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया ने इसे भारत का आंतरिक मामला ही माना है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में खून-खराबा तो रुक नहीं पा रहा है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के न थम पाने की वजह सरहद पार से मिल रहा सपोर्ट बताया जाता है। उसी की वजह से स्थानीय नौजवान भी आतंकवाद के रास्ते चलने लग रहे हैं, भले ही सेना कहे कि अब आतंकियों की शेल्फ लाइफ छोटी हो गई है, लेकिन सब रुक कहां रहा है? ऐसे में कैसे और किस भरोसे उम्मीद करें कि विभाजन की वेदना का कोई समाधान कभी मिल भी पाएगा, क्योंकि ये वो दर्द नहीं है जिसके लिए कोई पेनकिलर बना हो। ये सहन करने वाला ही दर्द है। दर्द की कोई दवा नहीं है। दरअसल, ये दर्द लाइलाज है और अगर ये केवल राजनीतिक विमर्श नहीं है तो वक्त जाया करने का कोई फायदा भी नहीं है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 5, पृष्ठ-48, 1 से 15 दिसंबर, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

कांग्रेस चिंतित

मप्र कांग्रेस ने उपचुनाव के बाद अब 2023 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव के फीडबैक कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। कांग्रेस हर वार्ड में अब वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाकर संगठन को मजबूत करने का प्रयोग कर रही है। ताकि वे 2023 के चुनाव में मजबूती से उतर सके।

● **शैलेंद्र झा,** राजगढ़ (म.प्र.)

आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं

प्रदेश में पहली बार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा 2021 की शुरुआत में महिलाओं को ड्राइविंग ट्रेनिंग की शुरुआत की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी इस योजना को शामिल कर लिया गया है।

● **हेमा नानकानी,** सीहोर (म.प्र.)

कुपोषण से राहत कब

कुपोषण प्रदेश सहित देशभर में बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। केवल सरकारी प्रयास से ही कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसमें आमजन की सहभागिता जरूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े कारणों के अलावा इस समस्या के सामाजिक कारण भी हैं।

● **प्रभु शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

कहीं सपना अधूरा न रह जाए...

राजधानी भोपाल को पेरिस बनाने का सपना कहीं सपना न रह जाए। राजधानी की खूबसूरती पर दाग लगा रही सड़कों की तस्वीरें अभी भी नहीं बदल पाई है। राजधानी में मानसून के महीनों में हरियाली और तालाबों की खूबसूरती तो बढ़ गई, पर सड़कें बद से बदतर हो चली हैं। लावारिस छोड़ दी गईं, इन सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। भोपाल में अभी भी 60 प्रतिशत सड़कें खराब हालत में हैं, जबकि 6 से 20 अक्टूबर के बीच में सड़कें 100 प्रतिशत सुधर जानी चाहिए थीं। कई इलाकों में तो सिर्फ मिट्टी और चूरी डालकर गड्ढे भर दिए गए। इस कारण धूल के गुबार उड़ रहे हैं और एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है।

● **राकेश श्रीवास्तव,** जबलपुर (म.प्र.)

कांग्रेस को मजबूत होना होगा

कांग्रेस का दावा यह है कि उसके बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। बेशक, कुछ राज्यों में विभिन्न वजहों और सत्ता विरोधी रुझान की वजह से कांग्रेस की हालत सुधरी है। लेकिन अभी कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होने की जरूरत है। यह कोई छुपी बात नहीं है कि पार्टी के फैसले सोनिया गांधी से ज्यादा राहुल-प्रियंका की जोड़ी ही कर रही है। जिससे कांग्रेस में गुटबाजी और अधिक बढ़ गई है। इस कारण कांग्रेस पहले से और ज्यादा कमजोर होती जा रही है।

● **मोनिका चौहान,** नई दिल्ली

कड़ी कार्यवाही हो...

राजधानी के हमीदिया अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में शार्ट सर्किट से आग लगने से मासूमों की मौत ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार को इस ओर कठोर कदम उठाने होंगे। ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। इस घटना में जवाबदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जाहिर है प्रदेश में इसके पहले भी अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

● **कमल सोनी,** भोपाल (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

हाशिए पर चाणक्य

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का जलवा अब उतार की तरफ जाता नजर आने लगा है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह के मध्य अब रिश्ते पहले जैसे प्रगाढ़ नहीं रह गए हैं। गुजरात में शाह के करीबी विजय रुपाणी को हटा भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी के पीछे भी इसी फैक्टर का हाथ होने की बात उठी थी। दरअसल, गुजरात की राजनीति में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और अब उप्र की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संग अमित शाह की पटरी कभी ठीक से बैठी नहीं। भूपेंद्र पटेल इन्हीं आनंदीबेन के शिष्य हैं, इसलिए रुपाणी को यकायक हटा पटेल की ताजपोशी होने के बाद शाह के रुतबे में आ रही कमी पर नाना प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। अब गपशप का केंद्र गत दिनों शाह की दक्षिण भारत यात्रा है। 'साउदर्न जोनल काउंसिल' केंद्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद् है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं। इस परिषद् का जिम्मा दक्षिण के राज्यों की समस्याओं का निस्तारण करना है। हर वर्ष इस परिषद् की बैठक दक्षिण के किसी एक राज्य में बुलाई जाती है, जहां का मुख्यमंत्री इस बैठक में बतौर उपाध्यक्ष मेजबानी करता है। गत सप्ताह बुलाई गई बैठक में भाजपा शासित कर्नाटक और पुडुचेरी के मुख्यंमत्री तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उपराज्यपाल तो शामिल हुए लेकिन केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री गायब रहे।

वास्तु सहारे राज ठाकरे

महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का भविष्य गर्त में है। शिवसेना प्रमुख स्व. बाल ठाकरे के अत्यंत करीबी राज ठाकरे एक समय में बाल ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी कहलाए जाते थे। शिवसेना भीतर मौजूद 'उज्जड़ सेना' के वे ही हीरो हुआ करते थे। लेकिन बाल ठाकरे ने अपनी विरासत भतीजे राज के बजाय बेटे उद्धव को सौंप डाली। इससे नाराज राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से अलग हो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर डाला था। 2009 में इस पार्टी के 13 विधायक चुने गए। लेकिन 2014 में इसे करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी केवल एक विधानसभा सीट जीत पाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति रही। जानकारों का कहना है कि राज ठाकरे लगातार मिल रही पराजय के पीछे अपने घर के वास्तु को दोषी मानते हैं। पिछले 25 बरसों के दौरान वे तीन बार अपना घर बदल चुके हैं। गत पखवाड़े उन्होंने अपने नए घर में बड़ी धूमधाम से गृह प्रवेश किया। 'शिव तीर्थ' नामक यह घर आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस एक छह मंजिला भवन है। देखना दिलचस्प होगा कि इस 'शिव तीर्थ' में प्रवेश बाद राज ठाकरे के सितारे गर्दिश से बाहर आते हैं या फिर कुछ समय बाद वे एक और नया घर अपने लिए तलाशते हैं। सूत्रों की मानें तो राज ठाकरे की पार्टी अगले वर्ष होने जा रहे वृहद मुंबई नगर पालिका चुनावों में दमदार प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है।

सोरेन की बढ़ती परेशानियां

झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन इन दिनों अपने परिवार में बढ़ रही रार से खासे चिंतित बताए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चौतरफा संकटों से जूझ रहे हैं। राज्य में गठबंधन सरकार अपने गठन के समय से ही लगातार अस्थिरता का सामना कर रही है। 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में जेएमएम के 30, कांग्रेस के 18, आरजेडी का 1, एनसीपी का 1 कम्युनिस्ट पार्टी का 1 तो विपक्षी दलों में भाजपा के 26, आजसू के 2 और 2 ही निर्दलीय विधायक हैं। सरकार के पास कुल 51 विधायकों का समर्थन है, वहीं विपक्ष में 30 विधायक हैं। हेमंत सोरेन की सरकार को सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के 18 विधायकों से बना हुआ है जिनमें से कई पाला बदलने को आतुर बताए जा रहे हैं। इस गठबंधन को बचाए रखने में ही मुख्यमंत्री सोरेन का अधिकांश समय निकलता है। ऐसे में अब नया संकट उनके घर के भीतर से ही निकलकर सामने आ गया है। हेमंत के बड़े भाई स्व. दुर्गादास की पत्नी और पार्टी की विधायक सीता सोरेन बागी होती नजर आ रही हैं। कुछ अर्सा पहले सीता सोरेन ने पार्टी प्रमुख और अपने ससुर शिबू सोरेन से एक अपील कर राज्य का राजनीतिक तापमान गर्मा दिया था।

नाराज ब्यूरोक्रेसी

धामी सरकार के बनते ही राज्य के एक पूर्व नौकरशाह यकायक फिर से देहरादून के सत्ता गलियारों में घूमते नजर आने लगे हैं। रिटायर होने से पहले इनकी हनक और धमक राज्य की हर सरकार में हुआ करती थी। मुख्यमंत्री चाहे जो भी रहा हो, ये हमेशा महत्वपूर्ण पद पर काबिज रहते आए। इन महाशय को विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री काल में खास तव्वजो नहीं मिली थी। लेकिन हरीश रावत सरकार में इनका खासा जलवा रहा। रावत इनकी 'क्षमताओं' से इतने प्रभावित थे कि सेवानिवृत्ति के बाद एक विशेष पद इनके लिए सृजित करने में उन्होंने देर नहीं लगाई थी। यह बात दीगर है कि रावत के बुरे दिनों में सबसे पहले उनका साथ छोड़ने वालों में यही शख्स थे। अब खबर है कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा डाली है। चर्चा गर्म है कि दिल्ली के एक बेहद विवादित बिल्डर ने इन महाशय की शह पर राज्य में सरकारी जमीनों की खरीद-फरोख्त में दलाली करनी शुरू कर डाली है।

गले की हड्डी बने मलिक

सतपाल मलिक इन दिनों गजब कर रहे हैं। वे लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं। उनके हमले खासे तीखे हैं लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा न जाने किस भय के चलते कुछ भी रिएक्ट करने से बच रही है। कई बार के सांसद रहे सतपाल मलिक समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। कभी कांग्रेस और जनता दल के सदस्य रहे मलिक ने 2004 में भाजपा की सदस्यता ले ली थी। पार्टी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 2018 में वे जम्मू-कश्मीर के गवर्नर बनें। उनके ही समय में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 केंद्र सरकार ने समाप्त कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। यहां के राज्यपाल रहते मलिक की भाजपा नेतृत्व से खटपट होने लगी। पहले उन्हें इस महत्वपूर्ण राज्य से हटा गोवा जैसे छोटे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई फिर यकायक ही उन्हें उनके बचे टर्म के लिए मेघालय का गवर्नर बना दिया गया।

नमक का कर्ज

प्रदेश के ताकतवर और रसूखदार शराब व्यवसायी एक बार फिर चर्चा में हैं। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि उक्त व्यवसायी का सालों नमक खाने वाले एक वकील जो अब बड़े ओहदे पर हैं, उन्होंने नमक का कर्ज चुकाया है। गौरतलब है कि इस शराब व्यवसायी की फैक्ट्री में बन रही अमानक शराब के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एक्साइज कमिश्नर ने परिणाम की चिंता किए बिना कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने प्रदेश की सबसे बदनाम डिस्टलरी में अवैधानिक गतिविधियों की सिरे से पड़ताल कराई और नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उस पर ताले लगवा दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साहब की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है और इसके पीछे सरकार के ही एक नुमाइंदे का हाथ है। जानकारी के अनुसार कभी शराब व्यवसायी के काले कारनामों के लिए केस लड़ने वाले एक वकील साहब इन दिनों सरकार में ओहदेदार बन गए हैं। हाईकोर्ट में जब शराब कंपनी का मामला गया तो उक्त कंपनी के व्यवसायी ने अपने पुराने वकील से संपर्क किया और उनसे सहायता मांगी। फिर क्या था, ओहदेदार वकील साहब ने नमक का कर्ज अदा करने के लिए सरकार की तरफ से जोरदार पक्ष नहीं रखा। ऐसे में कंपनी को स्टे मिल गया है।

पूछी न आछी... दुलहिन की चाची

यह प्रसिद्ध लोकोक्ति आपने सुनी ही होगी 'पूछी न आछी, मैं दुलहिन की चाची।' ऐसी ही स्थिति इन दिनों प्रदेश के एक कद्दावर मंत्रीजी की है। मंत्रीजी की सरकार में ढेले भर की नहीं चल रही है, लेकिन वे बड़ी-बड़ी बातें करके अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने नई पुलिस प्रणाली पर भी दावा किया था कि उसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। दरअसल, मंत्रीजी को इस समय न तो आईएएस और न ही आईपीएस भाव दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने शगूफा फेंका कि नई पुलिस प्रणाली को अमली जामा पहनाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं ही इसे बनाने वाले विभाग का मुखिया हूं। मेरे पास कुछ अन्य दमदार विभाग हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी इन दिनों इतनी लंबी-लंबी इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि सरकार में आजकल उनकी बिलकुल भी नहीं सुनी जा रही है। यह बात उन्हें भी मालूम है कि नई पुलिस प्रणाली को लागू करवाने में उनका कोई बस नहीं चलेगा। फिर भी वे श्रेय लेने के लिए शगूफा छोड़ते रहते हैं। कई बार वे सरकार के मुखिया से आगे निकलकर बयान देते हैं, लेकिन अगले दिन स्थिति टांय-टांय फिश वाली हो जाती है।

कलेक्टरी की कलाकारी में साहब मस्त

हर आईएएस अफसर का सपना होता है कि वह कलेक्टर बने और अगर वह जिला बड़ा तथा कमाऊ हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसलिए हर आईएएस अफसर इसके लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रदेश में कुछ बिरले अफसर ही होते हैं जिनकी मुराद पहली बार में ही पूरी हो जाती है। ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी की कलेक्टरी प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, साहब एक आदिवासी जिले के कलेक्टर हैं। पहली बार में ही उन्हें इस जिले की कमान मिल गई है। जिले में विकास के लिए सरकार ने योजनाओं की भरमार लगा दी है। ऐसे में साहब की लॉटरी लग गई है। साहब बिना सोचे-समझे पहली कलेक्टरी में ही कलाकारी दिखाकर माल कमाने में जुट गए हैं। साहब जबसे जिले में पदस्थ हैं, तबसे रोजाना लाखों रुपए वारे-न्यारे कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने पीए को माध्यम बना रखा है। लेकिन उस दिन साहब की कलेक्टरी की कलाकारी की पोल खुल गई, जिस दिन उन्होंने एक व्यक्ति से लाखों रुपए कमीशन के रूप में ले लिए। बताया जाता है कि पीए के माध्यम से साहब ने उक्त व्यक्ति से रुपए तो ले लिए हैं, लेकिन वह बात जिले से निकलकर राजधानी की प्रशासनिक वीथिका तक पहुंच गई है। संभावना जताई जा रही है कि यह बात कानोंकान बड़ों तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर साहब को कोई सपोर्ट नहीं मिला तो उनकी पहली कलेक्टरी आखिरी कलेक्टरी भी हो सकती है।

मंत्रियों में आक्रोश

प्रदेश में एक तरफ सरकार मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रही है। दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उधर, मंत्रियों का कहना है कि अधिकारी हमारी तनिक भी नहीं सुनते हैं। ऐसे में हमारी रिपोर्ट अच्छी कैसे रहेगी। इस संदर्भ में कुछ मंत्रियों का अपना दर्द बयां करते हुए कहना है कि न तो हमारे विभाग के अधिकारी हमारी सुनते हैं और न ही उच्च अधिकारी। एक मंत्री कहते हैं कि अधिकारियों द्वारा की जा रही नाफरमानी की शिकायत हमने कई बार प्रशासनिक मुखिया से की है, लेकिन वे खुद हमारी नहीं सुनते हैं। जब हम सरकार के मुखिया से प्रशासनिक मुखिया की शिकायत करते हैं तो वे भी हमारी नहीं सुनते हैं। ऐसे में न तो हम अपने विभाग का काम करवा पाते हैं और न ही अपने क्षेत्र का। वे कहते हैं कि मंत्रिमंडल में कुछ ही मंत्री ऐसे हैं जो अपने दमखम पर अपनी फाइलों पर मंजूरी पा लेते हैं। बाकी सब तो अफसरशाही के कायदे-कानून में फंसे रहते हैं। ऐसे में हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेहतर कैसे होगी। लेकिन हम करें भी तो क्या, हमारी कोई सुन नहीं रहा है।

मम्मा को मामा ने साधा

मिशन-2023 की तैयारी में जुटे भाजपा और सरकार की कोशिश है कि हर एक को साधा जाए। इसके लिए पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को मनाया जा रहा है। मामा ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। इसी कड़ी में गत दिनों मामा ने अपने संघर्ष के दिनों के साथी मम्मा को मनाने की जिम्मेदारी अपनी धर्मपत्नी को दी। दरअसल, मम्मा इन दिनों असंतुष्ट चल रहे हैं और वे इस बात से दुखी हैं कि उनकी पूछपरख कम हो गई है। सूत्र बताते हैं कि मामा के निर्देश पर उनकी पत्नी जब मम्मा को मनाने उनके घर गई तो मामा ने उनकी बात तो पूरी सुनी, लेकिन उनका आक्रोश कम नहीं हुआ। ऐसे में थक-हारकर मामा ने मम्मा को मनाने का बीड़ा उठाया। बताया जाता है कि विगत दिनों मामा ने अपने संघर्ष के दिनों के मित्र को बुलाया और कृष्ण-सुदामा की जोड़ी की तरह उनकी आवभगत की। उन्होंने मम्मा की समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि वे हमेशा उनके लिए एक पांव पर खड़े रहेंगे। मम्मा और मामा की इस जुगलबंदी से राजधानी में राजनीति की गई कहानी लिखे जाने की संभावना है।

किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया है। अब किसान बंधुओं को आंदोलन खत्म कर घर लौट जाना चाहिए। सरकार एमएसपी पर विचार कर रही है। जल्द ही किसानों के साथ बैठकर इसके लिए रास्ता निकाला जाएगा।

● **नरेंद्र सिंह तोमर**

मेरी कोशिश है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर काम करे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं चाहती हैं, इसलिए अब मैंने टीएमसी के विस्तार की योजना बनाई है। मैं किसी भी पार्टी में तोड़फोड़ नहीं करना चाहती। लेकिन जब लोग खुद मेरी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं तो उन्हें मना भी नहीं किया जा सकता। अब टीएमसी सबकी पसंद बन रही है।

● **ममता बनर्जी**

फिल्म 83 ने एक बार फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। यह मेरी टीम की कहानी है। ट्रेलर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशी धरती पर हमारे प्लेयर्स ने अपनी इज्जत और देश का अभिमान बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की थी। हमारी मेहनत का परिणाम है कि आज भारत की क्रिकेट टीम विश्व में सबसे मजबूत है।

● **कपिल देव**

अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और आगे मथुरा की तैयारी है। विदेशी आताताियों ने हमारे धार्मिक स्थलों का जो क्षरण किया है, उस गौरव को भाजपा सरकार लौटाने में जुटी हुई है। इसके लिए अयोध्या और काशी में निर्माण चल रहे हैं।

● **केशव प्रसाद मौर्य**

हर कलाकार की ब्रांडिंग के पीछे मीडिया का बड़ा हाथ होता है। लेकिन कई बार मीडिया अपनी हदें पार कर जाती है। शायद यह मीडिया के काम का हिस्सा होगा। इसलिए कभी कभार हमें लगता है कि मीडिया गलत कर रहा है। ऐसे में आवेष में आकर हमारे साथी या अंगरक्षक मीडियाकर्मियों से गलत सलूक कर देते हैं। मेरे लोगों ने ही कई बार ऐसा किया है। अगर किसी को मेरे कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। साथ ही अन्य कलाकारों से अपील करती हूं कि वे भी मीडिया के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करें।

● **सारा अली खान**

वाक्युद्ध

सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और किसान भी इससे खुश हैं, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि किसान बॉर्डर से वापस जाएं। इसलिए किसानों को बरगलाया जा रहा है। भाजपा सरकार किसानों की हमदर्द है और किसानों की हर समस्या का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है।

● **संबित पात्रा**

कृषि कानून किसानों के लिए बना था और किसानों ने ही इसका विरोध किया था। बिल में खामियां थीं, इसलिए कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है। कृषि कानून वापस होने पर यह साबित होता है कि बिल में खामियां थीं। अब किसान बॉर्डर पर क्यों बैठे हैं इस बात को सरकार और भाजपा दोनों जानते हैं। फिर दोषारोपण क्यों?

● **सुप्रिया श्रीनेत**

सियासत में सिंधिया घराने की चौथी पीढ़ी!

ग्वालियर राजघराने की चौथी पीढ़ी सियासत में आने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन ने जिस तरह से अपना 26वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं के साथ मनाया, उससे साफ संकेत है कि महाआर्यमन जल्दी ही नेताओं की पारंपरिक ड्रेस (सफेद कुर्ता-पायजामा) में दिखाई देंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पॉलिटिक्स में पहले से ही सक्रिय हैं। इसी तरह भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश भी विधायक बन चुके हैं। जयवर्धन विधायक हैं और पूर्व की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं जबकि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पिछले 3-4 साल में कई मौकों पर राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर आए। फिलहाल वे पढ़ाई पूरी करने अमेरिका गए हैं। अब ज्योतिरादित्य के पुत्र महाआर्यमन के लिए 'पॉलिटिकल कारपेट' तैयार हो रहा है।

खास बात है कि चारों में से तीन के पिता राजनीति की लंबी पारी खेल चुके हैं और अभी भी सक्रिय हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने अपने पुत्र जयवर्धन को राजनीति के अखाड़े में उतारा था। इसके बाद कमलनाथ ने मप्र की राजनीति में सक्रिय होते ही बेटे नकुलनाथ को अपनी संसदीय सीट छिंदवाड़ा की कमान सौंप दी। चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चार साल से बुधनी में सक्रिय हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वे अपने पिता की विरासत को कब संभालेंगे, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य की उम्र 51 साल है। वे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और शिवराज सिंह से उम्र में 10 से 15 साल छोटे हैं। इसी तरह चारों नेताओं के पुत्रों में महाआर्यमन उम्र के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। वे 17 नवंबर को 26 साल के हुए हैं। जबकि नकुलनाथ 47, जयवर्धन सिंह 35 और कार्तिकेय 25 साल के हैं। राजनीति में आने से पहले जयवर्धन से दिग्विजय सिंह ने कहा था- राजनीति में आने से पहले वह राघौगढ़ की जनता के साथ सात दिन गुजारें। यहां एक-एक परिवार से मिलें, उनकी बात सुनें, उन्हें समझें। अगर राघौगढ़ की जनता ने तुम्हें अपना लिया, तो तुम राजनीति कर सकते हो। पिता की शर्त के आगे अमेरिका में शिक्षा प्राप्त बेटा राघौगढ़ की सड़कों पर उतर गया। 2013 में राघौगढ़ के कोलुआ गांव से पदयात्रा निकाली। 6 दिनों तक चली इस पदयात्रा में दिग्विजय भी उनके साथ ही थे। फिर लड़ा विधानसभा चुनाव, विधायक और मंत्री बने।

मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष नेता कमलनाथ के बड़े बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा में राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे, लेकिन पहली बार मई 2018 में भोपाल में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आयोजित हुआ था। इस दौरान नकुलनाथ पिता के साथ-साथ थे। इस दौरान सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चले रोड शो में पूरे वक्त नकुल पिता के पीछे खड़े रहे। यही नहीं, कांग्रेस दफ्तर के सामने हुई कांग्रेस की रैली में भी मंच पर नकुल के लिए बाकायदा सीट रिजर्व की गई थी और नकुल पिता के ठीक पीछे बैठे थे। कार्यक्रम के बाद कमलनाथ की पत्रकार वार्ता में भी नकुल की सीट रिजर्व थी और वो सबसे पहले आकर अपनी सीट पर बैठ गए थे। शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय पिछले चार सालों से राजनीति में कुछ मौकों पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वे पिता के चुनाव में वर्ष 2013 से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने चुनावी सभाएं भी कीं। जनवरी 2018 में शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र में उन्होंने पहली बार बड़ी सभा को संबोधित किया था। तब उन्होंने एक बयान में कहा था- जब मैं कोलारस आ रहा था, तो मैंने अपने पिता से पूछा- मैं पहली बार बुधनी से बाहर जाकर सभा करूंगा तो वहां क्या बोलना है? इस पर पिता ने कहा कि जो सच हो, वह बोलना। इस सभा में कार्तिकेय का भाषण सुनकर भाजपा नेता चौंक गए थे।

विधानसभा उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 25 वर्षीय बेटे महा आर्यमन का एक पोस्टर तेजी से वायरल हुआ था, जिससे कयास लगने शुरू हो गए थे कि सिंधिया की नई पीढ़ी भी राजनीति में एंट्री करने की तैयारी में है। रायसेन के सांची में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहां बड़े-बड़े होर्डिंग लगे थे। इसमें महाआर्यमन के साथ कार्तिकेय का फोटो भी था, लेकिन यह सभा नहीं हुई थी। अब पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच जन्मदिन मनाए जाने के बाद राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ज्योतिरादित्य अपने बेटे की पॉलिटिकल लॉचिंग में ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे।

● **नवीन रघुवंशी**

राजनीति में आ चुके हैं 9 मुख्यमंत्रियों के 11 बेटे

मप्र के सियासी इतिहास के अगर पन्ने पलटें तो पता चलता है कि मप्र में अब तक हुए 19 मुख्यमंत्रियों में से 9 मुख्यमंत्रियों के 11 बच्चे न सिर्फ पिता का हाथ पकड़ राजनीति में आए बल्कि मंत्री भी बने। मप्र में अब तक 27 सरकारें रही हैं, जिसमें 19 मुख्यमंत्री रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं, जो दो या ज्यादा बार मंत्री रहे हैं। मप्र के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के दोनों बेटे विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल राजनीति में आए। श्यामाचरण शुक्ल 3 बार मुख्यमंत्री और विद्याचरण शुक्ल केंद्रीय मंत्री बने। मप्र के छठे मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के 2 बेटे हर्ष सिंह और ध्रुव नारायण राजनीति में आए। हर्ष सिंह शिवराज सरकार में मंत्री और ध्रुवनारायण 1 बार विधायक रहे। मप्र के 10वें मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी शिवराज सरकार में मंत्री रहे। मप्र के 11वें मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा के बेटे ओमप्रकाश सखलेचा 4 बार विधायक रहे। मौजूदा शिवराज सरकार में मंत्री हैं। दो बार मप्र में मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके। अब विधायक हैं। 3 बार मप्र के मुख्यमंत्री बने अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह 6 बार विधायक बने। मप्र के नेता प्रतिपक्ष रहे। दो बार मप्र के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा विधायक रहे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को विरासत में सियासत मिली। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं।

चुनौती के लिए भरपूर तैयारी

मप्र में भाजपा के साथ कांग्रेस भी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए दोनों पार्टियां तू डाल-डाल, मैं पात-पात की तर्ज पर सक्रिय हैं। हालांकि सांगठनिक तौर पर भाजपा कांग्रेस से काफी मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी सक्रिय हैं। लेकिन संगठन मजबूत नहीं होने के कारण उनकी सक्रियता प्रभावहीन साबित हो रही है। इसलिए अब पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में जल्द ही कांग्रेस संगठन विस्तार करेगी।

उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कमलनाथ ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में गत दिनों कमलनाथ ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ ने सोनिया गांधी को प्रदेश का फीडबैक दिया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कमलनाथ को प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने और संगठन का विस्तार करने के लिए फ्री हैंड कर दिया है। अब संभावना जताई जा रही है कि मप्र कांग्रेस का विस्तार दिसंबर में किया जा सकता है। गौरतलब है कि उपचुनावों के बाद से ही कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पदाधिकारियों के साथ निरंतर मंथन कर रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष की प्राथमिकता संगठन को मजबूत करने की है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि कमलनाथ जल्द ही संगठन विस्तार कर सकते हैं।

मप्र कांग्रेस संगठन में विस्तार के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कमलनाथ ने प्रदेश संगठन का खाका भी उनके सामने प्रस्तुत किया। अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। बता दें कि बीते समय से कांग्रेस के संगठन को लेकर चर्चाएं चल रहीं हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ कह चुके हैं कि वह दोनों में से एक पद छोड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है।

प्रदेश संगठन में होने जा रही नियुक्तियों में जहां युवा और सक्रिय नेताओं को मुख्य भूमिका में रखा जाएगा, वहीं पार्टी के कई नाराज नेताओं-कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा। ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक हजारों कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं को पद और सम्मान दिया जाएगा, ताकि दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को सक्रिय किया जा सके। प्रदेश में वर्ष 2023 में

2018 की रणनीति पर कांग्रेस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी संगठित होकर भाजपा की खामियों को जनता के बीच ले जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं। वे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं कर भाजपा सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की सक्रियता का असर दिखने लगा है और पार्टी के नेता भी मैदानी मोर्चे पर सक्रिय हो रहे हैं। कांग्रेस के मोर्चा संगठन भी आंदोलन के सहारे सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि प्रदेश के युवाओं का कांग्रेस की ओर रुझान बढ़ा है। इससे प्रदेश की राजनीति बदलती दिख रही है।

कमलनाथ के लिए गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती

आज से करीब 23 साल पहले जिस तरह सुभाष यादव ने नर्मदा नदी के किनारे खलघाट पर लाखों किसानों को एकत्रित कर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपनी ताकत का अहसास कराया था, उसी तर्ज पर अब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और उनके भाई व पूर्व मंत्री सचिन यादव कांग्रेस को अपनी ताकत का अहसास कराएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगातार उपेक्षित किए जाने के बाद अब अरुण यादव कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पार्टी को उनकी राजनीतिक ताकत का अहसास हो सके। खंडवा लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर उपचुनाव में अपनी दावेदारी को वापस लेने वाले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव अब कांग्रेस के झंडे और बैनर के बिना अपनी ताकत का अहसास करवाने पार्टी के नेताओं को संदेश देने की तैयारी में हैं। इसमें उनके भाई सचिन यादव भी साथ दे रहे हैं। दोनों भाईयों के समर्थकों ने इस आयोजन के लिए खलघाट को ही चुना है और अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

महिलाएं संभालेंगी मैदानी मोर्चा

प्रदेश में महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर महिला कांग्रेस निरंतर आंदोलन करेगी। गत दिनों पीसीसी में महिला कांग्रेस की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जयसवाल ने मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर कमलनाथ ने यह भी कहा कि महिला कांग्रेस को लक्ष्य साफ रखना होगा। मैं साफ बोलना चाहता हूं कि महिलाएं सजावट के लिए नहीं है। महिला कांग्रेस सिर्फ सजावट का संगठन नहीं है। महिला कांग्रेस को गांवों में फोकस करना होगा। महिलाएं किस गांव में कांग्रेस को मजबूत कर सकती है, उसकी लिस्ट बनाए। सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए। विधानसभा चुनावों में एक साल 10 महीने बचे हैं। ऐसे में पूरी तरह से चुनाव में लगना होगा। हम जहां चुनाव हारे, वहां उनके कारणों का पोस्टमार्टम करना होगा।

होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। संगठन में कसावट लाने के लिए सहयोगी संगठनों की समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रदेश से लेकर ब्लाक स्तर तक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 14 नवंबर को बाल कांग्रेस का गठन भी किया गया है। इसमें 16 से 20 साल के विद्यार्थियों को सदस्य बनाया जाएगा।

कांग्रेस आलाकमान ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को महंगाई और पेट्रोलियम की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरने-प्रदर्शन का टास्क दिया है। तीन कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस किसान आंदोलन में किसानों की मौत और अब तक हुए नुकसान का मुद्दा भी उठा रही है। इसे केंद्र सरकार की बड़ी विफलता के तौर पर जनता में भुनाने की प्लानिंग है। केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल से ज्यादा के कार्यकाल की विफलता जनता के बीच ले जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए राज्य में बड़े लेवल पर आंदोलन और धरने-प्रदर्शन के कार्यक्रमों का रोडमैप भी तैयार किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर दोहराया है कि वे मप्र नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति, एक पद की व्यवस्था के तहत पार्टी अध्यक्ष जो भी फैसला करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वे नेता प्रतिपक्ष पद के लिए किसी अन्य नेता का चयन करने के लिए आपसी सहमति बनाने की बात पहले ही कह चुके हैं।

मिशन 2023 में कांग्रेस ने हर बार की तरह युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस करने का प्लान बनाया है। आने वाले चुनावों में भी पार्टी युवाओं और महिलाओं को ही आगे रखेगी। प्रदेश में खासतौर से महिला सम्मान और महिलाओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस का फोकस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उप्र में प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस इस बार 40 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इसके अलावा बेटियों को स्कूटी देने का भी कांग्रेस ने वादा किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मप्र में भी इस घोषणा को लागू कर सकती है। इसलिए अभी से इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है।

मिशन 2023 के तहत पार्टी के नेता मैदानी इलाकों में घूम-घूमकर केंद्र और राज्य सरकार की विफलता को गिनाएंगे। भाजपा को घेरने के लिए भी पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। इसके मुताबिक, भाजपा के नेताओं के विवादित बयान को पार्टी चुनावी मुद्दा बनाएगी। चुनाव के दौरान नेताओं के बयानों का बड़ा असर पड़ता है। एक विवादित बयान पूरे चुनाव को पलट सकता है। यही कारण है कि पार्टी ने संगठन में ऐसे युवाओं और बुद्धिजीवी वर्ग की टीम बनाने को कहा है जो भाजपा के हर नेता का बयान बारीकी से समझेगा और अगर उसका कोई मुद्दा बनने लायक होगा तो उसे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उठाया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी अभियान के तहत इसका प्रचार-प्रचार होगा।

बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने और अपने वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए इस बार कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने बताया कि सभी जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों को बता दिया गया है कि केंद्रीय संगठन की अपेक्षा है कि दो माह के भीतर मतदान केंद्र स्तर पर पांच-पांच कार्यकर्ताओं की तैनाती हो जाए। इनके मोबाइल नंबर लेकर वाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे ताकि प्रदेश स्तर से दिए जाने वाले दिशा-निर्देश एक साथ सबको मिल जाएं। इन कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र के प्रबंधन का प्रशिक्षण केंद्रीय संगठन द्वारा विशेषज्ञों से दिलाया जाएगा।

प्रदेश के 65 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर तीन लाख से ज्यादा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। यह कार्य दो माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन सभी कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र के प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। प्रदेश के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 65 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कांग्रेस का ध्यान अब सर्वाधिक मतदान केंद्रों के प्रबंधन पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के सभी सहयोगी संगठन के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदान केंद्र इकाई को मजबूत करें। सभी अपनी-अपनी टीम बनाएं और उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण भी दें क्योंकि हमारा मुकाबला भाजपा के नेताओं से नहीं बल्कि उनके संगठन से है। दरअसल, भाजपा चुनाव के लिए सर्वाधिक ध्यान मतदान केंद्र के प्रबंधन पर ही देती है। इसके मद्देनजर युवा कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रत्येक मतदान केंद्र पर पांच कार्यकर्ताओं की तैनाती करे। इन्हें मतदाताओं से संपर्क अभियान चलाने के साथ पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम दिया जाएगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

मप्र की राजनीति में जगह तलाश रहे पटेल

दिल्ली की गुलाबी ठंड के बीच गत दिनों जनपथ स्थित एक कोठी में हुई दावत मप्र के राजनीतिक पंडितों का ध्यान खींच रही है। चुनिंदा लोगों की इस पार्टी में मूंग दाल के हलवे से लेकर जलेबी तक परोसी गई, लेकिन चर्चा मप्र के नरसिंहपुर जिले के गुड़ की ही रही। केंद्रीय राज्यमंत्री और मप्र के वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया में दखल रखने वाले मप्र से जुड़े लोगों को अपने घर दिवाली मिलन पर बुलाया था। प्रहलाद की पार्टी के मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं वे दिल्ली छोड़कर मप्र के पटेल तो नहीं बनने जा रहे। क्योंकि राजधानी भोपाल में लंबे समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विदाई और किसी नए चेहरे की मुख्यमंत्री के रूप में आमद की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं।

पार्टी में शामिल हुए लोगों को बतौर उपहार मप्र के नरसिंहपुर जिले का गुड़ भी भेंट किया गया। उपहार के पैकेट पर केंद्रीय मंत्री के भाई और प्रदेश से विधायक जालम सिंह पटेल का नाम लिखा था। प्रहलाद पटेल भाजपा के लिए लंबे समय तक संगठन का काम कर चुके हैं। मप्र के कद्दावर नेता पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ भाजपा छोड़ी थी। बाद में वापसी हुई तो अब दिल्ली में मोदी-शाह के करीबी माने जाते हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कयास तेज हैं कि मप्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में पटेल की दावेदारी भी खासी मजबूत है। हाईकमान उन पर भरोसा भी जता सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और पटेल भी ओबीसी से हैं। ऐसे में शिवराज सिंह को हटाकर पटेल को बैठाने से वह वर्ग भी नाराज नहीं होगा। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को दिवाली मिलन की इस दावत ने खासा बल दे दिया है। बात इसलिए भी दूर तक जा रही है क्योंकि आमतौर पर पटेल अब तक ऐसी दावतों से दूर रहते ही नजर आते थे।

मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले भाजपा के दो नेताओं का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए सबसे आगे बताया था। सिंह ने जुलाई में ट्वीट कर कहा था अब मप्र भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए केवल दो ही उम्मीदवार दौड़ में रह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवार हैं प्रहलाद पटेल और संघ के उम्मीदवार हैं वीडी शर्मा। बाकी उम्मीदवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मामू का जाना तय।

उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात के बाद मप्र में कांग्रेस लगातार शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल उठा रही है और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है। पेगासस लिस्ट में विपक्ष के नेताओं के साथ मोदी कैबिनेट के दो मंत्रियों के नाम भी सामने आए थे। उनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल शामिल थे। लिस्ट में नाम आने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री पटेल ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा था, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरी जासूसी की जाए।

केंद्रीय राज्यमंत्री पटेल का राजनीतिक कैरियर छात्र नेता के तौर पर शुरू हुआ था। उन्होंने मप्र के जबलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसके बाद उन्होंने राजनीति में पलटकर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते गए। पटेल उन गिने-चुने राजनेताओं में से हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है। पटेल चार बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार वे 1989 में सांसद बने थे। इसके बाद 1996, 1999, 2014 और 2019 में भी सांसद बने। पटेल वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में भी मंत्री रहे हैं। साल 2003 उमा भारती की अगुवाई में दिग्विजय सिंह की एक दशक पुरानी कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था, तो पटेल को राज्य स्तर पर पहचाना मिली। अपनी तेज-तर्रार छवि के चलते ही वह अटल बिहारी वाजपेयी के पसंदीदा नेताओं में शुमार होने लगे और बाद में उन्हें वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री बना दिया गया। यहां से वह राज्य से निकलकर केंद्र की तरफ बढ़ चले।

● **जितेंद्र तिवारी**

कभी मप्र की राजनीति में सबसे चमकदार चेहरा रहे प्रहलाद पटेल भले ही केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन एक तरह से हाशिए पर हैं। इसलिए पटेल एक बार फिर से मप्र में अपनी जगह तलाश रहे हैं।

प्रहलाद पटेल का केंद्रीय मंत्रिमंडल में घटा कद

जुलाई में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में प्रहलाद पटेल का कद कम कर दिया गया। पटेल से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार छीनकर उन्हें जलशक्ति व खाद्य प्रसंस्करण का राज्यमंत्री बनाया गया है। पटेल का मंत्रालय बदलने और उनके अधिकार सीमित किए जाना उनकी कार्यशैली और दमोह उपचुनाव में मिली भाजपा की करारी हार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रहलाद पटेल को शिवराज विरोधी खेमे का नेता भी माना जाता है। साल 2005 में जब उमा भारती पर दंगों के आरोप लगे तो पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद उमा भारती ने साल 2005 में अपना राजनीतिक दल भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाया। पटेल ने बगावती तेवर दिखाते हुए उमा भारती का साथ दिया। उनके इस कदम के बाद से वह शिवराज विरोधी माने जाने लगे। कुछ ही समय के बाद पटेल ने पार्टी छोड़ दी और 2009 में फिर से भाजपा में लौट आए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दमोह लोकसभा सीट से चुनाव जीता और 2019 में भी अपनी सीट बरकरार रखी।

मप्र की राजनीति में दबंगई

स्वस्थ राजनीति का केंद्र माने जाने वाले मप्र की राजनीति में भी क्या अब बंगाल और बिहार की 'दबंगई' वाली राजनीति आ गई है? यह सवाल मप्र के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में गूंज रहा है। दरअसल, हुआ यह कि मप्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा का वीडियो गत दिनों वायरल हुआ था। वीडियो में भोपाल के हुजूर क्षेत्र से विधायक शर्मा को एक कार्यक्रम में कांग्रेस और उसके बड़े नेता दिग्विजय सिंह को जमकर कोसते नजर आते हैं। वीडियो में शर्मा अपने समर्थकों को एक जगह सलाह देते हैं, 'भ्रष्ट कांग्रेसियों को बर्दाश्त मत करो, क्षेत्र में घुसें तो इनके घुटने तोड़ डालो।' इस वीडियो पर बवाल मच गया क्योंकि उन्होंने हिंसा की बात की। मप्र में इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि यहां राजनीति में ऐसी 'हिंसा' और 'दबंगई' की बात तो पहले नहीं होती थी।

शर्मा के वीडियो के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वीडियो वायरल होते ही पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने उनके सरकारी घर के समक्ष रामधुन गाने पहुंचने का ऐलान किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था, 'शर्मा के घर पहुंचेंगे। वे और उनके समर्थक उनका घुटना तोड़कर दिखाएं? शर्मा के हिंसात्मक व्यवहार का जवाब अहिंसा से देंगे।'

इसके बाद दिग्विजय सिंह पुरानी विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल मार्च करते हुए रामेश्वर शर्मा के निवास पर पहुंचे। अपनी ब्रिगेड के साथ रामधुन गाई। उधर वायरल हुए वीडियो पर पार्टी से फटकार पड़ने की चर्चाओं के बीच शर्मा ने यू-टर्न मारते हुए दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली का अपने घर पर स्वागत के लिए तैयारी की। दिग्जिवय सिंह की रामधुन के पहले राम दरबार सजाकर खुद रामधुन गाई। रामेश्वर शर्मा के यू-टर्न पर दिग्विजय सिंह ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट कर चुटकियां लीं। अपने एक ट्वीट में सिंह ने कहा, 'हिंसा पर अहिंसा की जीत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घुटने तोड़ने वाले भाजपा विधायक ने कांग्रेसियों के सामने घुटने टेके!! कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए हलुआ-पुड़ी का निमंत्रण। धन्यवाद। गांधी की आवाज सुनो।' सिंह ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, 'हे भाजपाईयों, है संघियों हमारे साथ बैठ कर रामधुन गाओ। और भारतीय संविधान का पालन कर सभी धर्मों का सम्मान करो। गांधी की आवाज सुनो।' ये मामला तो शांति से निपट गया, लेकिन बता दें यह पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी भाजपा खेमे से विवाद खड़े करने वाले अनेक बयान और उदाहरण सामने आए हैं। जो इशारा करते हैं कि मप्र की शिवराज सरकार एवं प्रदेश भाजपा अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए बंगाल और बिहार की राजनीति की 'राह' पकड़ रहे हैं।

रामेश्वर शर्मा की तरह अन्य विवादास्पद बयान रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा का नेतृत्व करने वाले भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी की ओर से सामने आया था। गत दिनों अपने क्षेत्र के एक कार्यक्रम में उन्होंने विरोधियों को धमकाते हुए सार्वजनिक मंच से कहा था, 'बदनाम करने वाले को सेमरिया के लोग जमीन में गाड़ देंगे। बदनाम करने वाला चाहे जहां से चुनाव लड़े जीत नहीं पाएगा।' त्रिपाठी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, 'हम ऐसी योजना बना रहे हैं, जिससे कांग्रेसियों के गुर्दे, किडनी और लीवर सब खत्म हो जाएंगे।' केपी त्रिपाठी के इस बयान को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने विरोध जताते हुए त्रिपाठी से खेद जताने और बयान वापस लेने की मांग रखी है।

● राकेश ग्रोवर

बदले की राजनीति

भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले भोपाल के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के चूना भट्टी इलाके के शोरूम में अतिक्रमण बताकर बड़ी तोड़फोड़ की गई थी। पूरे कागज होने के बावजूद एक न सुनने का आरोप लगाते हुए डागा ने इसे बदले की कार्रवाई बताया था। तोड़फोड़ की भनक लगने पर दिग्विजय सिंह भी डागा के व्यावसायिक स्थल पर पहुंचे थे। विरोध दर्ज कराया था। कोर्ट जाने की सलाह दी थी। डागा कोर्ट गए थे, उन्हें राहत मिली थी। भोपाल में ही कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के काफी पुराने कॉलेज में अतिक्रमण के नाम पर स्थानीय प्रशासन और नगर निगम द्वारा पिछले दिनों की गई भारी तोड़फोड़ को भी 'बंगाल-बिहार की राजनीति' का उदाहरण करार दिया गया था। मसूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लेकर बेहद मुखर थे। उनकी मुख्यमंत्री के खिलाफ तीखी-बयानबाजी के दौर के बीच तोड़फोड़ के तमाम निहितार्थ निकाले गए।

पंचायत चुनाव की तैयारी

अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले महीन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, वहीं उसने कलेक्टरों से परिसीमन की रिपोर्ट मांगी है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता हैं। गौरतलब है कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस करके पुरानी स्थिति के हिसाब से तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जिलों से दो दिन में पूर्व की स्थिति और 2019-20 में किए गए परिसीमन का मिलान करके जिन क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन हुआ है, उसकी जानकारी तीन दिन में भेजने के लिए कहा है। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अध्यादेश के प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब पुरानी व्यवस्था रहेगी। आरक्षण की व्यवस्था भी पूर्ववत बनी रहेगी। ऐसी ग्राम, जनपद या जिला पंचायत क्षेत्रों पर इस अध्यादेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो संबंधित पंचायत के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। जिला स्तर पर विकासखंड को इकाई मानते हुए जानकारी तैयार करें।

राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। इसके लिए सरकार ने मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना गत दिनों जारी कर दी गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द ही किए जाने के आसार हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2019 के बाद हुए परिसीमन को मद्देनजर रखते हुए पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कराई गई थी। नई व्यवस्था के हिसाब से अब फिर मतदाता सूची को सुधारना पड़ेगा। इसमें पुरानी व्यवस्था के हिसाब से मतदाताओं के नाम और मतदान केंद्रों का निर्धारण होगा। आयोग को अपने सॉफ्टवेयर में भी दर्ज जानकारियों में संशोधन कराना होगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स से राज्य शासन द्वारा जारी नए अध्यादेश के संबंध में चर्चा की। सिंह ने कहा कि अध्यादेश के अनुसार पूर्ववर्ती परिसीमन निरस्त हो जाने से ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/ जिला पंचायत क्षेत्र का निर्वाचन उस परिसीमन एवं विभाजन के आधार पर किया जाना है, जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे। ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/ जिला पंचायत क्षेत्र उसी वर्ग के लिए आरक्षित बने रहेंगे, जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे। यानी आगामी पंचायत चुनाव में वर्ष 2014 के पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। अध्यादेश ऐसी ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/ जिला पंचायत क्षेत्र पर नहीं होगा, जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गए हैं।

मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 एकी अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा-कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा सरकार ने कांग्रेस का परिसीमन रद्द किया है। भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि अध्यादेश के अनुसार शीघ्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कार्रवाई करें।

उधर, कानूनी दांवपेंच की परवाह किए बिना भाजपा पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसकी देखादेखी कांग्रेस भी चुनावी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग लगातार चुनावी प्रक्रिया में लगा हुआ है। आयोग ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे चुनावी तैयारी को अंतिम रूप दें। वहीं जिलों में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग लगातार फीडबैक ले रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

जयस बिगाड़ेगा भाजपा-कांग्रेस का खेल

मप्र की सियासत में भाजपा और कांग्रेस की नजर भले ही आदिवासी वोटर्स पर हों लेकिन सियासी दलों की कवायद के पलट आदिवासी संगठन जयस ने अपनी ताकत को और मजबूत कर लिया है। जयस ने मालवा निमाड़ के साथ पूरे प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाकों में अपने संगठन का विस्तार कर लिया है। उसने युवाओं को संगठन से जोड़ने में भाजपा और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। आदिवासी संगठन जयस के साथ जुड़े युवाओं की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में पांच लाख तो देश में करीब 20 लाख युवा जयस के सदस्य बन चुके हैं। यही कारण है जयस ने नीमच में आदिवासी युवक के साथ घटना के विरोध में अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो सियासी दलों की नींद उड़ गई। जयस के अध्यक्ष डॉ. हीरालाल अलावा का कहना है कि संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। अब पूरे प्रदेश में आदिवासी युवा, हमारे इस संगठन से जुड़ रहा है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि दूसरी जाति के लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में जयस की बढ़ती पैठ से भाजपा और कांग्रेस दोनों के अंदर हलचल तेज है। हालांकि कांग्रेस जयस की बढ़ती ताकत से इसलिए खुश है क्योंकि जयस के अध्यक्ष हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं और पार्टी को पूरा भरोसा है कि 2023 के चुनाव में जयस उसके साथ होगी और उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी।

खाद के साथ बिजली की परेशानी

प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई के बाद से ही किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, वहीं सिंचाई के लिए भी बेहाल हो रहे हैं। दरअसल, सरकार के लाख दावों के बाद भी किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली संकट के बीच सरकार का निर्देश है कि किसानों को कम से कम 10 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन शहडोल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सहित कई जिलों में स्थिति यह है कि गांवों में 6-8 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है।

प्रदेश सरकार इस बार भी रबी फसलों के रिकार्ड उत्पादन का अनुमान लगा रही है, वहीं किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिजली कटौती के बीच खेतों की सिंचाई वो करें तो कैसे करें। दरअसल रबी सीजन की खेती के लिए इन दिनों खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है और खेतों में पानी लाने के लिए बिजली चाहिए, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। बहुत कम समय के लिए बिजली दिन में मिल रही है और फिर उसके बाद जब बिजली दी भी जा रही है तो वह वो तड़के सुबह बिजली दी जा रही है तो किसानों का कहना है कि इस कड़कड़ाती ठंड में वह खेतों की सिंचाई करें कि अपनी जान बचाएं, कुल मिलाकर किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादातर किसानों की खेती में अब देरी हो रही है क्योंकि अब फसलों की बुवाई का समय आ चुका है और ज्यादा देरी किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है।

शहडोल के किसानों का कहना था कि बिजली की समस्या को लेकर वह बहुत परेशान हैं, क्योंकि थ्री फेस बिजली बहुत कम समय के लिए दी जा रही है और जो बिजली कुछ फेस में दी भी जा रही है तो वोल्टेज कम रहता है जिससे उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं दी गई तो वह खेतों की सिंचाई नहीं कर पाएंगे। अभी जितनी बिजली मिल रही है उसमें तीन-तीन दिन में 1 एकड़ भी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक बार सिंचाई का क्रम टूट जाता है तो फिर शुरुआत से सिंचाई करनी पड़ती है। इसलिए किसानों की मांग है कि पर्याप्त समय तक बिजली दी जाए जिससे वह खेतों की सिंचाई आराम से कर सकें।

बिजली की सप्लाई को लेकर सिंहपुर सब स्टेशन के जूनियर इंजीनियर डीएस धुर्वे कहते हैं कि सरकार के नियम के आधार पर हम अभी सिंगल फेसिंग पर काम कर रहे हैं, जिसमें 11 केवी फीडर जो सब स्टेशन से निकलते हैं उसमें जो मिक्स फीडर है उसमें हम शाम को 4 बजे से रात को 2 बजे तक 2 फेस चालू रखते हैं मतलब 1 फेस बंद कर देते हैं। फिर तड़के सुबह 4 से 6 बजे तक फिर से 3 फेस चालू कर देते हैं, फिर सुबह 6 से 10 बजे तक फिर 2 फेस चालू रखते हैं, फिर दिन में 10 से 4 बजे तक थ्री फेज सप्लाई करते हैं। ऐसा ही एग्रीकल्चर फीडर के साथ भी है। पंप की सिंचाई के लिए उसे हम दो स्लॉट में बांटे हुए हैं। एक तारीख से 15 तारीख के बीच में जो एजी फीडर चालू होगा सुबह 6.30 बजे से 12.30 बजे तक और शाम को 7.30 बजे से 11.30 बजे तक और 16 तारीख से 30 या 31 तारीख तक दोपहर 12.30 बजे से शाम को 6.30 बजे तक और रात में 11.30 बजे से 3.30 बजे तक चालू रहेगा।

अभी तक किसान खाद के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, अब बिजली के लिए किया जा रहा है। छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर रोड पर अमरवाड़ा-नरसिंहपुर एनएच 547 को किसानों ने जाम कर दिया। किसान बिजली की कटौती से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन की ओर से लंबे समय से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें गेहूं की फसल में पानी की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। किसानों ने कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि, बाद में प्रशासन के समझाने पर जाम हटाया गया।

● **अरविंद नारद**

फसलों का होगा नुकसान

किसानों ने बताया कि अगर सिंचाई में देरी होगी तो फसलों को लगाने में देरी हो जाएगी क्योंकि जब तक खेत में पानी नहीं पहुंचाएंगे तब तक फसल की बुवाई नहीं कर पाएंगे। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि अगर कुछ किसानों ने बुवाई कर भी ली है तो उनके फसलों को भी अब पानी की जरूरत है, अगर पानी नहीं देंगे तो उनके फसलों का नुकसान होगा। छिंदवाड़ा में भी किसानों ने खेतों में गेहूं की बोवनी कर दी है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं रात में बिजली सप्लाई न होने की वजह से ठंड के मौसम में किसान रतजगा करने को मजबूर हैं। कड़कड़ाती ठंड में जहां लोग घर से निकलने में भी परहेज करते हैं। वहीं इन दिनों छिंदवाड़ा के हर गांव के खेतों में कहीं किसान रात भर ठंडे पानी में सिंचाई करते हुए मिलेगा तो कहीं बिजली के इंतजार में रात भर जागता मिलेगा। दरअसल, रबी की फसल सिंचाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन बिजली का शेड्यूल ऐसा है कि किसान को दिन हो या रात सिंचाई के लिए खेतों में डटे रहना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उन्हें बिजली पर्याप्त नहीं मिलती है। कभी बिजली आती है तो फिर वोल्टेज की समस्या होती है, लेकिन बिजली कर्मचारी महीने में बिल वसूलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर कभी चूक हो जाए तो बिजली काटने से लेकर मोटर पंप तक कुर्क करने की धमकी तक देते हैं।

मप्र के जंगलों में बाघ सहित अन्य प्राणियों की लगातार हो रही मौत के बाद सरकार वन क्षेत्र के साथ ही वन्यप्राणियों की सुरक्षा और मजबूत करेगी। इसके लिए इस साल के अंत तक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इस साल अभी तक 38 बाघों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी मप्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी किया है।

टाइगर फिर भी जिंदा है

देश में पांचवीं बाघ गणना शुरू हो गई है। इस बीच मप्र की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक के साथ होने वाली प्रतिस्पर्धा में मप्र में बाघों की मौत के मामलों ने यह चुनौती और भी बढ़ा दी है। देश में एक जनवरी से 19 नवंबर 2021 तक 114 बाघों की मौत हो चुकी है। इसमें से अकेले मप्र में 36 प्रतिशत (38) बाघों की हुई है। यह पिछले पांच सालों में बाघों की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह स्थिति तब है, जब कर्नाटक की तुलना में मप्र में वर्ष 2018 की गणना में सिर्फ दो बाघ ज्यादा निकले हैं। कर्नाटक में 524 और मप्र में 526 बाघ गिने गए थे। वहीं, बाघों की मौत के मामले में देश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वहां इस अवधि में 21 तो कर्नाटक में 15 बाघों की मौत हुई है। इसको देखते हुए मप्र सरकार वन्यप्राणियों की सुरक्षा और मजबूत करने जा रही है।

केंद्र सरकार के निर्देश के 12 साल बाद वन विभाग स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने जा रहा है। ये फोर्स पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच नेशनल पार्क में तैनात की जाएगी। हर पार्क में 112 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही सुरक्षाकर्मियों की भर्ती सहित अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि बाघों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को वर्ष 2010 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही केंद्र ने 100 प्रतिशत बजट भी देने के लिए कहा था। सरकार ने कई सालों तक इसका गठन नहीं किया। बाद में इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा तो केंद्र ने कहा कि वो सिर्फ 60 फीसदी राशि देगा।

प्रदेश में लगातार बाघों की मौत पर मप्र हाईकोर्ट ने गंभीरता जताई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने राज्य व केंद्र सरकार से पूछा कि पिछले एक साल में प्रदेश में 36 बाघों की मौत कैसे हो गई? कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग तथा नेशनल टाइगर कन्सर्वेटर अथॉरिटी के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किए। 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया।

1000 करोड़ स्वाहा फिर भी जा रही बाघ की जान

1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्चने के बाद भी मप्र का वन अमला सजग नहीं हुआ है। इसका परिणाम है कि प्रदेश के जंगलों में बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों का लगातार शिकार हो रहा है। जानकारों का कहना है कि मप्र के जंगलों में आज भी खूंखार तस्करों का राज है, जो आदिवासियों को थोड़े से पैसे का लालच देकर बाघ या अन्य वन्य प्राणियों का शिकार करवाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दखल के बाद वन विभाग और खुफिया विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रदेश के 10 नेशनल पार्क तथा 25 अभयारण्यों के आसपास स्थित ऐसे फार्म हाउस और रिसोर्ट तस्करों का अड्डा बने हुए हैं। वन विभाग-नेशनल पार्क के अफसरों, सफदपोश लोगों, स्थानीय प्रशासन और तस्करों के गठजोड़ से मप्र में हर साल वन्य जीव तस्करी का अवैध कारोबार करीब 7500 करोड़ रुपए से अधिक का है। मप्र में इस साल अब तक 38 बाघों की मौत हो चुकी है।

टाइगर स्टेट का तमगा बचाने और बाघ गणना 2022 में प्रतिद्वंदी राज्यों को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे मप्र की धरातल पर स्थिति खराब है। यहां बाघों की मौत रुक नहीं रही है। यहां नवंबर माह के 23 दिनों में 6 बाघों की मौत हो चुकी है। अगस्त माह में पांच बाघों की मौत हुई है। मई माह तो बाघों के लिए सबसे बुरा समय साबित हुआ है। इस माह सबसे ज्यादा सात बाघों की मौत दर्ज हुई है। इससे टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखने की संभावनाओं पर धुंध छा गई है। इसके बाद भी वन विभाग से एक ही जबाव मिलता है कि मौत का आंकड़ा सामान्य है। ज्यादा बाघ हैं। इसलिए ज्यादा मौत भी हो रही है।

मप्र को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब प्रदेश को इस औहदे के साथ ही एक और औहदा मिल गया है। दरअसल प्रदेश, देश में नंबर एक स्थान पर है जहां इस साल अब तक सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। यानी टाइगर स्टेट के तमगे के साथ ही यहां सबसे ज्यादा बाघों की मौत का तमगा भी मप्र के सिर आ गया है। राज्य में नवंबर 2021 तक 38 बाघों की जान जा चुकी है। इनमें से कुछ का शिकार किया गया तो कुछ अपनी मौत ही मर गए। इन मौतों में से सबसे ज्यादा 20 मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई हैं। हाल ही में रातापानी सेंचुरी में भी दो बाघों के शव मिले थे। तेजी से मर रहे बाघों

की मौत के मामले में अब पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को मानते हैं, जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है।

वनाधिकारियों का कहना है कि बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से उनमें टेरिटोरियल फाइट होती है। इसमें कमजोर बाघ घायल होकर या तो इलाका छोड़ देता है या मर जाता है। यह प्राकृतिक है। टेरिटोरियल फाइट रोकने के लिए सेंचुरी बनाकर नए इलाके की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में फरवरी 2009 में बाघ विहीन हो गया था। यहां बाघों के कुनबे को बढ़ाने के लिए दो अलग-अलग टाइगर रिजर्व से बाघ-बाघिनों को शिफ्ट किया गया। इसके करीब ढाई साल बाद जंगल में अप्रैल 2012 में एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। इसके बाद यहां बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता गया। वर्तमान में पन्ना में 31 बाघ हैं।

मप्र में बाघों की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पिछले 6 साल में 177 बाघ मरे हैं। गौरतलब है कि मप्र का पन्ना टाइगर रिजर्व 2009 में बाघ विहीन हो गया था। यहां बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए दो अलग-अलग टाइगर रिजर्व से बाघ-बाघिनों को शिफ्ट किया गया था। आज मप्र में करीब 600 बाघ हो गए हैं। लेकिन उनकी मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वनाधिकारियों का कहना है कि ये सही है कि राज्य में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एनटीसीए की ओर से वर्ष 2012 से 2019 के बीच देशभर में मरने वाले बाघों पर जारी रिपोर्ट में मप्र शीर्ष पर है। यदि इनमें इस साल यानी 2020 में 26 बाघों की मौत को भी जोड़ दिया जाए तो प्रदेश में मरने वाले बाघों की संख्या 198 हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बाघों की मौत जनवरी, मार्च और दिसंबर माह में होती है। मई में भी मौत का आंकड़ा इसी के आसपास रहता है।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फारेस्ट में पिछले 8 महीने में 11 बाघों की मौत हो चुकी है। तीन

तेंदुए और दो हाथी भी मारे जा चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस वर्ष केवल 3 बार में सात बाघों की मौत हुई, इसमें 6 शावक शामिल थे। दो बार एक साथ दो-दो शावकों की मौत हुई, जबकि तीसरी बार में दो शावक और उनकी मां सोलो बाघिन-42 मौत का शिकार बने। बाघिन के दो शावक अभी भी लापता है। यह घटनाएं 14 जून, 10 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को हुई। 5 बाघों का शिकार तो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के भीतर हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया ने शिकारियों को पकड़वाने के लिए 25 हजार का ईनाम भी घोषित किया था। बांधवगढ़ में बाघों की यह मौतें सहज नहीं थी, क्योंकि किसी का शव जमीन में दबा मिला, तो किसी को मारने के बाद झाड़ियों में छिपा दिया गया था। बांधवगढ़ में बाघों की मौतों के सबसे ज्यादा मामले संदेहास्पद पाए गए हैं। मप्र में ज्यादा मौतें बताती हैं कि बाघ प्रबंधन में कितनी लापरवाही और उदासीनता बरती जा रही।

मप्र में वन्य-जीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो देश के दर्जन भर राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वन क्षेत्रों से भी बड़ा है। मप्र में 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र हैं। यहां 10 राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्य-प्राणी अभयारण्य हैं, जो विविधता से भरपूर है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है। अपनी स्थापना के समय से ही ये नेशनल पार्क और अभयारण्य रसूखदारों और तस्करों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यही कारण है की इनके भीतर स्थित गांवों को जहां बाहर किया जा रहा है, वहीं इनके आसपास फार्म हाउस और रिसार्ट बड़ी तेजी से बने हैं। जानकार बताते हैं कि जब नेशनल पार्क तथा अभयारण्यों के आसपास फार्म हाउस और रिसोर्ट बढ़ने लगे तब से प्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार के मामले भी बढ़ गए। वर्ष 2006 के पहले तक मप्र में बाघों की संख्या सबसे अधिक होने से टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार था। ऐसा भी मौका आया जब मप्र में करीब 700 टाइगर थे। वन विभाग वन्यप्राणियों की मौतों के कारण चाहे जो भी बताए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मप्र के बांधवगढ़, पन्ना, सिवनी, मंडला, भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन के जंगल शिकारियों के पनाहगाह बन गए हैं। देश के दूसरे राज्यों में टाइगर कॉरिडोर बड़े जंगलों में फैले हुए हैं, लेकिन मप्र में ऐसा नहीं है, इसलिए शिकारी घात लगा लेते हैं।

● **सुनील सिंह**

नई सेंचुरी की घोषणा, पुरानी ठंडे बस्ते में

बाघों की मौत का सही कारण नहीं मिलने और मौत को दबाने के लिए हर बार एक घोषणा कर दी जाती है। हाल ही में वन मंत्री विजय शाह ने बुंदेलखंड में नई सेंचुरी घोषित की, जबकि टाइगर स्टेट का तमगा मिलने के बाद प्रदेश में शुरू हुई 11 नए अभयारण्य गठन की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लग गया है। राज्य सरकार ने नए अभयारण्यों की जरूरत को सिरे से खारिज करते हुए इस प्रक्रिया को रोक दिया है। इनमें से पांच अभयारण्य के प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जा चुके थे तो शेष छह अभयारण्यों के प्रस्ताव भी लगभग तैयार थे। पिछले दिनों वन मंत्री विजय शाह ने साफ कहा है कि प्रदेश में कोई नया अभयारण्य नहीं खोला जाएगा। वर्ष 2018 के बाघ आंकलन (टाइगर एस्टीमेशन) में प्रदेश 526 संख्या के साथ देश में पहले स्थान पर रहा है। इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। विशेषज्ञों ने साफ कहा था कि बाघों की संख्या बढ़ने का मतलब है, ज्यादा निगरानी और बाघों के लिए नए क्षेत्रों का विकास। इसी सलाह पर पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने 11 नए अभयारण्यों के गठन का प्रस्ताव तैयार किया था। नाथ सरकार अभयारण्यों के गठन पर आखिरी फैसला ले पाती, इससे पहले ही सरकार गिर गई।

डेंगू का डंक

कोरोना महामारी के बाद मप्र सहित देशभर में डेंगू का कहर जारी है। मप्र में 14 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। यह इस बात का संकेत है कि हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग और निकाय मच्छरों को नहीं मार पाए।

कोरोना महामारी की दोनों लहरों में लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा उसने यह साबित कर दिया कि अगर कोई बीमारी महामारी का रूप ले ले, तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जवाब दे जाती है। इन दिनों तेजी से फैलते डेंगू ने भी यही साबित कर दिया है। कुछ राज्यों में तो हाल यह है कि मरीजों को समय पर सही इलाज मिलना तो दूर, जांच तक समय पर नहीं हो पा रही है। संक्रमण मुक्त पलंग (बेड) तक हर जगह मौजूद नहीं हैं, जिससे संक्रमण और बढ़ रहा है। डेंगू के इतने मरीज बढ़ रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों में बेड के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के जर्जर इसकी मूल वजह स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार होता निजीकरण और कार्पोरेट अस्पतालों का विस्तार होना है।

गंभीर बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में भी अब डॉक्टरों की नियुक्तियां अनौपचारिक (एडहॉक) या अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) पर एक या दो साल के लिए होने लगी हैं। इसके चलते डॉक्टर्स या तो मन से सेवाएं नहीं देते या फिर नियमित होने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स की कमी के चलते मरीज इलाज के लिए भटकते रहते हैं और कई बार इलाज न मिलने या समय पर इलाज न मिलने पर दम तोड़ देते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) कई बार आगाह कर चुका है। लेकिन सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की जगह उनके निजीकरण का विस्तार ही किया है।

मौजूदा समय में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उप्र, मप्र समेत कई अन्य प्रदेशों में डेंगू ने पिछले महीने से पैर पसार रखे हैं। जब भी कोई बीमारी महामारी का रूप लेती है, तो व्यवस्था के अभाव की वजह से मरीजों को झोलाछाप डॉक्टरों तक से इलाज कराने को मजबूर होना पड़ता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर अनिल बंसल का कहना है कि कोई भी संक्रमित बीमारी हो, अगर उसका समय रहते पक्का इलाज न हो तो वह भयंकर रूप ले लेती है। मौजूदा समय में डेंगू तेजी से फैल रहा है। देश के गरीब लोग सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर हैं। कहीं-कहीं सरकारी अस्पतालों की दशा बहुत खराब है। सरकारी अस्पतालों की लैबों में जांच रिपोर्ट ही दो से तीन दिन में मिलती है, जबकि डेंगू में रक्त की तुरंत जांच और प्लेटलेट्स की गिनती बहुत जरूरी होती है। लेकिन समय पर जांच रिपोर्ट न मिलने के चलते मरीजों को खतरा बढ़ जाता है और डेंगू के सही आंकड़े भी नहीं आ पाते। डॉक्टर बंसल कहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य बजट भी बहुत कम है।

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी डालमिया कहते हैं कि डेंगू हर साल कहर बनकर आता है। डेंगू फैलाने वाला एडीज इजिप्टी मच्छर साफ पानी और घरों में पनपता है। यही वजह है कि इन मच्छरों की संख्या बढ़ने पर डेंगू भी तेजी से फैलता है। ऐसे में घरों की सफाई, साफ पानी को भी ढंककर रखने, पानी जमा न होने देने और मच्छरों को मारने वाली दवा से ही इसका इलाज जरूरी है। साथ ही इन दिनों में होने वाले बुखार को लोग सामान्य न समझें और इलाज के साथ-साथ सबसे पहले डेंगू की जांच कराएं, ताकि अगर मरीज को डेंगू है, तो समय रहते उसका इलाज हो सके।

डेंगू विरोधी अभियान में गत 8 साल से काम करने वाले डॉक्टर दिव्यांग देव गोस्वामी का कहना है कि कई राज्यों में डेंगू के तेजी से विस्तार के लिए सरकार की उदासीनता और स्वास्थ्य एजेंसियां जिम्मेदार हैं। जब हर साल अक्टूबर और नवंबर में डेंगू फैलता है, तो सरकार डेंगू से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करती है? दवाओं का छिड़काव पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता। साल में दो-चार बार धुआं छोड़ने वाले आते हैं, जिससे मच्छर तो नहीं मरते, प्रदूषण जरूर फैल जाता है। देश में स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है, जिसके चलते पैसा कमाने के लालच में कॉर्पोरेट घराने इस क्षेत्र में पांव पसारते जा रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से इलाज दूर होता जा रहा है। बीमारियों को एक सुनियोजित तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे दवा कंपनियों और जांच केंद्रों का कारोबारी स्वार्थ भी है। डॉक्टर गोस्वामी का कहना है कि कई राज्यों में मरीजों के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं हैं। कई अस्पतालों में मानवता को झझकोर देनी वाली घटनाएं घट रही हैं।

● **बृजेश साहू**

स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा ज्यादा खराब

मप्र के सरकारी अस्पतालों की जानकारी जुटाई, जहां देखने में आया कि स्वास्थ्य व्यवस्था में उप्र की दशा सबसे ज्यादा खराब है। वहां डेंगू से मरने वालों की संख्या भी इसकी गवाह है। एक मरीज ने बताया कि अब तो डेंगू कुछ कम हो रहा है, लेकिन जब डेंगू के मामले चरम पर थे, तब एक-एक बेड पर कई-कई मरीज डाले जा रहे थे। इतने पर भी अनेक मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे थे। कई-कई दिन बेड की चादरें नहीं बदली जा रही थीं। डॉक्टर भी क्या करें, जब संसाधन ही नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा? एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि कुछ सरकारी डॉक्टर मरीजों को निजी अस्पतालों में भेज रहे थे। अब यह सांठगांठ की वजह से होता है या अव्यवस्था की वजह से, नहीं कह सकते।

धान की खरीद में कालाबाजारी

देश के किसान इन दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सरकार मौखिक रूप से कई बार कह चुकी है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। लेकिन क्या यह सत्य है? शायद नहीं। क्योंकि हर छमाही रबी और खरीफ की फसल बेचने के लिए किसानों को जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उससे यह साफ है कि इस बार भी धान की खरीदी में जमकर कालाबाजारी हो रही है। मप्र में 29 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई है। लेकिन प्रदेश के छोटे किसानों ने अपनी उपज समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर पहले ही बेच दी है और जो बचे हैं वे व्यापारियों को बेच रहे हैं। दरअसल धान कटाई के बाद किसानों को गेहूं की बोनी, खाद, कीटनाशक व अन्य कार्यों के लिए रुपयों की जरूरत है। इसलिए किसान बिचौलियों व व्यापारियों को मनमाने दाम पर अपनी उपज बेचकर अपना काम कर रहे हैं।

शासन द्वारा 29 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की गई हैं जिसमें धान का समर्थन मूल्य 1940 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। लेकिन इससे पहले ही छोटे किसानों ने 1400 से 1700 प्रति क्विंटल की दर से बेच दिया है। सवाल यह है कि किसान किससे शिकायत करें? सरकार एमएसपी पर गारंटी देना नहीं चाहती और खरीद केंद्रों को भी देरी से खोला जाता है। इसके बाद वहां भी किसानों के अनाज में अनेक कमियां निकालकर करदा काटकर अनाज को तौला जाता है। अगर किसान खरीदी केंद्रों की शिकायत करें, तो उन पर खरीद करने वाले लोग अनाज को गीला और खराब बताकर खरीदने से मना कर देते हैं। मप्र, उप्र, हरियाणा, पंजाब और बिहार के कई किसानों ने बताया कि किसानों के साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है।

मप्र के किसान विनोद कुमार साहू का कहते हैं कि यह पूंजीपतियों की सोची-समझी चाल है, जिसके तहत धान ही नहीं, किसी भी फसल की खरीददारी समय पर नहीं की जाती है। पहले डीजल-पेट्रोल के दाम कम थे, तो किराया-भाड़ा भी कम लगता था, लेकिन अब तो वह भी बढ़ गया है। पहले किसान आसानी से दूसरे जिले या राज्य में फसल बेच देते थे, अब यह संभव नहीं है। कुल मिलाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। महंगाई के अलावा बीमारियों का दौर चल रहा है। ऐसे में हर किसान को पैसे की सख्त जरूरत है और इसका फायदा आढ़तिये, पूंजीपति, खरीद केंद्रों के कर्मचारी, मंडियों में बैठे दलाल उठा रहे हैं और सरकार एमएसपी का ढोल ऐसे पीटती है, जैसे हकीकत में उसने किसानों पर कोई एहसान कर दिया हो। बड़ी बात तो यह है कि एमएसपी पर किसानों के खाद्यान शायद ही कहीं खरीदे जाते हों। बताते चलें एक दौर में खाद्यान्न खेतों से सीधे खरीद केंद्रों पर तुलते थे, बाजार में भी उनके दाम ठीक-ठाक मिल जाते थे। तब किसानों को प्रशासन से मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ती थीं और न ही समझौते का सहारा लेना पड़ता था। अब यह हालत है कि खरीद केंद्रों पर कर्मचारियों का दबदबा चलता है। वहां पुलिस मौजूद होती है। टोकन सिस्टम है। बारी आने पर अनाज लिया जाता है और बारी कई दिन तक नहीं आती। जब बारी आती है, तो कई कमियां। ऐसे में किसानों का हर तरह से नुकसान-ही-नुकसान होता है।

किसान नेता और वकील चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक के इतिहास में किसानों के साथ बाजारों में इतना भेदभाव नहीं हुआ है, जितना कि अब हो रहा है। उनका कहना है कि बाजारों और गेहूं की बड़ी-बड़ी मंडियों में सत्ता से जुड़े पूंजीपतियों का कारोबार है। सरकार द्वारा निर्धारित भाव को वे मानते नहीं हैं। अपने-अपने हिसाब से खरीद-फरोख्त करते हैं। गरीब किसान मजबूरी में औने-पौने दाम में उन्हें अनाज बेच देते हैं। सरकार ने जो खरीद केंद्र बनाए हैं, वहां पर प्रशासन भी मंडियों की भाषा बोलता है। ऐसे में आखिरकार न चाहते हुए भी किसान हर हालत में लुटता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में पहले जमाखोरी का कारोबार कम हुआ करता था। लेकिन अब सरकार में पूंजीपतियों की तूती बोल रही है और वे सारे कायदे-कानून ताक पर रखकर जमाखोरी करके खाद्यान की कालाबाजारी कर रहे हैं। यह एक सच्चाई है कि अब देश के पूंजीपतियों की नजर कृषि उत्पादों पर टिकी है और वे इस पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। किसानों का तो कहना है कि तीन कृषि कानून भी सरकार इसी सोच के चलते लाई है और यही वजह है कि उन्हें वापस करना नहीं चाहती।

इस बार प्रदेश में धान की बंपर पैदावार होने की संभावना है। क्योंकि किसानों ने 35 लाख हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में धान की बोवनी की। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 45 लाख टन से ज्यादा धान खरीदने की तैयारियां की हैं। पिछले साल राज्य में सर्वाधिक 37 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी। वहीं, कोशिश यह भी है कि केंद्र सरकार को सेंट्रल पूल में 10 लाख टन से ज्यादा चावल दिया जाए। इस साल अभी तक चार लाख टन चावल भारतीय खाद्य निगम को दिया जा चुका है। दिसंबर तक दो लाख टन चावल और दिए जाने की संभावना है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में किसान सोयाबीन से मुंह मोड़ने लगे हैं और धान की ओर उनका रूझान बढ़ने लगा है। प्रदेश में धान के समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ने के साथ धीरे-धीरे धान का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। 2019 में 30.76 लाख हैक्टेयर में धान बोया गया था। जबकि 2020 में 34.04 लाख हैक्टेयर में बोवनी की गई। वर्ष 2021 में 35 लाख हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में धान की खेती की गई है।

● श्याम सिंह सिकरवार

साल दर साल बढ़ रहा उत्पादन

प्रदेश में धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 106 लाख टन से ज्यादा धान हुआ था। इस बार अनुमान है कि 125 लाख टन से ज्यादा धान का उत्पादन होगा। पिछले साल पांच लाख 80 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। इस बार 9 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। इसे देखते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने समर्थन मूल्य पर 45 लाख टन धान बिकने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आने का अनुमान लगाया है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य भी 72 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर एक हजार 940 रुपए कर दिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि इस बार पिछले साल से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। हमने धान खरीदने, रखने और मिलिंग की पूरी तैयारी कर ली है।

इंदौर का सफाई में पंच

केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार पांचवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के परिणामों की घोषणा गत दिनों की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। सर्वेक्षण में वाराणसी को 'स्वच्छ गंगा शहर' की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और गांधीजी की इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया।

स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर मप्र ने अपना लोहा मनवाया है। इंदौर जहां लगातार पांचवी बार देश का सबसे साफ शहर घोषित हुआ है, वहीं मप्र को इस बार 35 अवार्ड मिले हैं। हालांकि ग्वालियर सहित कुछ अन्य शहरों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। लेकिन मप्र की स्थिति संतोषजनक है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में मप्र के इंदौर शहर का एक बार फिर डंका बजा है। इंदौर 5वीं बार भी देशभर में अव्वल आया है। वर्ष 2017 से इंदौर देशभर में नंबर-1 पर आ रहा है। इस बार इंदौर ने सफाई का पंच लगा दिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर अव्वल रहा। इसमें 12 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला। राज्य कैटेगरी में मप्र को तीसरा स्थान मिला है। मप्र को कुल 35 अवार्ड मिले हैं। इंदौर के पांचवीं बार टॉप रहने पर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंदौरी अंदाज दिखा। उन्होंने ट्वीट किया- वाह भिया! छा गया अपना इंदौर...। दस लाख से ज्यादा आबादी वाले टॉप 20 शहरों में मप्र के चारों बड़े शहर शामिल हैं। इंदौर-1, भोपाल-7 ग्वालियर-15 जबलपुर-20 नंबर पर है। 10 लाख तक की आबादी में उज्जैन का पांचवा नंबर है। वहीं तीन लाख की आबादी वाले शहर में देवास को छठवां स्थान मिला है।

दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में विजेता शहरों और प्रदेशों को सम्मानित किया जा रहा है। देश के सबसे साफ शहरों की श्रेणी में इंदौर की प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी। हुआ भी वैसा ही। साल 2017 से इंदौर नंबर-1 पोजिशन पर है। लगातार पांचवीं बार उसे यह खिताब मिला है। राष्ट्रपति कोविंद ने नंबर-1 पर रहे इंदौर को अवार्ड दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंच पर मौजूद रहे। इंदौर का अवार्ड लेने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल आदि दिल्ली पहुंचे थे। भोपाल से भी कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर-भोपाल समेत उज्जैन, देवास, होशंगाबाद और बड़वाह को नामांकित किया गया था। भोपाल ने सफाई मित्र, स्टार रेटिंग और स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए दावा किया। पिछले साल भोपाल देश के सबसे साफ शहरों में सातवें नंबर पर था। इस बार रैंकिंग में सुधार हुआ है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में इंदौर, भोपाल और देवास ने राष्ट्रीय पुस्कारों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया है। इसमें इन्हें अच्छी पोजिशन मिली है। स्टार रेटिंग में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, ग्वालियर, सिंगरौली, मूंदी, बुरहानपुर, राजगढ़ और धार समेत 25 शहरों ने दावा किया था। इनमें कई शहर आगे रहे हैं।

● **विकास दुबे**

भोपाल देश का 7वां सबसे साफ शहर

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ-सुथरा शहर बन गया है। वहीं, बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी मिला है। यह रैंकिंग और अवार्ड पिछले साल भी मिले थे। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल तीसरे नंबर पर रहा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मप्र के टॉप-20 शहरों में चार महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर शामिल हैं। हालांकि, सीवेज, पॉलिथीन का उपयोग और खुले में कचरा फेंकने जैसी समस्याओं के कारण भोपाल का इंदौर को पछाड़ पाना ख्वाब जैसा ही माना जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर ने जहां नंबर-1 की पॉजिशन हासिल की है। वहीं, राजधानी भोपाल 7वें नंबर पर रहा। उसे 6000 में से 4783.53 अंक मिले हैं। सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला। यह अवार्ड पिछले साल भी भोपाल को मिला था। इस बार नए अवार्ड के रूप में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में थर्ड पॉजिशन हासिल हुई है। इसमें निगम को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल ने 2017 और 2018 में लगातार दो साल देश में दूसरी रैंक हासिल की थी। 2019 में भोपाल खिसककर 19वें नंबर पर आ गया था। उस समय अफसरों के लगातार तबादले के कारण तैयारियों की दिशा ही तय नहीं हो पाई थीं, लेकिन 2020 में कमबैक करते हुए 12 पायदान ऊपर खिसका और 7वीं रैंक हासिल की। इस बार भी 7वां स्थान हासिल किया है।

अब प्रदेश में होगी वाहनों की एक ही नंबर की सीरीज

मप्र में सड़क सुरक्षा और सड़क परिवहन के प्रति सरकार लगातार सजग है और क्रांतिकारी पहल कर रही है। अब सरकार नए साल में वाहनों के नंबर की नई सीरीज लाने जा रही है। जानकारों का कहना है कि कई जिलों में वर्तमान नंबर की सीरीज लगभग समाप्त होने वाली है। ऐसे में पूरे प्रदेश में नई सीरीज शुरू होगी।

प्रदेश में जल्द ही सभी वाहनों के नंबर की एक ही सीरीज होगी। अब तक हर जिले के वाहनों की अपनी अलग सीरीज होती है, लेकिन जल्द ही परिवहन विभाग इस व्यवस्था को खत्म कर प्रदेश के सभी वाहनों के नंबरों की एक ही सीरीज चलाएगा। इससे यह तो पता नहीं चलेगा कि गाड़ी किस शहर की है, लेकिन गाड़ी का मॉडल किस साल का है यह आसानी से पता चल जाएगा। इसे लेकर योजना तैयार कर ली गई है। संभवत: अगले साल से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इसके तहत नंबर की शुरुआत जिस वर्ष से होगी उस वर्ष को लिखा जाएगा। इसके बाद प्रदेश, यानी मप्र आएगा, फिर नंबर और आखिरी में सीरीज के अल्फाबेट आएंगे। इस तरह नए साल की पहली गाड़ी का नंबर 22-एमपी-0001-ए हो सकता है।

कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और ऐसी नौकरी वाले लोगों, जिनके लगातार देश में कहीं भी ट्रांसफर होते हैं, के लिए बीएच सीरीज की शुरुआत की है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति अपनी गाड़ी पर ऐसे नंबर ले सकते हैं जो पूरे देश में एक समान रूप से चलेंगे, अन्यथा राज्य बदलने पर नंबर की सीरीज भी राज्यवार बदल जाती है। कुछ दिनों पहले ही कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत भी की है और जल्द ही मप्र में भी इसकी शुरुआत होने वाली है। इसके तहत वाहन के नंबर की शुरुआत वाहन के रजिस्ट्रेशन के वर्ष के अंतिम दो अंक, फिर बीएच, फिर नंबर और बाद में सीरीज के अल्फाबेट आते हैं। इसके बाद नंबर 21-बीएच-0001-एए की तरह नजर आते हैं, लेकिन यह सुविधा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों और ट्रांसफर होने वाली नौकरी करने वाले लोगों को ही मिलेगी। इसी से प्रेरित होकर मप्र परिवहन विभाग ने भी प्रदेश की एक ही सीरीज शुरू करने की योजना तैयार की है। बताया जा रहा है कि अन्य प्रदेश भी अपने यहां जिलेवार नंबरों की सीरीज को खत्म करते हुए प्रदेश की एक ही सीरीज शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका कारण सभी प्रदेशों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल सर्वर से जुड़ जाना है। एक ही सीरीज होने से इस प्रक्रिया में भी आसानी आएगी।

इस पूरी योजना के लिए परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मसौदा तैयार करते हुए मुख्यालय को भेजा है, जिस पर परिवहन मंत्री और आयुक्त विचार करेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही इसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और साल 2022 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

नई व्यवस्था से सरकार को वीआईपी नंबरों से होने वाली आय भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी वीआईपी नंबरों की नीलामी जिला स्तर पर होती है। नई व्यवस्था के बाद जिला स्तर पर नंबर बंद हो जाएंगे और प्रदेश स्तर पर एक ही सीरीज खुलेगी। इससे नई सीरीजें भी जल्दी-जल्दी आएंगी, जिससे वीआईपी नंबर भी ज्यादा मिल सकेंगे। वहीं वीआईपी नंबरों के लिए पूरे प्रदेश से शौकीन बोली लगाएंगे। इससे बोली बड़े स्तर पर पहुंचेगी और शासन को ज्यादा राजस्व मिल सकेगा।

● **लोकेंद्र शर्मा**

अपने पुराने नंबर के लिए दोबारा चुकाना पड़ेगी नीलामी की राशि

वीआईपी नंबरों के शौकीनों के लिए प्रदेश सरकार एक तोहफा लेकर आई है। वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी का वीआईपी नंबर गाड़ी खराब होने के बाद भी रख सकेंगे। इस नंबर को वे अपनी नई गाड़ी पर दर्ज करवा सकेंगे। हालांकि यह नंबर उन लोगों को महंगा पड़ेगा, जिन्होंने नीलामी में ऊंची बोली लगाकर नंबर लिया था। वाहन मालिक को नई गाड़ी पर पुराना वीआईपी नंबर लेने के लिए भी उतनी ही कीमत चुकाना पड़ेगी, जितने में पहले उसने नंबर खरीदा था। प्रदेश में लंबे समय से इस संबंध में मांग की जा रही थी कि ऊंची कीमत पर वीआईपी नंबर खरीदने वाले लोगों को वो नंबर गाड़ी के खराब हो जाने के बाद नई गाड़ी पर दिए जाने की व्यवस्था की जाए। पंजाब, हरियाणा सहित कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था लागू है। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने कुछ समय पहले इस व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की थी। इसे लेकर हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर दावे-आपत्तियों की सुनवाई के बाद जल्द ही प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। आदेश के मुताबिक वीआईपी नंबर ट्रांसफर करवाने के लिए यह जरूरी होगा कि पहले जिस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी थी, नई गाड़ी भी उसके ही नाम पर हो। इसके बाद वाहन मालिक को वीआईपी नंबर ऑनलाइन नीलामी से या उससे पहले लागू व्यवस्था 'पहले आओ-पहले पाओ' की तरह लिए गए नंबर के लिए जो कीमत चुकाई थी उसमें नीलामी की राशि या 15 हजार रुपए जो राशि ज्यादा हो वह चुकाना होगी। इसके साथ ही पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी के लिए तब ही मिलेगा, जब वाहन मालिक शासन की नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन को स्क्रैप करवाने के बाद पंजीयन निरस्त करवाएगा और स्क्रैप का सर्टिफिकेट जमा करवाएगा। इसके बिना पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

मंडरा रहा है सूखे का खतरा

सूखा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (डीईडब्ल्यूएस) द्वारा जारी हालिया आंकड़ों को देखें तो भारत का पांचवां हिस्सा (21.6 फीसदी भू-भाग) सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। देखा जाए तो सूखे का सामना करने वाला यह क्षेत्र पिछले साल की तुलना में करीब 62 फीसदी ज्यादा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान देश का करीब 7.86 फीसदी हिस्सा सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा था। आंकड़ों के अनुसार देश का जो 21.6 फीसदी हिस्सा सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, वहां कहीं सूखे की स्थिति मध्यम और कहीं काफी गंभीर है। जहां 1.63 फीसदी क्षेत्र अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहा है, वहीं 1.73 फीसदी भू-भाग असाधारण रूप से शुष्क है। 2.17 फीसदी गंभीर रूप से शुष्क है जबकि 8.15 फीसदी हिस्सा मध्यम रूप से शुष्क है। 16 अगस्त, 2021 को जारी नवीनतम इन आंकड़ों के अनुसार देश की करीब 7.38 फीसदी भूमि असामान्य रूप से शुष्क है।

पिछले कुछ समय से देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बानी हुई है। वहीं पिछले दो महीनों में हुई बारिश के पैटर्न के आधार पर लगाए गए अनुमान के अनुसार राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और नागालैंड जैसे कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूखे की गंभीर से असाधारण स्थिति बनी हुई है। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि पश्चिमी राजस्थान में तो सूखे की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वहां पाली जिले में जल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन ट्रेन से पानी की सप्लाई पर विचार कर रहा है। इस जिले में सामान्य से 37 फीसदी कम बारिश हुई है और पूरे जिले को पानी की आपूर्ति करने वाले बांध में केवल एक माह का पानी शेष बचा है। इस बारे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के एसोसिएट प्रोफेसर विमल मिश्रा ने जानकारी दी है कि दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं। यदि इन क्षेत्रों में मानसून के शेष भाग के दौरान वर्षा नहीं होती है, तो स्थिति और खराब हो सकती है। अनुमान है कि मौजूदा स्थिति के लिए वर्षा का असमान वितरण और मानसून का विफल होना मुख्य वजहों में से है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इनमें से अधिकांश राज्यों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। 19 अगस्त तक जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में सामान्य से 48 फीसदी कम बारिश हुई है, वहीं ओडिशा में यह आंकड़ा 29 फीसदी है। वहीं नागालैंड और पंजाब दोनों राज्यों में सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 11 फीसदी और राजस्थान में सामान्य से चार फीसदी बारिश कम हुई है। पिछले एक महीने के दौरान मिट्टी में मौजूद नमी से जुड़े सूचकांक पर आधारित अनुमानों के अनुसार ओडिशा के कई जिले सूखे की चपेट में है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो खरीफ फसल को बचाने के लिए राज्य सरकार पहले ही कृषि विभाग को आकस्मिक योजना तैयार करने का निर्देश दे चुकी है।

जलवायु मॉडल के अनुमानों से पता चलता है कि ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) की बढ़ती मात्रा के तहत सूखा कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। शुष्क भूमि के वातावरण को देशों और क्षेत्रों के द्वारा साझा किया जाता है। लेकिन इन पारिस्थितिक तंत्रों का प्रबंधन अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से होता है। साथ ही, एशियाई शुष्क भूमि के लिए सीएमआईपी 6 आंकड़ों पर आधारित अध्ययनों का अभाव है। शोध के परिणामों से पता चला है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक-आर्थिक मार्गों के तहत, भविष्य में दुनियाभर में स्थलीय सूखे की बढ़ती प्रवृत्ति में आशंका जताई गई। बढ़ते सूखे की आशंका शेयर्ड सोसिओ-इकोनॉमिक पाथवेज (एसएसपी) 126, एसएसपी 245 और एसएसपी 585 के तहत दिखाई दी है। इन तीनों के आधार पर सूखे का अनुपात क्रमश: 36.2 फीसदी, 53.3 फीसदी और 68.3 फीसदी पाया गया। इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने पाया कि भविष्य में सूखा कम बार पड़ेगा, लेकिन सूखे की अवधि लंबी और अधिक तीव्र होगी। भविष्य में सूखे की यह अवधि 2021 से 2060 और 2061 से 2100 की अवधि क्रमश: 10.8 महीने और 13.4 महीने होगी, जबकि ऐतिहासिक अवधि 1960 से 2000 की अवधि 6.6 महीने तक की थी। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक भारत में अधिकांश सूखे की घटनाएं मानसून के मौसम के दौरान हुई हैं। विशेष रूप से सूखे की घटनाएं देश के मध्य, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व के इलाकों में देखी गई। ये घटनाएं 1980 से 2015 के बीच मई से लेकर सितंबर के दौरान हुई थीं। मौसम संबंधी अचानक सूखे की घटना के विश्लेषण से पता चला है कि ये क्षेत्र मानसून के मौसम की शुरुआत में अपनी चरम सीमा का अनुभव करते हैं। अचानक होने वाली सूखे की घटनाओं का बार-बार होना मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई गई।

● राजेश बोरकर

एशियाई देशों में बढ़ सकती है सूखे की त्रासदी

एशिया में दुनिया के सबसे बड़े शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र है, यह 1,145 वर्ग किलोमीटर तक फैले हैं। इसलिए एशियाई शुष्क इलाकों में भविष्य में पड़ने वाले सूखे का समय पर मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। हाल के वर्षों में बार-बार आने वाले रेत के तूफानों को लेकर भी यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। शुष्क क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन और जलवायु के चरम सीमाओं का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। एशिया में शुष्क क्षेत्र पश्चिम में कैस्पियन सागर से पूर्व में मंचूरिया तक फैला हुआ है। इसमें मंगोलिया गणराज्य और उत्तर पश्चिमी चीन के साथ पांच मध्य एशियाई देश शामिल हैं। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक भारत में भी मौसम संबंधी सूखे की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। सूखे की वजह से स्थानीय कृषि, जल संसाधनों और पारिस्थितिक पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते भविष्य में सूखे की वजह से होने वाले बदलावों के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण है।

बुंदेलखंड की सियासी बयार

तैयार है सूखे की सियासी फसल

गरीबी, सूखा और पिछड़ेपन पर राजनीतिक फसल की कटाई का वक्त आ गया है। बुंदेलखंड के गांव-कस्बों में साफ नजर आ रहा है कि जीत के लिए जरूरी जाति के समीकरण काफी बदल गए हैं। 403 विधानसभा सीटों वाले उप्र में महज 19 सीटें रखने वाले बुंदेलखंड पर सभी की नजर है। वैसे बुंदेलखंड की 19 सीटों पर औसतन 25 फीसदी दलित वोटर हैं। इनमें जाटव और गैर-जाटव के बीच मोटे तौर पर 60-40 का अनुपात है। माना जा रहा है कि इस बार वाल्मीकि, कोरी, बरार और अन्य दलित जातियों में बसपा के प्रति थोड़ी खटास हो सकती है। कांग्रेस इसी खटास के जरिए बुंदेलखंड में अपना दही जमाना चाहती है। कांग्रेस को भरोसा है कि मुसलमान उसे समर्थन देंगे और कुछ हद तक ओबीसी और ब्राह्मण वोट भी उसकी झोली में आएंगे।

उप्र में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, शहरों से लेकर गांवों तक के मतदाताओं में सियासी दल गुणा-भाग कर अपना-अपना जनाधार मजबूत करने की जुगत में लगे हैं। ऐसे में बुंदेलखंड में एक बार फिर से सियासी बयार तेज हो गई है। सूखे, गरीबी से बेहाल लोगों को उम्मीद जगी है कि राजनीतिक पार्टियां उनके क्षेत्र के लिए विकास का पिटारा खोलेंगी। उप्र के छह जिलों झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। हर गांव में नेताओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोगों को केवल वादों और आश्वासनों से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि बुंदेलखंड के विकास के लिए किसी के पास कोई सुनियोजित प्रोग्राम नहीं है।

बुंदेलखंड के लोगों का कहना है कि उपेक्षा और अनदेखी पहले की सरकारों ने भी की और वर्तमान सरकार भी कर रही है। बुंदेलखंड के लोगों को सियासी दलों ने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसके कारण बुंदेलखंड दिन-ब-दिन पिछड़ता ही गया है। यहां बेरोजगार लोग बड़ी संख्या में हैं। आज भी लोग बिजली-पानी और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया इस बार यहां के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले साबित होंगे। क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर बढ़ती महंगाई के अलावा किसानों को खाद के लिए जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते वे समय पर बुवाई नहीं कर पा रहे हैं।

बताते चलें कि इस बार का विधानसभा चुनाव भाजपा और सपा के बीच सीधी चुनावी टक्कर तो है, लेकिन कांग्रेस के बढ़ते जनाधार और बसपा की चुनावी चुप्पी से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा इस बार उप्र की सियासत में दो नई सियासी पार्टियां- आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर सेंध लगाएंगी। लोगों का मानना है कि बुंदेलखंड में दो दशक से बसपा, सपा और भाजपा को एक तरफा शासन का मौका मिला है। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ औवेसी की पार्टी अगर दमखम से चुनाव लड़ती है, तो बुंदेलखंड में काफी कुछ बदलाव की राजनीति हो सकती है।

बुंदेलखंड के लोगों का कहना है कि आज भी यहां के लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली-पानी की सुविधा देते हैं, तो केजरीवाल को जिताने में क्या हर्ज है? अब तक जिस तरह पूरे देश में जाति-धर्म की सियासत होती रही है, उससे कहीं बढ़कर बुंदेलखंड में जाति-धर्म को लेकर सियासत होती है। लेकिन इस बार बुंदेलखंड के लोग जाति-धर्म से हटकर विकास के लिए चुनाव में मतदान करने का मन बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब पूर्वांचल और पश्चिमी उप्र में विकास हो सकता है, तो बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हो सकता? जबकि बुंदेलखंड में 19 विधानसभा सीटों में भाजपा का परचम लहराया था।

बुंदेलखंड के लोगों का कहना है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुंदेलखंड के लोगों के बीच आकर साफ कहा है कि सपा, बसपा और भाजपा ने यहां की जनता को गुमराह किया है, जिसके चलते आज भी यहां के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। बुंदेलखंड की राजनीति के जानकार संजीव कुमार का कहना है कि इस बार अगर कोई भी सियासी दल सही प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारता है, तो वह चुनाव जीत सकता है। क्योंकि अभी जो चुनाव जीते हैं, वे रातोंरात भाजपा में शामिल होकर भाजपा लहर में जीतकर तो आ गए हैं; लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड का विकास न करके, खुद का विकास किया है। यहां के लोगों का कहना है कि जब 2017 में बुंदेलखंड की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

विकास बोर्ड का गठन तो हुआ, लेकिन विकास नहीं हुआ। भाजपा के प्रति लोगों के बढ़ते आक्रोश के चलते जीते हुए विधायकों का टिकट कटने कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते यहां की सियासतदानों में उथल-पुथल सी मची हुई है। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भी कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के विकास में कोई बाधा नहीं आने देंगे। जबकि यहां के लोगों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने का वादा किया था, लेकिन सड़कों की हालत और जर्जर हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आशाराम सिंह का कहना है कि अगर सपा का संवर्ग मत (काडर वोट) मुस्लिम-यादव तथा अन्य जातियों के मतदाता मजबूती के साथ रहे, तो कोई भी राजनीतिक दल सपा को सरकार बनाने से नहीं रोक सकेगा। आने वाले समय में चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि अगर भाजपा, सपा और बसपा के विधायकों को उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिए, तो वे किसी दूसरे दल के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इससे यह बात तो साफ है कि भाजपा ही नहीं, दूसरे क्षेत्रीय दलों की भी स्थिति बुंदेलखंड में बहुत मजबूत नहीं है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

चाल, चेहरा और चरित्र वाली भाजपा में बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। शायद इसकी वजह है मिशन-2023 और 2024। मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा ने मप्र सहित देशभर में 51 फीसदी वोट का टारगेट रखा है। इस टारगेट को पाने के लिए मप्र में सत्ता और संगठन को कसौटी पर परखा जा रहा है। इसके लिए विगत दिनों विधायकों से दो दिनों तक वन-टू-वन की गई, उसके बाद कार्यसमिति में टारगेट तय किया गया, फिर मंत्रियों, पदाधिकारियों से उनके कार्यकाल का हिसाब लिया गया। इन सबके आधार पर सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव का खाका तैयार होगा।

● राजेंद्र आगाल

भाजपा अपनी हर गलती से सबक लेती है और फिर नई तैयारी से जुट जाती है। यानी पार्टी हार के बाद जीत के लिए पूरे तन-मन से लग जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मप्र में 2018 का विधानसभा चुनाव रहा है। इस चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए भाजपा ने अभी से मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। सत्ता और संगठन लगातार मिशन 2023 को लेकर मंथन कर रहे हैं। आलाकमान ने प्रदेश संगठन को 51 फीसदी वोट पाकर 200 से अधिक सीटें जीतने का टारगेट दिया है। ऐसे में पार्टी ने रणनीति बनाई है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता और संगठन से उन चेहरों को बाहर किया जाए जिनकी परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है। इसके लिए नवंबर महीने में कई स्तरों पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई। अब यह रिपोर्ट आलाकमान के पास पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर सत्ता और संगठन का चाल, चेहरा और चरित्र बदला जाएगा।

गौरतलब है कि मप्र भाजपा और संघ की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। अपनी नई नीति और रणनीति का यहीं परीक्षण होता है। फिर उसे दूसरे राज्यों में लागू किया जाता है। अपनी इसी रणनीति के तहत भाजपा ने मिशन 2022, 2023 और 2024 के लिए 51 फीसदी वोट का टारगेट निर्धारित किया है। इस टारगेट को किस तरह हासिल किया जाएगा, इसके लिए मप्र में फॉर्मूले का परीक्षण किया जा रहा है। इस फॉर्मूले के तहत प्रदेश में ओबीसी के बाद अब जनजातीय समुदाय पर फोकस किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेशभर में अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे भाजपा में संतोष की लहर देखी जा रही है। इसी संतोष को देखते हुए नवंबर माह में मप्र भाजपा के नेताओं को कई स्तरों पर परखा गया। परीक्षण के बाद केंद्र और राज्य के नेता रिपोर्ट तैयार कर आलाकमान को देंगे, जिसके आधार पर सरकार में आगामी समय में बदलाव किए जाएंगे।

51 फीसदी का टारगेट

मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा के नेताओं और विधायकों ने कार्यसमिति की बैठक में संकल्प लिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 51 फीसदी वोटशेयर के लिए आज से ही जुट जाएंगे। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अधिक वोट हासिल करने के बाद भी भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी, क्योंकि सीटों की संख्या कम थी। इसलिए पार्टी 2 साल पहले चुनावी मोड में आ गई है। इसके लिए जहां 24-25 नवंबर को भाजपा कार्यालय में सत्ता और संगठन में अपने 127 विधायकों से मैदानी फीडबैक लिया, वहीं 26 नवंबर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल सहित प्रदेश भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों की उपस्थिति में हुई कार्यसमिति की बैठक में जमकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की तारीफ की गई। मिंटो हॉल में आयोजित बैठक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आधारित थी, लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी योजनाओं की खूब तारीफ हुई। स्वागत भाषण में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राजगढ़ में आयोजित पिछली कार्यसमिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुमोदन करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान **संविधान दिवस** के मौके पर सभी पदाधिकारियों ने संविधान की शपथ ली और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया।

2023 में 200 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने के लिए भाजपा ने 51 फीसदी वोट पाने की कार्ययोजना बनाई है। इसके लिए पार्टी अभी से अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश भाजपा के प्रभारी पी मुरलीधर राव का कहना है कि वर्ष 2022 के अंत तक प्रदेश में भाजपा का वोट प्रतिशत 51 फीसदी करना है। यह पार्टी का नया लक्ष्य है। इसके लिए बूथ को पैमाना बनाया जाएगा। पार्टी का सीधा फॉर्मूला है कि हर बूथ पर मौजूदा वोट प्रतिशत में 10 फीसदी की वृद्धि करना है। इसके लिए सत्ता और संगठन मिलकर प्रयास करेंगे। जिस प्रकार किसी समय कांग्रेस का जनाधार था, उसी प्रकार अब पंचायत से संसद तक भाजपा ही रहेगी।

गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से अधिक सीटें जीती थीं, लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत उससे अधिक था। इसलिए पार्टी ने 2018 में मिले 41 फीसदी वोटों को 2023 में 51 फीसदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश भाजपा के प्रभारी पी मुरलीधर राव का कहना है कि इसके लिए पार्टी हर स्तर पर काम करेगी। उनका कहना है कि

कमिश्नर प्रणाली के जरिए पुलिस की नई शुरुआत

दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरह जल्द ही भोपाल और इंदौर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाने जा रही है। उप्र के चार शहरों लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में भी इसके लागू होने के बाद से आ रही सफलता की सूचनाओं ने मप्र सरकार को उत्साहित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। यही कारण है कि मप्र सरकार ने बिना देर लगाए प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निश्चय कर लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों पूर्व इसकी औपचारिक घोषणा कर संदेश दिया कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को उनकी सरकार प्राथमिकता से लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। शांति और सद्भाव है लेकिन हाल के दिनों कुछ नए तरह के अपराध सामने आए हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसी चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटने एवं जनता को बेहतर सेवा देने के लिए दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने जा रहे हैं। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री की घोषणा का यह कहकर स्वागत किया कि इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार होगा और बिना विलंब के जनता की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। माना जा रहा है कि भोपाल एवं इंदौर में यदि पुलिस कमिश्नर प्रणाली सफल होती है तो ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है। यह एक तथ्य है कि राज्य के अन्य शहरों की तुलना में भोपाल एवं इंदौर का विकास तेजी के साथ हो रहा है। हर साल बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों एवं छोटे शहरों से लोग इन शहरों में आ रहे हैं।

राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने मंत्रियों से लिया एक साल का हिसाब

मप्र में भाजपा अपने मंत्रियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के विवादित बयान को लेकर मचे बवाल के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, लेकिन बिसाहूलाल सहित विजय शाह, मीना सिंह, रामकिशोर कांवरे और प्रेम सिंह ठाकुर बैठक में नहीं पहुंचे। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से सवाल पूछा गया तो वे किनारा कर गए। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने शिवराज कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रियों के परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई। बैठक शुरू हुई तब 15 मंत्री ही मौजूद रहे। इसको लेकर संतोष ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। लेकिन आधे घंटे बाद लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे थे। जबकि उद्योग मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह दत्तीगांव भाजपा कार्यालय पहुंचे, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने मंत्रियों से कहा- कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, संगठन के लिए एक आम कार्यकर्ता ही है। संगठन और सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करें। संतोष ने मंत्रियों से पूछा- संगठन से आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं? इस पर कोई मंत्री खुलकर नहीं बोला, लेकिन संतोष ने साफ तौर पर कह दिया कि संगठन को मंत्रियों से जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें हर हाल में एक साल में पूरा करना है। उन्होंने हर मंत्री से उनके विभाग की उपलब्धियों की जानकारी भी ली।

प्रदेश में सरकार और संगठन में समन्वय बहुत अच्छा है। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बतौर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रभावी भूमिका निभाई है। हाल ही में उपचुनाव में पृथ्वीपुर और जोबट में भाजपा की जीत से यह बात स्थापित हो गई है कि पार्टी वहां भी मजबूत हो रही है, जहां वह पहले कमजोर थी। यह रेखांकित करने वाली जीत है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा ही राजनीति के दो ध्रुव हैं। पिछले करीब दो दशक से भाजपा सत्ता में है। अब हम नए लक्ष्य और योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संकल्प यह है कि अगले दो दशक भी प्रदेश में भाजपा का ही शासन रहेगा।

शिवराज को मिला फ्री हैंड

प्रदेश के उपचुनावों में 3-1 की जीत के बाद आलाकमान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फ्री हैंड दे दिया है। अब शिवराज के नेतृत्व में सत्ता और संगठन मिशन 2023 की तैयारी में जुटेंगे। साथ ही प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद भी शुरू होगी। दरअसल, आलाकमान की मंशा है कि शिवराज अपनी सुविधा और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से जमावट करे। इसलिए आलाकमान ने उन्हें पूरी तरह फ्री हैंड कर दिया है। जिस तरह दूध का जला मट्ठा फूंक-फूंककर पीता है, उसी तर्ज पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों मात खाई भाजपा अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। आलाकमान ने अबकी बार 200 के पार का लक्ष्य निर्धारित कर चुनावी रणनीति बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंपी है। अब मुख्यमंत्री उसके हिसाब से जमावट करेंगे। मप्र में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में 2 साल का समय बाकी हो, लेकिन भाजपा ने मिशन 2023 के लिए जमीनीं तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी का पूरा फोकस आदिवासी और ओबीसी वर्ग पर है। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए सरकार और संगठन ने कानूनी मोर्चा संभाल लिया है, वहीं कई विभागों की भर्ती परीक्षाओं में 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है। वहीं अब पार्टी प्रदेश की 2 करोड़ आबादी को साधने में जुटी हुई है। राज्य में 43 समूहों वाली आदिवासी आबादी 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस समुदाय ने भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। पार्टी अब वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है।

बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन बहुमत के आंकड़े 7 सीटे (116 में से 109) कम मिली थीं। जबकि कांग्रेस को 40 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन सीटें 114 मिली थीं और कांग्रेस ने बीएसपी के समर्थन से सरकार बना ली थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर ऐतिहासिक काम किया है। आदिवासी वोट बैंक को साधे रखने की रणनीति के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह की तारीफ की। शर्मा ने कहा- प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जनजातीय दिवस मनाने का ऐलान कर इस वर्ग की वर्षों से की जा रही उपेक्षा को दूर किया। प्रदेश में गौरव दिवस की शुरूआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की। जिनको आज सरदार पटेल की भूमिका में देखते हैं।

वीडी शर्मा ने कहा कि जब प्रदेश में कोरोना दस्तक दे रहा था, तब कांगेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत से काम किया। उन्होंने संकट की घड़ी में 24 घंटे पलक पावड़े बिछाकर काम किया। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री कोई था, निर्णय कोई और लेता था। फिर जब भाजपा की सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान पर प्रहार करने की कोशिश की गई। उपचुनाव चुनौतीपूर्ण थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इमोशनली नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर सरकार को बचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में चुनौती को स्वीकार किया और सरकार ने बहुमत साबित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुंडों को बढ़ावा दे रही है।

कांग्रेस के भ्रम को तोड़ा शिवराज ने

कोरोना के बाद पहली बार प्रत्यक्ष रूप से हुई भाजपा कार्यसमिति की बैठक में वीडी शर्मा ने कहा है कि मप्र के कार्यकर्ताओं ने देशभर में आइडियल कार्यकर्ता बनने का काम किया है। कोरोना में जब कांग्रेस और अन्य दलों के लोग घरों में बैठे थे तब हमारे मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता फील्ड में डटे थे। कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने तक का काम किया। आदिवासी क्षेत्रों में कहते थे कि वैक्सीन लगवाओगे तो जाने

क्या हो जाएगा लेकिन यही वैक्सीन आज लोगों की जीवन रक्षक बनकर सामने आई है। कोरोनाकाल में हर कार्यकर्ता ने काम किया है। मजदूरों की सेवा की, उनका ख्याल रखा गया था। ऐसे संकट के समय में भी हमारी सरकार ने 18 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में जीत हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।

हर अभियान में आगे रहे कार्यकर्ता

शर्मा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन, रेमडेसिवर, डॉक्टर्स सहित अन्य चीजों की समस्याएं आ रही थीं, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशभर में डॉक्टर्स और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की चेन खड़ी करने की बात कही। उनके आव्हान पर कदम बढ़ाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कीर्तिमान रच दिया और हर गांव में प्रशिक्षित स्वास्थ्य स्वयंसेवक तथा हर ब्लॉक में डॉक्टर्स की श्रृंखला तैयार कर दी। संकट के दौरान हर गरीब को पेट भर भोजन उपलब्ध कराने के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करते हुए अन्न उत्सवों का आयोजन किया और एक दिन में 25 लाख लोगों को अन्न वितरण का रिकॉर्ड बना दिया। आपसी समन्वय के साथ किस तरह गरीब कल्याण और सेवा के काम किए जाते हैं, यह हमारी प्रदेश सरकार और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीखा जा सकता है।

शर्मा ने कहा कि हमारी केंद्र और राज्य सरकारें अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ हमारी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला जैसी योजनाओं से जीवन स्तर उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार लोगों की सोच बदल रही है। प्रदेश में हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही लाड़ली लक्ष्मी, बेटी बचाओ जैसी योजनाएं शुरू की थीं। आज प्रदेश में 35 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन गई हैं। जिन बेटियों को कभी अभिशाप समझा जाता था, वो अब वरदान बन गई है। प्रदेश में पहले जहां 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं होती थीं, वहीं अब 1000 पुरुषों पर 956 महिलाएं हैं। यह हमारी सरकारों की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का अभिनंदन करता हूं।

छलका विधायकों का दर्द

करीब 2 साल बाद मिंटो हाल में संपन्न हुई प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में जहां एक तरफ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ में कसीदे गढ़े, वहीं दूसरी तरफ विधायकों का एक बार फिर दर्द छलका। विधायकों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा कि हमें अगली बार 200 पार का टारगेट दिया गया है, लेकिन मंत्री और अफसर हमारी सुनते नहीं हैं, तो हम कैसे काम करेंगे। सूत्र बताते हैं कि विधायकों के इस दर्द को राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव का भी समर्थन मिला।

गौरतलब है कि कार्यसमिति की बैठक से पहले दो दिनों तक प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश भाजपा के 127 विधायकों में से करीब 82 विधायकों ने संगठन के सामने मंत्रियों और अफसरों की अनदेखी की शिकायत की। पार्टी सूत्रों के अनुसार वन-टू-वन चर्चा में ग्वालियर-चंबल, रीवा, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, शहडोल के अधिकांश विधायकों ने कहा कि अफसर हमें बिलकुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। जिलों में जहां कलेक्टर और एसपी हमें नजरअंदाज करते हैं, वहीं विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी सुनते तक नहीं हैं। ऐसे में काम करना मुश्किल हो रहा है।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उनके विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी ही उनकी नहीं सुनते। कांग्रेस से आकर भाजपा में मंत्री बने एक नेता ने तो कहा कि वे जो भी प्रस्ताव विभाग के पास भेजते हैं उस पर अफसर काम ही नहीं करते। वे कहते हैं कि हमने तो इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। दो दिन की वन-टू-वन और कार्यसमिति के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव एक-दो दिन में

कलेक्टर-एसपी के काम पर निर्भर है जनता को सुशासन देना

प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर, आईजी-पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस में अफसरों से कहा कि मप्र में ऐसे सभी एनजीओ को चिन्हित करें, जिन्हें फॉरेन फंडिंग (विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद) हो रही है। यह भी पता लगाएं कि इस फंड का कहां और क्या उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैमनस्य फैलाने, समाज को तोड़ने का काम करने वाले और धर्मांतरण करने वाले एनजीओ के लिए मप्र में जगह नहीं है। उन्हें हम यहां रहने नहीं देंगे। समाज को तोड़ने में कई एनजीओ का भी हाथ है। ऐसे संगठनों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इनसे जुड़े लोगों की सूची बनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमिश्नर-कलेक्टर, आईजी-एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने अब सुशासन के लिए एक निश्चित व्यवस्था का स्वरूप धारण कर लिया है। यह सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी है। कॉन्फ्रेंस का निश्चित एजेंडा है, उस पर बिंदुवार चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर विचार-विमर्श किया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के संबंध में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान बताया गया कि नक्सलियों ने कान्हा पार्क के आसपास नया ठिकाना बना लिया है। इंटेलीजेंस इनपुट के आधार पर बताया गया कि जनवरी 2021 में परसवाड़ा, दोरा और छरेगांव में नए दलम (नक्सली) के एक नए ग्रुप की मौजूदगी देखी जा रही है। इस तरह 30 नक्सलियों का नया ग्रुप कान्हा नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में बनाया गया है।

रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। बताया जाता है कि दोनों नेता सरकार और संगठन दोनों के कार्य से नाखुश हैं। वे सरकार और संगठन की रिपोर्ट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे।

'नकारा' मंत्री होंगे बाहर

उपचुनाव निपटने के साथ भाजपा विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुट गई है। सत्ता और संगठन के चुनावी मोड में आते ही राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि दिसंबर में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। विस्तार को प्रदेश कार्यसमिति में हरी झंडी दिखाई जाएगी। भाजपा सूत्रों को कहना है कि परफॉर्मेंस के आधार पर 8 से 10 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं मंत्रियों का विभाग भी बदला जाएगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार के करीब एक दर्जन से अधिक मंत्रियों की **परफॉर्मेंस संतोषजनक** नहीं पाई गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में फेरबदल बड़े स्तर पर होगा और नकारा मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

प्रदेश में आम विधानसभा चुनाव होने में अभी भले ही दो साल का समय है, इसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी से चुनावी मोड में आते दिखने लगे हैं। यही वजह है कि उनके इस मोड में बाधा बनने वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। दरअसल सरकार नहीं चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति वर्ष 2018 के चुनाव परिणामों की तरह रहे। इसके लिए सरकार अब अपना पूरा ध्यान विकास और जनकल्याणकारी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने पर लगा रही है। इसके माध्यम से सरकार की मंशा उसके खिलाफ कोरोनाकाल में बनी एंटी इनकंबेंसी को दूर करना है। यही वजह है कि प्रदेश में भी राज्य सरकार केंद्र की तरह

तमाम समीकरणों को साधने के लिए राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की तैयारी कर रही है। इस पुनर्गठन के पहले मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई है। जिसमें कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस पुअर पाई गई है।

मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बनने की खबर सामने आते ही प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों अजब सी हलचल मची हुई है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के मौजूदा 30 मंत्रियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तैयार करवाई गई है। रिपोर्ट कार्ड तैयार होने की खबर मिलते ही उन मंत्रियों के होश उड़ गए हैं, जो अभी तक अपना टास्क पूरा करने में पिछड़े हैं।

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में करीब आधे से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं, जो अपने विभागीय काम के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। उनमें से करीब एक दर्जन से अधिक तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति दयनीय है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री बारीकी से एक-एक पॉइंट पर नजर रखे हुए हैं। विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्रियों के सामने उनका रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। उसके बाद यह रिपोर्ट कार्ड पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाएगा। आगे चलकर जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो इस रिपोर्ट कार्ड को आधार बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी में मुख्यमंत्री के सामने कैबिनेट विस्तार को लेकर नामों को लेकर उलझन जारी है। प्रदेश सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट में कुल 31 सदस्य हैं। जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या 35 हो सकती है। फिलहाल कुल चार पद खाली हैं, जिसके लिए टकटकी लगाने वालों में शिवराज के पूर्व मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ नेता भी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार की योजना बनाई है। यानी जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब होगी उनका मंत्रिमंडल से बाहर जाना तय है। इसके अलावा पार्टी नेताओं से भी मंत्रियों के कामकाज के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है।

दरअसल कुछ मंत्री ऐसे हैं, जिनकी अब तक न तो विभाग पर ही पकड़ बन पाई और न ही उनके कामकाज से संगठन से लेकर कार्यकर्ता तक खुश है। माना जा रहा है कि इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जाएगा। इसके पहले इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री और प्रमुख सचिव में विवाद के कारण सरकार की नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसी कारण मुख्यमंत्री के साथ संगठन स्तर पर भी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।

15:25:50 फॉर्मूले पर सभी 150 आईपीएस पास

आम जनता के लिए भले ही प्रदेश की व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अनाचार आदि समाहित हैं, लेकिन सरकार की नजर में उसके अधिकारी पाक साफ हैं। विगत दिनों मप्र कैडर के 150 से अधिक आईपीएस अफसरों के कामकाज का आंकलन करने वाली छानबीन समिति की बैठक में 15:25:50 फॉर्मूले से आईपीएस अधिकारियों का परीक्षण किया गया। मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार जिन अफसरों ने सर्विस के 15 साल पूरे कर लिए हैं, समिति उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। इसके साथ ही जिन अफसरों ने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है और उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है, इनका भी रिकॉर्ड चेक किया गया। उसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रदेश में एक भी आईपीएस अधिकारी नकारा नहीं है। गौरतलब है कि आईपीएस अफसरों की जांच-पड़ताल के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए (15:25:50) फॉर्मूला लागू किया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति बनाई गई है। समिति में डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास अशोक शाह और छत्तीसगढ़ के डीजी प्रबंधन आरके विज सदस्य हैं। इन सदस्यों ने प्रदेश के 150 आईपीएस अधिकारियों का सर्विस रिकार्ड चेक किया। जिसमें पाया गया कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ गंभीर मामले नहीं हैं। अब यह समिति सिफारिश केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजेगी।

जानलेवा लॉकडाउन

देश में आत्महत्याएं करने की संख्या बढ़ रही है। एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट में जो इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात है वह यह कि कोरोनाकाल में हुई तालाबंदी के दौरान देशभर में आत्महत्याओं का ग्राफ सीधे 10 फीसदी बढ़ गया है। दूसरी चिंताजनक बात यह है कि सन् 1967 के बाद सन् 2020 में आत्महत्याओं के सबसे अधिक मामले हुए हैं। अच्छे दिन वाले देश में सन् 2020 में हर रोज 418 लोगों ने आत्महत्या कर ली। चिंताजनक पहलू यह भी है कि आत्महत्या करने वालों में ज्यादातर छात्र और छोटे उद्यमी हैं। जाहिर है अनियोजित तालाबंदी के नुकसान के गंभीर नतीजे अब धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट पूरे साल की घटनाओं पर आधारित है। यह वह कालखंड है जब देश में लंबे और अनियोजित तालाबंदी के कारण लाखों छोटे उद्योग-धंधे चौपट हो गए और करोड़ों लोग रोजगार से हाथ धो बैठे। इनमें से ज्यादातर को अभी तक दोबारा रोजगार नहीं मिल पाया है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट-2020 के जनवरी से दिसंबर तक में हुई घटनाओं पर आधारित है। रिपोर्ट कहती है कि एक साल में आत्महत्या के कुल 1,53,052 मामले सामने आए। पिछले 53 साल में आत्महत्याओं का यह आंकड़ा सबसे बड़ा हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चौंकाने वाले आंकड़े कहते हैं कि 2019 के मुकाबले 2020 में व्यापारियों की आत्महत्याओं की संख्या चिंताजनक 50 फीसदी ज्यादा हो गई। आत्महत्याओं की किसी भी श्रेणी में यह सबसे बड़ा उछाल है। देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़ गई। आंकड़ों के मुताबिक, देश में 2020 में प्रति लाख आबादी पर आत्महत्या संख्या 2019 के मुकाबले 10.4 फीसदी से बढ़कर 11.3 फीसदी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में देश में हर रोज 418 लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली।

महामारी ने 2020 में जमीन पर जिंदगियां तो लील ही लीं, करोड़ों जिंदा लोगों के सामने दो जून की रोटी का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तबाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 की तुलना में 2020 में आत्महत्या करने वालों में किसानों से अधिक व्यापारी रहे। साल 2020 में महामारी के कारण आर्थिक संकट के काले काल के दौरान व्यापारियों की हत्या बताती है कि सरकार लोगों के रोजगार को नाकाम रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 के एक ही साल में 10,677 किसानों की तुलना में 11,716 छोटे-बड़े व्यापारियों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इन 11,716 मौतों में आत्महत्या करने वाले 4,356 ट्रेड्समैन थे और 4,226 वेंडर्स यानी विक्रेता थे। बाकी मरने वाले लोगों को अन्य व्यवसायों की श्रेणी में रखा गया है। ये तीन समूह हैं, जिन्हें एनसीआरबी आत्महत्या रिकॉर्ड करते समय व्यापारिक समुदाय के रूप में मानता है। सन् 2019 की तुलना में 2020 में कारोबारी समुदाय के बीच आत्महत्या के मामलों में 29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस बीच व्यापारियों के बीच आत्महत्या 49.9 फीसदी की उछाल के साथ 2019 में 2,906 से बढ़कर 2020 में 4,356 हो गई।

हाल के दशकों में किसानों ने देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। यह व्यापारिक समुदाय से कहीं कम थी। आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि व्यापारी कोरोना महामारी और तालाबंदी के बाद पैदा हुए घोर आर्थिक संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में उन्हें तनाव या डिप्रेशन झेलना पड़ा। जानकारों के मुताबिक, तालाबंदी के दौरान छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है और इनमें से कई अपने धंधे समेटने को मजबूर हो गए।

तमाम सरकारी दावों के बावजूद देश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। एनसीआरबी के आंकड़े जाहिर करते हैं कि सन् 2020 में 2019 की अपेक्षा किसानों (किसान और कृषि मजदूर) की आत्महत्याओं के मामले लगभग 4 फीसदी बढ़े हैं। यही नहीं देश में कृषि मजदूरों की आत्महत्या के मामले 18 फीसदी बढ़े हैं। वैसे राज्यों की बात करें, तो महाराष्ट्र 4,006 आत्महत्याओं के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद कर्नाटक में 2,016, आंध्र प्रदेश में 889, मप्र में 735 और छत्तीसगढ़ में 537 कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि किसानों और कृषि मजदूरों में आत्महत्या के मामले रुकने की जगह बढ़ रहे हैं।

देश में सन् 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में 10,677 लोगों की आत्महत्या की जो देश में कुल आत्महत्याओं (1,53,052) का 7 फीसदी है। इसमें 5,579 किसान और 5,098 खेतिहर मजदूरों की आत्महत्याएं दर्ज हैं। वैसे 2016 से 2019 के बीच चार साल तक इन आत्महत्याओं में गिरावट दर्ज होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। सन् 2016 में कुल 11,379 किसान और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2017 में इसमें गिरावट आई और संख्या 10,655 रह गई। सन् 2018 में 10,349 तो 2019 में इस तरह के आत्महत्या के कुल 10,281 मामले सामने आए थे, जबकि सन् 2020 में यह मामले 10,677 हो गए।

● **कुमार विनोद**

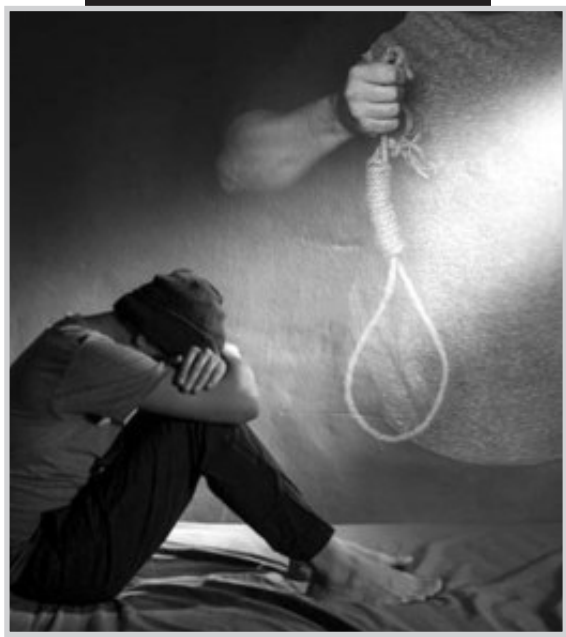

तालाबंदी के दौरान अवसाद बढ़ा

करीब 68 दिन के पहले सबसे लंबे तालाबंदी ने देश की निचली आबादी की कमर तोड़कर रख दी। लोगों में इस दौरान अवसाद बढ़ गया और आत्महत्या के मामलों में आश्चर्यजनक उछाल देखने को मिला। रिपोर्ट से यह भी जाहिर होता है कि तालाबंदी में सबसे अधिक प्रभावित वे छात्र भी रहे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। इनमें से कई ऐसे थे, जिनके कैरियर की उम्र खत्म हो रही थी और वही सबसे ज्यादा अवसाद की चपेट में आए। इस दौरान न तो स्कूल-कॉलेज खोले गए और न ही दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट जाहिर करती है कि भारत में अभी भी 2.9 करोड़ छात्रों के पास डिजिटल उपकरणों की पहुंच नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने के लिए संसाधनों का उपयोग करने में असमर्थता के कारण छात्रों के आत्महत्या करने की कई रिपोर्ट्स आई हैं। उधर छोटे उद्यमी, जिन्होंने बैंक कर्ज और अन्य माध्यमों से उद्यम शुरू किया था, तालाबंदी में उनका कामकाज चौपट हो गया। कर्ज का बोझ ऊपर से आर्थिक तंगी। नतीजे में कई उद्यमियों ने आत्महत्या का रास्ता अपना लिया। विशेषज्ञों के मुताबिक, तालाबंदी तनाव का सबसे बड़ा जरिया बना।

पश्चिम बंगाल के बाद उपचुनावों में भाजपा को आशातीत सफलता नहीं मिली है। ऐसे में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव भाजपा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं हैं। वहीं कांग्रेस, आप, टीएमसी, सपा, बसपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां भाजपा के खिलाफ सक्रिय हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि चुनाव आक्रामक और रोचक होगा।

पांच राज्यों का घमासान

अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों उप्र, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनावी घमासान शुरू होगा। लेकिन भाजपा के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं। इसलिए भाजपा में सबसे अधिक सक्रियता और चिंता देखी जा रही है। नवंबर के पहले रविवार को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य रूप से अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक की खास बात यह रही कि राजनीतिक संकल्प पत्र उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया, जो पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते थे। इसने भाजपा के भी अनेक नेताओं को चौंकाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इसमें इस बात का खास तौर से जिक्र किया गया है कि 'पार्टी अगले विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करेगी।' उप्र के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। महंगाई, बेरोजगारी और कृषि कानून जैसे मुद्दों के बीच पंजाब में भाजपा ने सभी 117 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। चंद महीने पहले तक कांग्रेस के लिए आसान दिखने वाले पंजाब में माहौल अस्थिर है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के रूठने-मनाने का दौर जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस को दलित और पिछड़े वर्ग में फायदा मिलता तो दिख रहा है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद पार्टी में कोई बड़ा जट्ट सिख चेहरा नहीं है। अमरिंदर खुद कांग्रेस को चुनौती देने के लिए कमर कस रहे हैं।

योगी के संकल्प पत्र पेश करने के कई मायने हैं। भाजपा जानती है कि 2024 में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने के लिए 2022 में उप्र जीतना जरूरी है। पिछले दिनों प्रदेश में सरकार विरोधी माहौल बनने के बावजूद पार्टी को लगता है कि सफलता वही दिला सकते हैं। पिछले आम चुनाव में उन्होंने प्रदेश की 80 सीटों में से 64 सीटें दिलाई थीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से हफ्ताभर पहले गृहमंत्री अमित शाह भी उप्र और योगी का महत्व बता चुके थे। लखनऊ में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था, 'मैं उप्र की जनता को बताने आया हूं कि मोदीजी को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में फिर एक बार योगीजी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा।' भाषण के अंत में उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, 'मोदीजी को एक और मौका दे दीजिए, योगीजी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए।' शाह के इन शब्दों से यह सवाल उठा कि क्या भाजपा को अपनी स्थिति कमजोर होती दिख रही है, इसलिए 'पार्टी के चाणक्य' को इस तरह अपील करनी पड़ रही है?

तमाम विश्लेषणों में भाजपा भले उप्र में अभी लाभ की स्थिति में दिख रही हो, लेकिन इस बार मुकाबला 2017 जैसा नहीं रहने वाला। पिछली बार 403 सीटों में से भाजपा ने 312 (सहयोगी दलों समेत 325) पर जीत दर्ज की थी। सपा 47, बसपा 19 और कांग्रेस सिर्फ सात पर सिमट गई थी। इस बार सत्तारूढ़ दल को सबसे बड़ी चुनौती सपा से ही मिलती दिख रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़े ही रणनीतिक तरीके से चालें चल रहे हैं। पूर्वी इलाके में पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने भाजपा के पूर्व सहयोगी ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के साथ गठबंधन किया है, तो पश्चिमी उप्र में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है जिन्होंने हाल ही 'आशीर्वाद पदयात्रा' की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष शाह ने मऊ में राजभर के साथ रैली की थी, इस बार अखिलेश ने राजभर के साथ रैली की है। राजभर जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश की आबादी में वह तीन से चार फीसदी है। प्रदेश स्तर पर यह आंकड़ा भले कम हो लेकिन ज्यादातर लोग पूर्वी इलाके में ही हैं। पार्टी का आधार सिर्फ राजभर समुदाय में नहीं बल्कि चौहान, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, मल्लाह जैसे दूसरे अति पिछड़ा वर्ग में भी है। पूर्वी उप्र के 18 जिलों में 90 सीटें हैं। इनमें से 25-30 सीटों पर राजभर बड़ी संख्या में हैं। पूर्वी उप्र में 2017 में भाजपा की सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 72 हो गई तो समाजवादी पार्टी की 52 से घटकर 9 रह गई थी। राजभर

गोवा, उत्तराखंड में एंटी-इनकंबेंसी

महज 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा के लिए 8 पार्टियां मैदान में हैं। इस तटीय राज्य में तृणमूल कांग्रेस तो पहली बार चुनाव लड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी दूसरी बार यहां प्रयास कर रही है। वैसे मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। 2017 में भाजपा को 13 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं लेकिन दूसरे दलों और निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर भाजपा ने सरकार बना ली थी। 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक टूटकर भाजपा में चले गए थे। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गिरीश चोडणकर के अनुसार पिछली बार भी लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन भाजपा ने जिस तरह जनमत चुराया उसे देखते हुए लोग इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिलवाएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता लुइजिन्हो फलेरियो और टेनिस स्टार लिएंडर पेस को पार्टी में शामिल किया है। तृणमूल को ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन वह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस को नुकसान आप से भी हो सकता है, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है।

जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं जिसका अखिलेश ने वादा किया है।

राजभर समुदाय के दो और बड़े नेता भी अखिलेश के साथ हैं- पूर्व बसपा नेता रामअचल राजभर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के बेटे कमलकांत। रामअचल और वरिष्ठ बसपा नेता लालजी वर्मा हाल ही अंबेडकर नगर रैली में सपा में शामिल हुए। बसपा के छह निलंबित विधायक और भाजपा के सीतापुर से बागी विधायक राकेश राठौड़ भी सपा में शामिल हुए हैं। मायावती ने अक्टूबर 2020 में राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी रामजी गौतम का विरोध करने की वजह से इन विधायकों को निलंबित किया था। राठौड़ ने महामारी के समय लोगों से घंटियां और तालियां बजाने की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। जिस दिन मऊ में अखिलेश यादव एसबीएसपी की रैली में गए, उसी दिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में दावा किया कि पूर्वांचल में पिछड़े वर्ग की सात छोटी पार्टियां उनके साथ हैं। भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में चार सदस्यों की समिति बनाई है। यह दूसरे दलों के उन नेताओं की पहचान करेगी जो हाशिए पर हैं और बेहतर राजनीतिक प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। पार्टी ने लालजी वर्मा, रामअचल राजभर जैसे नेताओं के सपा में जाने को गंभीरता से लिया है। उसे लगता है कि ये नेता उसके लिए काफी उपयोगी हो सकते थे। पार्टी इस बात से भी चिंतित है कि गैर-यादव ओबीसी अब भाजपा के बजाय सपा को तरजीह दे रहे हैं, जबकि भाजपा को ओबीसी में बड़े जनाधार वाली पार्टी माना जाता है।

रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कहते हैं, 'भाजपा तालिबान और पाकिस्तान की बात कहती है, लेकिन असली मुद्दे बेरोजगारी महंगाई और किसानी की बदहाली है। उनके मुद्दों का जवाब देने के बजाय हम असली मुद्दे उठाते रहेंगे।' उनकी पार्टी को 2017 में सिर्फ एक सीट मिली थी। पार्टी ने घोषणा पत्र भी जारी किया है जिसमें महिलाओं को नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण और सत्ता में आने के बाद 6 महीने के भीतर एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात है। किसानों को हर साल किसान दिवस पर 12 हजार रुपए देने का वादा भी किया गया है। जयंत चौधरी को साथ लेने के बाद अखिलेश ने कहा कि नेताजी (मुलायम सिंह) के जन्मदिन पर 22 नवंबर को चाचा शिवपाल सिंह को साथ लाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश के सपा अध्यक्ष बनने पर शिवपाल ने 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नाम से अलग पार्टी बना ली थी।

राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत टंडन कहते हैं, 'प्रदेश में लखीमपुर खीरी एक नया क्षेत्र उभरा है। इसमें 42 सीटें आती हैं जिनमें पिछली बार 37 भाजपा को मिली थीं। उप्र के 15 फीसदी सिख यहीं रहते हैं। यहां के सिख मजबूत हैं और दूसरों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। टंडन कहते हैं, '2014 से 2017 के दौरान प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे 28 फीसदी बढ़े थे जिसका असर 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखा था, लेकिन इस बार वैसी कोई बात नहीं है।' शायद इसलिए ध्रुवीकरण की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर कहा कि पहले सरकारी पैसा कब्रिस्तान पर खर्च होता था, अब मंदिरों पर खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले 19 फरवरी 2017 को फतेहपुर में 'कब्रिस्तान बनाम श्मशान' की बात कही थी। अखिलेश ने भी पटेल जयंती पर हरदोई में आयोजित जनसभा में पटेल, गांधी और नेहरू के साथ जिन्ना का नाम लेते हुए कहा कि वे एक ही संस्थान में पढ़कर बैरिस्टर बने और हमें आजादी दिलाई। योगी समेत कई भाजपा नेता इसकी आलोचना कर चुके हैं। प्रदेश का सघन दौरा करने वाले टंडन के अनुसार, 'इस बार मुस्लिम वोटर शायद मायावती के साथ न जाएं। मुसलमानों को लगता है कि अगर भाजपा की सीटें कम हुईं तो सरकार बनाने के लिए मायावती उसका समर्थन कर सकती हैं।'

प्रदेश में 86 सुरक्षित सीटें हैं, जिनमें 76 पर भाजपा जीती थी। वहां के सवर्ण मतदाता भाजपा के दलित उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। दूसरी पार्टियां इसकी काट के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। पिछली बार 54 सीटों पर हार-जीत 5 हजार से कम वोटों के अंतर से हुई थी। भाजपा ने ऐसी 20 सीटें जीती थीं। पार्टियां इन सीटों पर भी फोकस कर रही हैं। विश्लेषक इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ने का भी अनुमान लगा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रमुख अजय लल्लू खुद ओबीसी से आते हैं, उन्होंने जिला स्तर पर ओबीसी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

● रजनीकांत पारे

लिएंडर भी हुए टीएमसी के

उत्तराखंड में भी सत्तारूढ़ भाजपा को एंटी-इनकंबेंसी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मार्च से अब तक पार्टी तीन मुख्यमंत्री बदल चुकी है। ध्रुवीकरण की कोशिश यहां भी है। देहरादून में प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस के शासन में लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर वहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती थी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक खोने के डर से केदारनाथ में पुनर्विकास कार्य नहीं किए। यहां चुनाव पर ध्यान देने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पिछले दिनों पंजाब प्रभारी का पद छोड़ा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुश्किल पार्टी के भीतर मची खींचतान है। शाह ने उनके 2016 के स्टिंग का भी मुद्दा उठाया जिसमें विश्वास मत पर मतदान के लिए कुछ बाकी कांग्रेस विधायकों को तथाकथित रूप से रिश्वत देने की बात थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने से तराई इलाकों में पार्टी को लाभ मिल सकता है। लेकिन पार्टी में आर्य का विरोध भी हो रहा है। तराई इलाकों में किसान भी भाजपा से नाराज हैं। उसे सिख बहुल ऊधमसिंह नगर में लखीमपुर कांड का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पांचों राज्यों में चुनाव होने में अभी दो महीने से ज्यादा का समय बाकी है। इतना समय किसी भी रुख को बदलने के लिए काफी हो सकता है। देखना है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं का रुख क्या रहता है।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून वापसी विधेयक लोकसभा में पास हो गया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान मार लिया है या फिर कृषि कानून वापस लेकर उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। गौरतलब है कि किसानों ने ऐलान किया है कि एमएसपी कानून बनने के बाद ही वे दिल्ली बॉर्डर से वापस जाएंगे। ऐसे में मामला सुलझने की बजाय और उलझता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आगामी दिनों में सरकार इस मामले से कैसे निपटती है।

क्या मोदी ने मार लिया मैदान...?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की तो आम प्रतिक्रिया थी कि सच हार गया और झूठ जीत गया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई विशेषज्ञ समिति के सदस्य अनिल घनवट की मानें तो सच को हराने में जाने-अनजाने अदालत का रवैया भी सहायक बना। अब सवाल है कि यह आखिरकार हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक दूसरे प्रश्न के उत्तर पर गौर करना होगा। सवाल है कि सरकार के सामने क्या कोई और विकल्प था? जो गतिरोध बना हुआ था, उसका फायदा किसे मिल रहा था?

'आंख के अंधे नाम नयनसुख' वालों को छोड़ दें तो पूरे देश में बहुमत इस पर सहमत था और है कि तीन कृषि कानून किसान, कृषि और देश की अर्थव्यवस्था के हित में थे। तो पहले बात करते हैं कि सरकार के सामने क्या कोई और भी विकल्प था? तीनों कृषि कानूनों का मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सर्वोच्च अदालत ने क्रांतिकारी काम किया। कानूनों की संवैधानिक वैधता जांचे बिना उनके अमल पर रोक लगा दी। उसी समय एटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चेताया था कि गलत परंपरा डाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पंचाट नहीं है। वह संवैधानिक अदालत है। उसे अपने अधिकार के दायरे में ही रहकर काम करना चाहिए, पर अदालत ने तय किया कि वह कानून की वैधता जांचे बिना ऐसा करेगी। उसने किसान संगठनों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, पर वे नहीं गए। अदालत ने विशेषज्ञों की कमेटी बनाई। किसानों ने उसके सामने जाने से भी मना कर दिया। कमेटी ने आठ महीने पहले रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन अदालत को उस पर सुनवाई करना या उसे सार्वजनिक करना जरूरी नहीं लगा। अनिल घनवट को बोलना पड़ा कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जातीं।

संयुक्त किसान मोर्चे के नेता सरकार से 11 दौर की बातचीत में स्पष्ट संकेत दे चुके थे कि समस्या के समाधान में उनकी कोई रुचि नहीं है। तीनों कृषि कानूनों पर सबसे खतरनाक खेल पंजाब में खेला गया। सिखों और खासतौर से जट सिखों के मन में बैठा दिया गया कि ये कानून उन्हें बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं। आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में मदद करके सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इसे हवा ही दी। फिर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों में बैठे खालिस्तानी तत्वों ने पूरी ताकत लगा दी। पिछले सात साल से मोदी से मात खा रहे

लोकतंत्र में सही फैसले लेना और उन्हें लागू करना कठिन होता है...

सरकारों ने पहले भी अपने फैसले वापस लिए हैं, लेकिन यह शायद पहली बार है जब कोई सरकार किसी फैसले को सही बताने के बाद भी उसे वापस लेने को विवश हुई हो। कृषि कानूनों की वापसी ने फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सही फैसले लेना और उन्हें लागू करना कठिन होता है। इस मामले में नरसिंह राव से सबक लेने की जरूरत है। वह अपनी राजनीतिक चतुराई से कहीं अधिक कठिन फैसले लेने में समर्थ रहे और वह भी तब, जब अल्पमत सरकार चला रहे थे। आज यह कहना आसान है कि यदि मोदी सरकार ने संसद के भीतर-बाहर व्यापक विचार-विमर्श के बाद कृषि कानून बनाए होते तो शायद नतीजे दूसरे होते, लेकिन इसकी चर्चा करते हुए इस पर भी बहस होनी चाहिए कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने जो किया, वह कितना सही है? कांग्रेस वैसे ही कानूनों के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई, जैसे कानून बनाने का वादा उसने अपने घोषणापत्र में किया था। इन कानूनों में आवश्यक संशोधन-परिवर्तन कर उन्हें बचाया जाना चाहिए था। यदि कृषि कानून नहीं बचाए जा सके तो यह अफसोस की बात है। इन कानूनों की वापसी की घोषणा पर खुशी जताना एक तरह से खेती और किसानों की बर्बादी का जश्न मनाना है। अब किसानों की मुश्किलें और अधिक बढ़ना तय है। किसी को भी अपना उत्पाद अपनी मर्जी से बेचने न देना एक प्रकार से उसे गुलाम बनाए रखना है।

विपक्षी दलों को किसान यूनियन के नेताओं में अपना तारणहार नजर आया। उनके लिए यह यूरेका-यूरेका (मिल गया-मिल गया) वाला पल था। सारे मोदी विरोधी राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्व आंख बंद करके इस आंदोलन के पीछे खड़े हो गए।

जिनके हित के लिए ये कानून बनाए गए, वे खामोश थे। हिंसक अल्पसंख्या खामोश बहुसंख्या पर भारी पड़ी। 80 फीसदी से ज्यादा छोटे-मझोले किसानों के हित के लिए यह कानून बनाया गया था, पर सरकार को साफ नजर आ रहा था कि जिन लोगों के हित के लिए यह कानून बना है, उन्हें इसका फायदा तो तब मिलेगा जब ये कानून लागू होंगे। इसके लिए न तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता तैयार थे और न ही सुप्रीम कोर्ट। जब तक मामला अदालत में है, तब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में कुछ कर ही नहीं सकती थी। लागू कर पाए बिना इनके राजनीतिक विरोध को सरकार रोज-रोज डेल रही थी। जिस प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में सबसे ज्यादा काम किया, उसकी छवि किसान विरोधी बनाने की कोशिश हो रही थी। उन्हें असंवेदनशील बताया जा रहा था। पंजाब में भाजपा के नेता घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हरियाणा में मुख्यमंत्री तक को अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाने दिया जा रहा था। पश्चिमी उप्र में भाजपा को बड़े चुनावी नुकसान की फर्जी खबरें चलाई जा रही थीं।

ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने कानून वापस लेने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। कानून वापस लेकर मोदी ने अपने विरोधियों और समर्थकों, दोनों को चौंका दिया। समर्थकों को इस घोषणा को पचाने में दिक्कत हो रही है तो विरोधी निहत्थे हो गए हैं। मोदी की इस एक घोषणा से पूरे विपक्ष की हवा निकल गई। जिस मुद्दे को ब्रह्मास्त्र की तरह लिए घूम रहे थे, वह मुद्दा ही खत्म हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कुछ और मुद्दों को लेकर आंदोलन को चलाते रहने की घोषणा, थूक लगाकर चूहे को जिंदा रखने की कहावत चरितार्थ करने जैसी है। किसान संगठनों के नेता कुछ भी कहें कि एमएसपी की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन सच यह है कि किसान आंदोलन तीन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ था और उनकी वापसी के साथ इसका औचित्य भी खत्म हो गया। अभी तक हठधर्मी का जो आरोप किसान यूनियन प्रधानमंत्री पर लगा रही थीं, वह खुद उन पर चस्पा हो गया है। कहते हैं कि कोई चीज जब पास होती है तो उसका महत्व समझ नहीं आता, पर जब चली जाए तो उसकी कमी खलती है। तीनों कृषि कानूनों के साथ यही हो रहा है। देशभर से कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इन कानूनों के वापस होने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। शेतकारी संगठन के अनिल घनवट कह रहे हैं कि उनका संगठन जल्द ही इन कानूनों की वापसी की मांग लेकर एक लाख किसानों को दिल्ली लेकर आएगा। यह तो पता नहीं कि संयुक्त किसान मोर्चे की एमएसपी की ताजा मांग का सरकार पर क्या असर होगा, लेकिन जिस किसी को भी भारतीय कृषि और किसानों की चिंता है, वे सब लोग किसानों की इस मांग से भयाक्रांत हैं। कहा जा रहा है कि एमएसपी को कानूनी रूप देना बर्बादी को न्यौता देना है। ढाई प्रदेशों (पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उप्र) के बड़े किसानों का आंदोलन एक और संदेश देता है कि किसी भी घटना को स्थायी मान लेना नासमझी होती है। विपक्षी दलों को लग रहा था कि किसान आंदोलन उनके लिए राजनीतिक एटीएम जैसा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस एटीएम को ही बंद कर दिया। पांच राज्यों और खासतौर से उप्र, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के हाथ से उसका सबसे बड़ा मुद्दा चला गया। इसीलिए कहते हैं कि उधार के सिंदूर से मांग भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

लोकतंत्र में हठधर्मिता के लिए कोई स्थान नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जड़ता एवं टकराव लोकतंत्र की प्रकृति-प्रवृत्ति नहीं। संवाद से सहमति और सहमति से समाधान की दिशा में सतत् सक्रिय एवं सचेष्ट रहना ही लोकतंत्र की मूल भावना है। गुरु पर्व के पवित्र अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए इसका अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उदारता दिखाते हुए उन्होंने देशवासियों से इसके लिए क्षमा भी मांगी कि सरकार नए कृषि कानूनों की उपयोगिता को समझाने में विफल रही। साथ ही किसानों और खेती के हित में निरंतर कल्याणकारी निर्णय करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। सरकार और प्रधानमंत्री की यह पहल स्वागतयोग्य है कि उन्होंने कृषि कानूनों को अहम का मुद्दा नहीं बनाया। इस फैसले को किसी पक्ष की हार-जीत के रूप में देखा जाना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं परंपराओं के विरुद्ध होगा।

● इन्द्र कुमार

अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने भी की थी संसद भवन में चढ़ाई

देश को शर्मिंदा करने वाली इस घटना के 20 दिन पहले 6 जनवरी को ऐसी ही घटना अमेरिका में हुई थी। वहां ट्रंप समर्थकों ने संसद भवन पर चढ़ाई कर दी थी। पिछले दिनों इनमें से दो दंगाइयों को 41-41 महीने की सजा सुनाई गई। जब अमेरिका में दंगाइयों को सजा सुनाई जा रही थी, तब अमरिंदर के उत्तराधिकारी चरणजीत सिंह चन्नी लालकिले की हिंसा में आरोपित 83 दंगाइयों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर रहे थे। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद इन दंगाइयों को माफ करने की मुहिम छिड़ जाए तो हैरानी नहीं। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा मजबूरी में की गई, यह प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि 'शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी, जिस कारण दीये के प्रकाश जैसा सत्य हम कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए।' यह एक भावुक बयान था, लेकिन आखिर किसके सामने? भीड़तंत्र के सामने। भीड़तंत्र के आगे ऐसी भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद यह अंदेशा उभर आया है कि भीड़तंत्र पर यकीन करने और जोर-जबर से अपनी ही चलाने वालों का दुस्साहस बढ़ सकता है। ऐसे तत्वों के आगे झुककर शांति नहीं हासिल की जा सकती। यदि यह मान लिया जाए कि किसान आंदोलन की आड़ में सक्रिय देश विरोधी तत्वों को झटका देने के लिए कृषि कानून वापस लिए गए तो सवाल उठेगा कि क्या अब वे निष्क्रिय हो जाएंगे?

असंतोष दूर करने का फार्मूला

राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान ने सिर फुटौअल रोकने के लिए मंत्रिमंडल फेरबदल करके अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में संतुलन बनाने का प्रयास किया। विरोधी खेमे की मांग के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बदला गया लेकिन पायलट के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई जिससे उनका भी राजनीतिक महत्व बना रहे। अब सबकी निगाह छत्तीसगढ़ पर है जहां उप्र चुनाव के बाद एक बार फिर सियासत गरमा सकती है। माना जा रहा है कि राजस्थान का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी काम आ सकता है। यानी मंत्रिमंडल फेरबदल करके भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव खेमे में एक संतुलन बनाया जाए। हालांकि देव मुख्यमंत्री से कम की बात पर राजी नहीं हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ के लिए तय किया था। जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इस फॉर्मूले से अनजान रहे। इस तरह के फॉर्मूले पर न तो वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई थी और न ही भूपेश बघेल को ही इस बारे में बताया गया था। लिहाजा अब उस कथित वादे पर अमल आसान नहीं है।

सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर जब छत्तीसगढ़ का मामला निपटाने के लिए उप्र चुनाव के बाद बैठेंगे तो ये तय माना जा रहा है कि सबसे मुफीद फॉर्मूला राजस्थान जैसा ही होगा। क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगने लगा है कि आंतरिक दबाव में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला अंतत: भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। जानकार ये भी मानते हैं कि राजनीतिक लिहाज से प्रचंड बहुमत की सरकार में मुखिया को बदलने की जरूरत शायद ही कभी महसूस हुई हो। वह भी तब जबकि ज्यादातर विधायकों का समर्थन भी मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बात के पक्ष में कतई नहीं हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदला जाए।

दावा है कि छत्तीसगढ़ में बघेल के पक्ष में विधायकों का समर्थन है, साथ में उनका जातीय आधार भी पार्टी को प्रदेश और प्रदेश से बाहर ताकत प्रदान करता है। बघेल कुर्मी जाति से आते हैं। पिछड़ा वर्ग में कुर्मी काफी प्रभाव रखते हैं। खासतौर पर उप्र में कुर्मियों की सियासी ताकत के बूते ही अपना दल को भाजपा ने काफी महत्व दिया है। उप्र में बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भी यही संदेश दिया है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि एक बात और जो बघेल के पक्ष में है वह ये है कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का गवर्नेंस एक मॉडल के तौर पर उभर रहा है। राज्य की योजनाएं केंद्रीय स्तर पर चर्चा में आई हैं। खुद प्रियंका गांधी ने इन योजनाओं का बखान किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री बदलने का सीधा फायदा भाजपा को होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल को भाजपा फेल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करेगी। जानकारों के मुताबिक बघेल के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर टीएस देव कई मामलों में पिछड़ जाते हैं। सियासी और संगठन के स्तर पर वे बघेल की तरह पैठ नहीं बना पाए हैं। मंत्री के तौर पर भी वे अपनी खास छाप छोड़ने में असफल रहे। तर्क दिया जाता है कि कोविड के दौर में जब लोगों को मदद की जरूरत थी उनका दिल्ली में जमे रहना उनके खिलाफ गया। आदिवासी मुद्दे पर देव ने अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया लेकिन अपने ही इलाके में पंडो आदिवासियों की मौत के मसले पर उनकी चुप्पी उनके लिए उल्टा पड़ गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष की बातें आलाकमान तक पहुंची हैं और इसकी पुष्टि के बाद ही बघेल को मुख्यमंत्री बनाए रखने के पक्ष में प्रियंका गांधी मजबूती से सामने आईं। हालांकि राहुल गांधी के कुछ करीबी रणनीतिकार देव के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे लेकिन प्रियंका के आगे आने के बाद उन्होंने खुद को पीछे कर लिया।

छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच लगातार विवाद की तस्वीरें सामने आती रही है। कुछ दिनों पहले जशपुर में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ हाथापाई का मामला सामने आया था। उसके बाद बिलासपुर में शहर विधायक को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ था। मामला यहीं थमा नहीं, एनएसआई कार्यकर्ताओं के बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, राजीव भवन में ही विवाद की तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमरजीत चावला के बीच विवाद की तस्वीरें सामने आई थीं। इन सब विवादों में देखा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। ताज्जुब की बात यह रही कि इन सब विवादों में से सिर्फ सन्नी अग्रवाल और अमरजीत चावला के बीच हुए विवाद पर कार्रवाई की गई, जिसमें सन्नी अग्रवाल को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पार्टी अनुशासन का पालन नहीं करने वाले बाकी नेताओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

● **रायपुर से टीपी सिंह**

राजस्थान-छत्तीसगढ़ दोनों में कांग्रेस सरकार

राजस्थान को छत्तीसगढ़ में आवंटित मौजूदा कोयला खदान में नवंबर तक का ही कोयला बचा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने वहां परसा कोल ब्लॉक में 5 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष और केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में 9 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए अतिरिक्त खदान का आवंटन किया है, लेकिन दोनों ही मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार स्वीकृति प्रक्रिया में देरी कर रही है। इससे राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आमने-सामने स्थिति बन गई है। यह स्थिति तब है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दो बार चिट्ठी लिखी है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार ही है। दरअसल, कोल ब्लॉक परसा से माइनिंग की केंद्रीय कोयला मंत्रालय और केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने तो क्लीयरेंस दे दी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार स्तर पर अंतिम स्वीकृति अटकी हुई है। ऐसे में राजस्थान अपनी ही कोयला खान से माइनिंग नहीं कर पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कोल ब्लॉक की जमीन छत्तीसगढ़ के वन विभाग क्षेत्र में आती है। आदिवासी क्षेत्र में कुछ स्थानीय नेताओं और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वोट बैंक को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रही है। ..

अंतिम सांसें गिन रहा माओवादी आंदोलन

महाराष्ट्र पुलिस के सी-60 दस्ते ने छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे गढ़चिरौली में दो-तीन शीर्ष कमांडरों सहित 26 नक्सलियों को मार गिराया। यह जवाबी कार्रवाई पिछले दिनों 15 पुलिस कमांडों की शहादत के बाद की गई थी। इस ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सी-60 दस्ते के सदस्य थे, जिसे विशेष रूप से 1990 में नक्सल हिंसा से निपटने के लिए गठित किया गया था। सी-60 पहले भी इस इलाके में इस तरह के ऑपरेशन करता रहा है। यह ऑपरेशन पूरी तरह से खुफिया जानकारियों पर आधारित था, जिसमें माओवादियों की लोकेशन एवं मिलिंद बाबूराव तेलतुम्बडे सहित वहां छिपे अन्य माओवादियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। मुठभेड़ में ढेर हुए मिलिंद तेलतुम्बडे भाकपा के नवगठित एमएमसी क्षेत्र (महाराष्ट्र-मप्र-छत्तीसगढ़) का प्रमुख था, जिस पर 50 लाख रुपए का इनाम रखा गया।

असल में माओवादी आंदोलन अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एक समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने माओवादी हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज न केवल माओवादी हिंसा में कमी आई है, बल्कि कई बड़े-बड़े माओवादी कमांडर मारे गए हैं। गढ़चिरौली में सी-60 द्वारा की गई इस कार्रवाई में भी मिलिंद तेलतुम्बडे के अलावा दो अन्य शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। वर्ष 2009 में देश के 123 जिले माओवादी हिंसा से प्रभावित थे और 65 जिले बहुत ज्यादा माओवादी हिंसा से प्रभावित थे। लेकिन आज देश के मात्र 65 जिले माओवाद प्रभावित हैं और मात्र दो से तीन जिलों में माओवादी हिंसा सर्वाधिक है। बाकी जिलों में छिटपुट माओवादी गतिविधियां होती हैं। वर्ष 2009 और 2010 में प्रति वर्ष एक हजार से ज्यादा लोग (माओवादी, पुलिस, आम लोग समेत) मारे गए थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। माओवादियों के वर्चस्व का क्षेत्र सिकुड़ गया है।

संयुक्त आंध्र प्रदेश (तेलंगाना समेत) में एक समय साल में चार सौ-पांच सौ लोग नक्सली हिंसा में मारे जाते थे, अब एक-दो लोग भी मारे जाते हैं, तो बड़ी बात हो जाती है। सरकार के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिससे नक्सली हिंसा का एकदम से खात्मा कर दिया जाएगा। इसे धीरे-धीरे खत्म किया जा सकता है और वह हो रहा है। फिलहाल जो स्थिति है, उसमें एक तरह से माओवादी आंदोलन लगभग खात्मे के रास्ते पर है। धीरे-धीरे इनके वर्चस्व के क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं। याद होगा कि 2008-09 में पश्चिम बंगाल पूरे देश में सबसे ज्यादा माओवाद प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन आज वहां माओवादी हिंसा की घटना शायद ही सुनने को मिलती है। जहां तक बिहार, झारखंड में नक्सली हिंसा की बात है, तो वह माओवादी आंदोलन नहीं है। उधर जो माओवादी गुट सक्रिय हैं, वे दरअसल फिरौती गिरोह हैं। उनकी तुलना छत्तीसगढ़ या गढ़चिरौली के माओवादियों से करेंगे, तो यह गलत होगा। बिहार, झारखंड में जो नक्सली गुट हैं, वे छोटे-छोटे फिरौती गिरोह हैं, जबकि छत्तीसगढ़ या गढ़चिरौली के माओवादियों के आंदोलन में अब भी थोड़ी जान बची है। और इसे काबू में लाने के लिए गढ़चिरौली में ये ऑपरेशन किए गए, जो बहुत कामयाब रहे।

विभिन्न क्षेत्रों में कभी-कभार माओवादियों की जो हिंसक घटनाएं होती हैं, उसका एक कारण यह है कि वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसी हिंसक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। कोई भी हिंसक संगठन अगर कुछ न करे, और चुप बैठ जाए, तो वह सिकुड़ कर अपने आप खत्म हो जाएगा। उसे अपनी क्षमता दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। वे अपनी क्षमता दो-तीन चीजों के लिए दिखाते हैं। अगर वे अपनी क्षमता नहीं दिखाएंगे, तो कोई उनकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। माओवादियों को अपने संगठन में भर्ती करने के लिए नए-नए रंगरूट नहीं मिलेंगे।

दूसरी बात, उन इलाकों में रहने वाले आम लोग, जो उनकी विभिन्न तरह से मदद करते हैं, वे भी इनकी निष्क्रियता देख धीरे-धीरे अलग होने लगते हैं और सरकार के सुरक्षा बलों की मदद करने लगते हैं। इसलिए उन्हें सरकार का मददगार बनने से रोकने के लिए, धमकाने-डराने की खातिर माओवादी हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तीसरा, ये पुलिस के मुखबिरों को निशाना बनाने के लिए हिंसा करते हैं। चौथा, अगर उन्हें खबर मिलती है कि अमुक रास्ते से पुलिस या सुरक्षा बलों का दस्ता जा रहा है और उनकी क्षमता मजबूत होती है, तो वे सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसा करते हैं। ऐसे ऑपरेशन को मौके का ऑपरेशन कहा जाता है और अगर ये ऑपरेशन ज्यादा कामयाब होते हैं, तो फिर उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है। लेकिन छिटपुट घटनाओं के बावजूद माओवादियों का वर्चस्व एक छोटे से क्षेत्र में सिमटकर रह गया है और माओवादी हिंसा में भारी कमी आई है। माओवादी हिंसा आज आंतरिक सुरक्षा के लिए पहले की तरह बड़ा खतरा नहीं रह गई है। आज माओवादी आंदोलन अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

● **बिन्दु माथुर**

गढ़चिरौली में सबसे अधिक चौकसी

गढ़चिरौली में माओवादी छिपते हैं। आप पिछले रिकॉर्ड देखेंगे, तो पाएंगे कि गढ़चिरौली में माओवादियों द्वारा हिंसक घटनाएं बहुत कम हुई हैं, जबकि माओवाद विरोधी सुरक्षा बलों की कार्रवाई की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हिंसक घटनाएं होना और माओवादियों का वर्चस्व, दोनों दो चीजें हैं। देश के 65 जिलों में वे आज भी हैं और छिटपुट हिंसक घटनाएं साल में एकाध बार होती रहती हैं। लेकिन जिस तरह का उनका वर्चस्व था और जितनी सक्रियता थी, वह बहुत हद तक सिमट गई है। आज वे मात्र छत्तीसगढ़ में ही हावी हैं, वह भी बस्तर डिवीजन के दो-तीन जिलों में। एक जमाने में बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बल जाने से डरते थे, लेकिन आज उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की चौकियां हैं। आज बस्तर के जंगलों के छोटे-छोटे इलाके में माओवादी छिपे हुए रहते हैं और पुलिस जब उधर सर्च ऑपरेशन चलाती है, तो वे उस इलाके की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए तत्काल भाग जाते हैं और फिर उन क्षेत्रों में लौट आते हैं। इक्का-दुक्का हिंसक घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं।

क्या पायलट होंगे 2023 में चेहरा?

राजस्थान नहीं छोड़ेंगे पायलट

पायलट ने मंत्रिमंडल को लेकर खुशी जताते हुए संकेत दिए हैं कि एआईसीसी में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही हैं। कांग्रेस आलाकमान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पायलट को किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है, लेकिन पायलट राजस्थान नहीं छोड़ेगे और लगातार सक्रिय रहेंगे। पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उप्र या किसी चुनावी राज्य में प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती हैं। पायलट को प्रियंका गांधी के सहयोग के लिए राजी किया गया है। साथ ही कुछ अन्य सूत्रों का यह भी कहना है कि पायलट को कांग्रेस के मीडिया सेल का प्रभारी बनाया जा सकता है। क्योंकि उनकी हर मुद्दे पर बात रखने की कला का कांग्रेस लाभ लेना चाहती हैं। अब फैसला आलाकमान को करना है।

राजस्थान कांग्रेस में सुलह हो गई है। सचिन पायलट ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर खुशी जता दी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि गहन चिंतन और चर्चा विमर्श के बाद नेतृत्व ने जो कदम उठाया है, उससे पूरे प्रदेश में अच्छा संकेत जा रहा है। खुशी है कि जो कमी थी उसे पूरा किया है। पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और हम 2023 में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आज पूरे राजस्थान में एक ही चर्चा है कि पायलट को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या सचिन राजस्थान में 2023 में कांग्रेस के पायलट बनेंगे?

उधर, अगले महीने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कुछ नए चेहरों के साथ सरकार चलाएंगे। गहलोत मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है। इस फेरबदल में 15 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें से 11 विधायकों ने कैबिनेट व चार ने राज्यमंत्री की शपथ ली। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए थे। नए चेहरों में सचिन पायलट के पांच करीबी शामिल हैं। पायलट गुट के हेमाराम चौधरी ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

मंत्रिमंडल फेरबदल में सबको साधने की कवायद का ही एक रूप यह भी दिखा कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रत्येक विधायक का नाम स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घोषित किया और उन्हें मंच पर आमंत्रित किया। इस दौरान मंत्री पद की शपथ ले रहे प्रत्येक विधायक के समर्थकों ने जोरदार नारे भी लगाए। पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अपनाए जाने के समय हटाए गए विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए छह विधायकों में से राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री बनाया गया है। गहलोत मंत्रिमंडल का कोटा पूरा हो गया। अब चर्चा है कि 15 विधायकों को संसदीय सचिव व सात को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया जाएगा।

बेशक यह कहा गया कि ताजा फेरबदल में सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन गहलोत की चुनौतियां बरकरार हैं। टीकाराम जूली को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस के ही एक विधायक ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस्तीफे की धमकी तक दे दी थी, वहीं बसपा से कांग्रेस में आए कुछ नेताओं ने भी इस फेरबदल पर असंतोष जाहिर किया। हालांकि गहलोत के लिए यह राहत की बात होगी कि राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने फेरबदल पर संतोष जताया है। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा कि जो कुछ कमियां थीं, उन्हें दूर किया गया है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि जो मुद्दे उठाए गए थे, उनका संज्ञान लिया गया है। गौरतलब है कि पायलट एवं उनके समर्थक 18 विधायकों ने पिछले साल मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अपना लिया था। तब पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। तभी से पायलट एवं उनके समर्थक मंत्रिमंडल में फेरबदल एवं राजनीतिक नियुक्तियां किए जाने की मांग उठा रहे थे। अपनों के ही बगावती तेवरों से डगमगाती दिख रही गहलोत सरकार अब स्थिर है। राज्य के विकास के लिए तो यह अच्छी खबर है ही, कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है।

सचिन पायलट ने कहा कि मंत्रिमंडल की नई सूची से अच्छा और सकारात्मक संदेश गया है। हमने इस मुद्दे को बार-बार उठाया था। मुझे खुशी है कि पार्टी आलाकमान और राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लिया। पायलट ने कहा कि मंत्रिमंडल में दलित वर्ग को विशेष महत्व दिया गया है। आदिवासियों का भी स्थान बढ़ाया गया है। कांग्रेस के साथ जो तबका हमेशा रहा उसको प्रतिनिधित्व मिला है। अभी मुख्यमंत्री सलाहकार सहित कई राजनीतिक नियुक्ति होनी हैं। सभी में कार्यकर्ता और जनभावना का ध्यान रखा जाएगा।

खुद की भूमिका को लेकर फिर पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुझे 20 साल में जो जिम्मेदारी दी है, मैंने पूरी ताकत और निष्ठा के साथ निभाई हैं। आने वाले समय में जो भी आलाकमान की ओर से मुझे निर्देश मिलेंगे वो मैं करूंगा। जहां भी मुझे काम देगी मेरी उपयोगिता समझेगी, मैं पूरी ताकत से वहां जाकर काम करूंगा। पायलट ने कहा कि हर हाल में हमें फिर से कांग्रेस की सरकार बनानी है। साथ ही जब पायलट से यह पूछा गया कि क्या 2023 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस सवाल को टाल गए।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

पूर्वांचल भरोसे भाजपा

तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान को व्यापक रूप से पश्चिमी उप्र में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल करने की, भाजपा की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन, पश्चिम उप्र में किसी भी झटके की भरपाई के लिए, पार्टी पहले से ही उस रणनीति पर मेहनत कर रही है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक और नेता, उसका 'पूर्वांचल विकास मॉडल' बता रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले ही पिछले एक महीने में पूर्वी उप्र के तीन दौरे कर चुके हैं, जिनमें सबसे ताजा दौरा 16 नवंबर को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए था। इससे पहले वो कुशीनगर और सिद्धार्थ नगर गए थे, जहां उन्होंने क्रमशः एक हवाई अड्डे और एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। अपेक्षा की जा रही है कि वो जल्द ही, काशी कॉरिडोर परियोजना के उद्घाटन के लिए वाराणसी जाएंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसी महीने, पूर्वी उप्र के अपने दौरे के दौरान, कई सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत की, और उनके फिर से वहां जाने की अपेक्षा है। मोदी और शाह के बार-बार दौरे और क्षेत्र की 'विकास' परियोजनाओं को दिए गए जबर्दस्त मीडिया प्रचार से, उप्र में चुनाव आने के समय भाजपा के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा। 28 जिलों में फैली 164 असेम्बली सीटों (उप्र की कुल 403 सीटों में) के साथ, पूर्वांचल क्षेत्र प्रदेश चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयोग से यहां मोदी (वाराणसी) और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (सांसद के रूप में उनके पिछले कार्यकाल में गोरखपुर) का चुनाव क्षेत्र भी है।

2017 के प्रदेश चुनावों में भाजपा ने पूर्वांचल में भारी जीत हासिल की थी, और 164 में से 115 सीटों पर विजयी रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 17, बसपा को 15, कांग्रेस को दो, और अन्य को 15 सीटें मिलीं थीं। पूर्वी उप्र में पार्टी के कार्यक्रम को देखने वाले एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि चुनावी लड़ाईयां 'नैरेटिव और अवधारणा' पर टिकी होती हैं और लोगों के बीच अपनी परियोजनाओं और स्कीमों को बढ़ाने के लिए, पार्टी कड़ी मेहनत कर रही है। पदाधिकारी ने कहा, 'पूर्वांचल हमारे प्रचार की आत्मा है और हमें यहां पहले से ज्यादा अंतर से जीतना है।' नेता के अनुसार, पार्टी इस इलाके में गैर-यादव ओबीसी भाजपा समर्थकों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। नेता ने कहा, 'ओम प्रकाश राजभर (पूर्व भाजपा सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता) एसपी गठबंधन में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनकी जाति के वोटों का झुकाव भाजपा की तरफ है। हमने वहां एक समानांतर नेतृत्व खड़ा कर दिया है।' इसी तरह दूसरे गैर-यादव ओबीसीज जैसे मौर्या, चौहान (नुनिया), निषाद, बींद, कुर्मी, प्रजापति आदि हमारे साथ हैं। हमारी पार्टी ने उन्हें प्रतिनिधित्व दिया है।

उप्र के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जिनका चुनाव क्षेत्र सिद्धार्थ नगर जिले में है, ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी विकास परियोजनाओं के साथ, 'पूर्वांचल की छवि बदल दी है। जहां से मैं आता हूं उसे उप्र के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया जाता है। 2017 से पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार वहां मुख्य चुनौतियां थीं। अब हमारे यहां सिद्धार्थनगर में एक मेडिकल कॉलेज है। मैंने हाल ही में अपने चुनाव क्षेत्र में भी, एक सरकारी अस्पताल का उद्घाटन किया है। बिजली और सड़क संपर्क की स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई है।' उप्र भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, कि पार्टी राज्य में एक क्षेत्रवार रणनीति का दृष्टिकोण लेकर चल रही है।

उन्होंने आगे कहा, 'चुनाव के नजरिए से मैं समझता हूं, कि 'मिशन पूर्वांचल' से जुड़े हमारे कार्यों के पूरा होने के बाद, पार्टी पश्चिमी उप्र पर ध्यान देना शुरू करेगी। पूर्वांचल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और विकास की दृष्टि से भी मध्य और पश्चिम उप्र की अपेक्षा, यहां ज्यादा परियोजनाओं की जरूरत थी। इस सरकार के बनने से पहले पूर्वी उप्र की छवि अच्छी नहीं थी।' उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र, क्रमशः वाराणसी और गोरखपुर में, काफी परियोजनाएं सामने आईं हैं, जबकि दूसरे जिलों में भी खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जुलाई में, वाराणसी से पूर्वांचल में चुनावी बिगुल फूंक दिया था, जहां उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। उस आयोजन के तुरंत बाद गृहमंत्री अमित शाह मिर्जापुर पहुंच गए, जो पूर्वी उप्र में विंध्याचल क्षेत्र का हिस्सा है, जहां उन्होंने 150 करोड़ रुपए की विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक पदाधिकारी ने कहा, कि सरकार ने 'पूर्वी उप्र के लिए बहुत कुछ किया है।'

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

पूर्वांचल विकास मॉडल बतौर चुनावी मुद्दा

उप्र भाजपा उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा कि वे पूर्वांचल में जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हम प्रदेश के हर हिस्से पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये सही है कि पिछले चार या पांच वर्षों में, पूर्वांचल हमारे लिए एक मजबूत गढ़ बन गया है। पूर्वांचल के लोग योगी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बार पूर्वांचल में हमें पहले से कहीं बेहतर नतीजे मिलेंगे। हमारी सरकारी स्कीमें वहां घर-घर तक पहुंच गईं हैं। उप्र भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि पार्टी स्पष्ट तौर पर 'पूर्वांचल विकास मॉडल' को एक चुनावी मुद्दे के तौर पर उभार रही है। सूत्र ने आगे कहा, 'अगर आप पिछले कुछ हफ्तों के आयोजनों में दिए गए बयानात पर ध्यान दें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा।' पिछले महीने कुशीनगर में अपने संबोधन के दौरान, मोदी ने कहा कि उप्र का 'औद्योगिक विकास' अब एक या दो शहरों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि 'पूर्वांचल के जिलों में भी पहुंच रहा है।

नई जोड़ी क्या गुल खिलाएगी?

बिहार का तापमान इस वक्त भले ही कम हो, लेकिन सियासी पारा रोज बढ़ रहा है। दिल्ली में नेताओं की भेंट-मुलाकात ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय जनता दल के बीच आगामी विधान परिषद् चुनाव के मद्देनजर कोई नई खिचड़ी पक रही है। यह खिचड़ी कितनी लजीज होगी और क्या जनता को यह रास आएगी, इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। एलजेपी (रामविलास) की पटना में बिहार प्रदेश के संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि एलजेपी को आगामी विधान परिषद् चुनाव लड़ना चाहिए, पर अकेले नहीं। खबर है कि आरजेडी के सर्वोच्च नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एलजेपी को 5-6 सीटों का ऑफर दिया है।

75 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद् के 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है। हर दो वर्ष के बाद विधान परिषद् एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्यों का चयन होता है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद् में आरजेडी के पांच सदस्य हैं जबकि एलजेपी का ना तो विधानसभा में और ना ही विधान परिषद् में एक भी सदस्य है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी का एक विधायक चुना गया था जिसने बाद में सत्तारूढ़ जनता दल-यूनाइटेड जॉइन कर लिया था। अभी कुछ ही महीने पहले हुए पार्टी के विभाजन के बाद एलजेपी (रामविलास) के एकमात्र सांसद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान हैं।

एलजेपी के बिहार संसदीय बोर्ड की तरफ से घोषणा की गई है कि आगामी विधान परिषद् चुनाव पार्टी गठबंधन में लड़े और यह गठबंधन किसके साथ हो, इसका अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पर छोड़ा जाता है। उम्मीद की जा रही है कि चिराग पासवान जल्द आरजेडी के साथ गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। आरजेडी की व्याकुलता समझी जा सकती है। अभी हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने पुराने सहयोगी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन भंग कर दिया। दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ, दोनों सीट जेडी-यूके के खाते में गई और दोनों सीटों पर आरजेडी दूसरे स्थान पर रही। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं होता हो आरजेडी तारापुर सीट जीत सकती थी। यानी, आरजेडी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह पूरे बिहार में अकेले और अपने दम पर चुनाव लड़ सके और 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। गठबंधन तोड़ने के बाद आरजेडी अब वापस कांग्रेस के पास तो जा नहीं सकती है, इसलिए एलजेपी के साथ वह गठबंधन करने को उत्सुक है। वैसे भी विधानसभा उपचुनाव में एलजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के मुकाबले कहीं बेहतर था।

रही चिराग पासवान की बात तो शायद उन्हें भी यह अहसास हो गया है कि जोश और हकीकत में कितना अंतर होता है। युवा जोश में चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग हो गए। फैसला किया कि उनकी पार्टी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और भाजपा का समर्थन करेगी। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई पार्टी किसी गठबंधन के किसी एक दल का समर्थन करे और दूसरे का विरोध। चिराग की लौ लगभग बुझ गई और पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीतने में सफल रही। बाकी का सारा काम चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने विद्रोह करके पूरा कर दिया। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए और चिराग अलग-थलग पड़ गए। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने यह साफ कर दिया कि पिता रामविलास पासवान द्वारा गठित पार्टी का सतीत्व तब ही बच सकता है अगर एलजेपी किसी बड़ी पार्टी की पूंछ पकड़ ले। चूंकि एनडीए में चाचा पशुपति पारस वाली एलजेपी है, लिहाजा चिराग के पास और कोई चारा बचा भी नहीं है कि वह आरजेडी का दामन थाम लें। तेजस्वी यादव की सोच है कि अगर आरजेडी के यादव वोट बैंक और एलजेपी के दलित वोट बैंक का विलय हो जाए तो इससे उनका भविष्य में मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

सियासी गलियारों में अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या लालू यादव चिराग पासवान को अपने साथ लेने की रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि श्याम रजक की लालू यादव से लगातार मुलाकातें तो यही इशारा कर रही हैं। इसके अलावा पिछले महीने राजद प्रवक्ता ने एक डिबेट के दौरान कहा था कि लालू यादव के बाहर आने के बाद बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इसकी पीछे जमीनी स्तर की वह राजनीति है जिसमें पशुपति कुमार पारस भले ही अपने जनाधार का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविक समर्थन चिराग पासवान के पक्ष में नजर आता है। इसका कनेक्शन वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से भी जुड़ता है। हम आंकड़ों की अगर बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग ने जीत और हार के अंतर को कम कर दिया था।

● **विनोद बक्सरी**

दोनों हाथ पकड़ने को आतुर

कुछ समय पहले रामविलास पासवान की पहली बरसी के अवसर पर जब चिराग तेजस्वी से आमंत्रण देने के नाम पर मिले तो दोनों की गर्मजोशी देखी जा सकती थी। तेजस्वी ने चिराग को अपना बड़ा भाई करार दिया और इस नई खिचड़ी पकने का व्यंजन वहीं तय हो गया था। अब जबकि तेजस्वी और चिराग अपने-अपने पिता द्वारा अर्जित साख खोते दिख रहे हैं तो एक-दूसरे का हाथ पकड़ने को आतुर होना स्वाभाविक है। भविष्य में इस गठबंधन की क्या रूपरेखा होगी, यह कितना सशक्त बन पाएगा और कैसे तेजस्वी और चिराग एक-दूसरे के पूरक बनेंगे, इसका फैसला विधान परिषद् चुनाव के निर्णय से ही पता चल पाएगा। पर इतना तो तय है कि ताकि उनकी लौ पूरी तरह ना बुझ जाए, चिराग अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे इस प्रस्तावित गठबंधन से उनके स्वर्गीय पिता की आत्मा को ठेस ही क्यों ना पहुंचे। आखिर राजनीति इसी को कहते हैं और मौकापरस्ती राजनीति का अभिन्न हिस्सा होता है।

इमरान का समर्पण

तहरीक-ए-लब्बैक से विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भयभीत

टीएलपी की हिंसक भीड़ को वापस घर भेजने के लिए सुरक्षा प्रतिष्ठान ने क्या कीमत चुकाई है? मुख्य सवाल जो पाकिस्तान में पूछा जा रहा है, वह यह कि क्या यह संगठन प्रतिबंधित है और चुनाव आयोग ने इसे पिछले आम चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति क्यों दी थी। यह पिछले चुनावों में पंजाब में चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसने नवाज शरीफ के वोट बैंक में सेंध लगाई और इस तरह उन्हें संसद में बहुमत से वंचित कर दिया। टीएलपी से विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इतना भयभीत हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग में उसका जोरदार विरोध नहीं किया। इसके अलावा, इन पिछले दो हफ्तों में विपक्षी राजनीतिक दल चुप रहे और पहले तो, सरकार के खिलाफ उन्होंने धरना नहीं किया, क्योंकि इस हिंसक भीड़ के साथ खतरनाक स्थिति थी और दूसरी बात यह कि मुसलमानों के रूप में वे टीएलपी के नारे के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। एक मुसलमान इसके खिलाफ अपनी आस्था और विश्वास से कैसे लड़ सकता है? खतरा यहीं पर है।

लगभग दो साल पहले परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के साथ ही दुनिया के सबसे गरीब देशों के लिए एक वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों एक साझा शत्रु का सामना कर रहे थे। और यह शत्रु थी विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी, जिसने सारी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। यह वायरस इतना छोटा था कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, फिर भी यह इतना शक्तिशाली था कि इसने इस धरती पर से लाखों लोगों का सफाया कर दिया। आज भी मानव जाति इस अज्ञात चुनौती का सामना करने के लिए जूझ रही है, भले ही महामारी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यह अब भी मौजूद है और दुनियाभर में लोगों का जीवन, चाहे अमीर हों या गरीब, अब भी खतरे में है। कम से कम पिछले दिनों हमने जो कुछ देखा, उससे प्रतीत होता है कि पाकिस्तान में इस महामारी से कोई सबक नहीं सीखा गया है और इस परमाणु सशस्त्र राष्ट्र ने अब कुछ ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया है, जो कोविड-19 की तुलना में घातक और शायद अधिक खतरनाक है। वह है कट्टरपंथ। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के आगे इमरान सरकार समर्पण करती नजर आ रही है।

पाकिस्तान और उसके नागरिकों के लिए यह खतरा पहले से कम ज्ञात धार्मिक संगठन, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) है, जो एक प्रतिबंधित संगठन है। इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर जाने वाली सभी सड़कें बंद थीं, क्योंकि धार्मिक कट्टरपंथियों ने धरना दिया, लोगों की हत्या की, उन्हें उत्पीड़ित किया और गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को वे इस्लामाबाद आने से रोक रहे थे। सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। आज इसने देश को अपने उन्माद की चपेट में ले लिया है। टीएलपी की मांग अपने नेताओं और अनुयायियों को रिहा करने के लिए थी, जिन पर आतंकवाद विरोधी अदालतों में मुकदमा चलाया गया था। इसके अलावा वे फ्रांसीसी राजदूत को भी निष्कासित करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि फ्रांस ने मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा अपने नागरिकों की हत्या के बाद कई मुस्लिम विरोधी कानून पारित किए थे, और यूरोपीय संघ के साथ रिश्ते खत्म कर दिए थे।

आज तक सुरक्षा प्रतिष्ठान, प्रधानमंत्री और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को छोड़कर किसी को भी हस्ताक्षर किए गए समझौते के बारे में पता नहीं है। जाहिर है, सरकार कथित रूप से पुलिसकर्मियों की हत्या, मुल्क और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करने में शामिल टीएलपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को आगे नहीं बढ़ाने पर सहमत हो गई है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकार समूह को प्रतिबंधित करने के अपने निर्णय में कानूनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। अंग्रेजी अखबार दैनिक डॉन लिखता है, 'टीएलपी के मुद्दे पर अब और पर्दा नहीं डाला जा सकता। आंदोलन करने वाले घर जा सकते हैं, लेकिन वे सरकार से भारी कीमत वसूल कर ऐसा करेंगे। वे राज्य की ताकत और विश्वसनीयता की कीमत पर भी ऐसा करते हैं। जब तक राज्य को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं होता और इससे निपटने के लिए कदम उठाना शुरू नहीं होता, तब तक टीएलपी मुल्क को चुनौती देने, डराने और विजयी होने की अपनी क्षमता के आधार पर बढ़ती रहेगी।'

वर्ष 2017 में सुरक्षा प्रतिष्ठान ने राजनेताओं के खिलाफ एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस संगठन को खड़ा किया। जब कानून मंत्री के इस्तीफे के साथ ही टीएलपी का विरोध और धरना समाप्त हो गया, तो सुरक्षा प्रतिष्ठान ने इन धार्मिक कट्टरपंथियों से सौदे में अपनी भूमिका नहीं छिपाई। सोशल मीडिया पर अब भी एक वीडियो उपलब्ध है, जिसमें सेना के एक वरिष्ठ जनरल दिखाई दे रहे हैं, जो पैसे का लिफाफा सौंपते हुए भीड़ से कह रहे हैं कि इससे घर लौटने के किराए का इंतजाम कर लें।

वह उन्हें शांत होने के लिए भी कहते हैं और बताते हैं कि वह खुद और ये लोग एक ही हैं। उस समय टीएलपी के बहुत अनुयायी नहीं थे, लेकिन इन धार्मिक कट्टरपंथियों का इस्तेमाल पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की निर्वाचित और मौजूदा पीएमएल (एन) सरकार के खिलाफ सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा किया गया था। वर्ष 2017 में राजधानी की पहली घेराबंदी के बाद अल्पज्ञात बरेलवी कट्टरपंथी संगठन का उदय हुआ। यह लोकप्रिय जन समर्थन नहीं, बल्कि नागरिक-सैन्य विभाजन था, जिसने इसे एक ताकत के रूप में बदल दिया। अब नवंबर 2021 में एक बार फिर जैसे ही पूरे पाकिस्तान में जनजीवन ठप हो गया, सुरक्षा प्रतिष्ठान ने दखल देकर मामले को सुलझाया, लेकिन टीएलपी और प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के बीच हुए समझौते को गुप्त रखा गया है, और ना ही कोई जानता है कि सरकार के इस समर्पण की शर्तें क्या हैं। यदि एक बार फिर टीएलपी को आम चुनावों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो वे विशेष रूप से पंजाब में मजबूत उम्मीदवारों के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, और त्रिशंकु संसद हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक जाहिद हुसैन कहते हैं, 'बगैर दंड के समूह की गतिविधियां जारी हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन ने जानबूझकर अपने प्रतिबंध के फैसले को अस्पष्ट रखा है। टीएलपी की हिंसक गतिविधियों के बावजूद प्रशासन ने अपने तुष्टीकरण के नजरिए को जारी रखा है।'

● **ऋतेन्द्र माथुर**

चीन का शत्रुतापूर्ण रवैया

भले ही चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का महत्वाकांक्षी सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि विश्व समुदाय और भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस घटनाक्रम को बारीकी से देखने की जरूरत है। सैन्य आधुनिकीकरण तथा युद्ध में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सैन्य संगठन, सिद्धांत, शिक्षण, प्रशिक्षण और कार्मिक नीतियों में सुधार की आवश्यकता थी। इस दिशा में चीन ने जो सुधार किए, उनमें केंद्रीय सैन्य आयोग के गठन और अन्य वैचारिक परिवर्तनों के साथ 1984 में नए सैन्य सेवा कानून का अधिनियमन शामिल था। इसने चीनी पीएलए को पहले जैसी सांस्कृतिक सेना के मुकाबले एक सैन्य चेहरा प्रदान किया।

यह सैन्य सुधार रक्षा अनुसंधान एवं विकास के पुनर्गठन और सैन्य व असैन्य विज्ञान तथा उद्योग को एकीकृत करने के लिए औद्योगिक आधार पर केंद्रित था। हथियारों के उन्नयन के लिए चुनिंदा विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रक्षा उद्योग सुधारों के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार में चीन का प्रवेश भी हुआ। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री की अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई एक ताजा रिपोर्ट में चीनी सेना के सैन्य-तकनीकी विकास के वर्तमान और संभावित भविष्य के कार्यक्रम और इसकी सुरक्षा व सैन्य रणनीति के सिद्धांतों और संभावित विकास के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह खतरनाक बदलाव को दर्शाता है।

चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिनमें लगभग 350 जहाजों और पनडुब्बियों की कुल युद्ध शक्ति है, जिसमें 130 से अधिक सतह पर वार करने वाले लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसकी तुलना में, अमेरिकी नौसेना के युद्ध बल में 2020 की शुरुआत में लगभग 293 जहाज थे। भूमि आधारित पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में, चीन के पास 1,250 से अधिक ग्राउंड-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और ग्राउंड-लॉन्च क्रूज मिसाइल हैं, जो 500 से 5,500 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। अमेरिका के पास फिलहाल एक तरह का पारंपरिक ग्राउंड-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 70 से 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है और उसके पास कोई ग्राउंड-लॉन्च क्रूज मिसाइल नहीं है। एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों के दायरे में चीन सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की उन्नत प्रणालियों वाली दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, जिनमें रूस निर्मित एस-400, एस-300 और घरेलू स्तर पर तैयार सिस्टम शामिल हैं, जो इसकी मजबूत और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं।

हालांकि चीनी परमाणु बलों के विकास का गहन अंतर्दृष्टि के साथ मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अमेरिकी परमाणु हथियारों के साथ बराबरी या उससे ज्यादा हथियार रखने की कोशिश के बजाय चीन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिकी हमलों के मद्देनजर उसके पास एक सुनिश्चित जवाबी क्षमता हो। चीन स्वतंत्र रूप से लक्षित कई रीएंट्री वाहन हथियारों की बड़ी संख्या को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। समुद्र, जमीन और वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता से उसके परमाणु हथियारों में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये नई प्रणालियां सुसज्जित हैं। पीएलए की वायुसेना एक नई वायु-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करके परमाणु मिशन को भी अपना रही है, जो परमाणु सक्षम होने के साथ ही परमाणु-सक्षम एच-20 रणनीतिक बमवर्षक भी हो सकती है। इतनी तेजी से सैन्य विकास के बीच हो सकता है कि चीन ने परमाणु हथियारों में भी निवेश किया हो, जिससे उसके पड़ोसियों को तात्कालिक खतरा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में मोर्चे पर तैनात हमारे सैनिकों को लक्ष्य करके चीन ने बैलेस्टिक मिसाइल तैनात कर रखे हैं। चीन द्वारा अभी हासिल की गई सैन्य क्षमता के अलावा उसके द्वारा हाल ही में तैनात की गई मध्य और मध्यवर्ती रेंज की बैलेस्टिक मिसाइलें भी उसकी मंशा के बारे में बताती हैं। कुल मिलाकर, हालिया रणनीतिक परिदृश्य चीन के वर्चस्ववादी रवैये के ही बारे में बताता है, जिसके तहत वह भारत की सीमा और ताइवान में अपनी सैन्य उपस्थिति जताने के अलावा दक्षिण चीन सागर में भी आक्रामकता का परिचय दे रहा है। वह दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर अपनी ऐतिहासिक हिस्सेदारी का दावा करता आया है, हालांकि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसके दावे को खारिज कर चुका है। लेकिन बीजिंग इस कानूनी फैसले को स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है। आक्रामक रवैये से चीन ने ब्रुनेई, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस के साथ अपने संबंधों को और भी जटिल तथा तनावपूर्ण बना दिया है।

● **कुमार विनोद**

चीन का सीमा पर सामरिक कदम उठाना जारी

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने सूचित किया है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए कोर कमांडरों की लगातार वार्ताओं के बावजूद बीजिंग ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने दावे के अनुरूप दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी और सामरिक कदम उठाना जारी रखा है। यही नहीं, भारत को अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ता बनाने से रोकने के लिए भी वह प्रयत्नशील है, जिसमें वह विफल हुआ है। पेंटागन का साफ कहना है कि चीन का खासकर भारत के प्रति रिश्ता बेहद आक्रामक और दबाव बनाने वाला है। इसी के तहत उसने सीमा पर तनाव को देखते हुए तिब्बत और शिंजियांग सैन्य जिलों से सैनिकों को लाकर पश्चिमी चीन में तैनात कर रखा है। पेंटागन का यह भी कहना है कि चीन ने पिछले साल चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच के विवादग्रस्त क्षेत्र में 100 घरों का एक गांव बसाया है। अमेरिका के इस खुलासे में सच्चाई है। कई बैठकों के बावजूद चीन ने डेपसांग घाटी और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई इलाकों से अपने सैनिक हटाने से मना किया है। उससे भी बदतर यह कि हाल ही में एक कानून बनाकर उसने सीमा के गांवों को भारतीय सैनिकों के खिलाफ एकतरफा कदम उठाने को अधिकृत कर दिया है। दोतरफा वार्ताओं के बीच चीन के इस रवैये से परेशानी ही बढ़ेगी। भारत-अमेरिका रिश्तों को पटरी से उतारने की चीनी कोशिश अर्थहीन है, क्योंकि इन दो लोकतंत्रों के बीच मजबूत संबंध दशकों की आपसी समझ-बूझ से बने हैं।

घरेलू महिलाओं की उपेक्षा खतरनाक

देश में संवेदनशील मुद्दों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तभी जोर पकड़ती हैं, जब वे स्वार्थ सिद्धि के साधक नजर आते हैं, अन्यथा गंभीर विषय भी ताक पर रख दिए जाते हैं। भारत की गृहिणियां अवसाद में हैं। उनकी आत्महत्या दर किसानों से दोगुनी है, पर शायद इस तथ्य से कोई भी विचलित नहीं है। हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट, 2020 में खुलासा हुआ है कि बीते दशकों में घरेलू महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। 2020 में भारत में हुई कुल आत्महत्याओं में किसानों का हिस्सा 7 प्रतिशत था, वहीं घरेलू महिलाओं का हिस्सा 14.6 प्रतिशत। देश में आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में दूसरे स्थान पर महिलाएं हैं और किसानों का स्थान सातवां है। यह स्थिति पिछले कई वर्षों से निरंतर कायम है, परंतु फिर भी राजनीतिक मंचों से चर्चा सिर्फ किसानों की आत्महत्या की ही क्यों होती है? शायद इसलिए कि महिलाओं की आत्महत्या पर बात करने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला। यह संवेदनशीलता नितांत एकपक्षीय क्यों? वर्ष 2020 में कुल 5,579 किसानों ने आत्महत्या की जिसमें 244 महिलाएं किसान थीं, क्या उनकी आत्महत्या विचारणीय नहीं है? इस पर निश्चित ही विचार किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि भारत में घरेलू महिलाओं की आत्महत्या दर वैश्विक औसत दर की दोगुनी से भी अधिक है। ये आंकड़े उन शोधों को गलत ठहराते हैं, जिनका निष्कर्ष यह है कि महिलाएं विवाहित होने पर कहीं अधिक सुरक्षित हो जाती हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विवाहित लोगों में आत्महत्या की दर उसी आयु के अविवाहित लोगों की तुलना में कम है। आमतौर से घरेलू महिलाओं में आत्महत्या की ऊंची दर के लिए लैंगिक भेदभाव को जिम्मेदार ठहराया जाता है, परंतु ऐसे कई और भी कारण हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। सितंबर 2018 में 'द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी' में बताया गया था कि दुनियाभर में महिलाओं की आत्महत्या का सीधा संबंध घरेलू हिंसा से है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 15 से 49 साल के आयु वर्ग में 29 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने अपने जीवन साथी से हिंसा झेली है और इसी आयु वर्ग की गृहिणियां सबसे अधिक आत्महत्या करती हैं। यह बहुत चिंतित करने वाला रुझान है।

आत्महत्या को निजी मामला मानने की सोच मिथक है, क्योंकि वास्तविकता इससे इतर है। आत्महत्या सामाजिक दबाव का वह प्रतिफल है, जो ऐसी परिस्थितियों से निर्मित होता है, जहां व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने जैसे कदम उठाने के लिए विवश हो जाता है। यह धारणा सही नहीं कि घरेलू महिलाओं का जीवन मानसिक तनाव से दूर, घर की चारदीवारी के भीतर सुकून से भरा दिखाई देता है। यह भी एक तथ्य है कि कामकाजी महिलाएं घर और दफ्तर के बीच संतुलन स्थापित करने की जद्दोजहद में घरेलू महिलाओं की अपेक्षा अधिक संघर्ष और तनाव भरा जीवन जी रही हैं। इन सबके बीच गृहिणियों के अस्तित्व को नकार दिया जाता है। इस तरह घरेलू महिलाओं की संवेदनाएं न केवल उपेक्षित कर दी जाती हैं, बल्कि उनकी परेशानियों को उनका मानसिक विकार समझते हुए उन्हें परिवार के सदस्यों से अवहेलना मिलती है।

दुखद पहलू यह है कि घरेलू महिलाओं की मनोस्थिति के संबंध में न चिकित्सीय स्तर पर और न ही सामाजिक स्तर पर चिंतन किया जाता है। 'घर पर निठल्ले बैठे रहने' का उलाहना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हरेक घरेलू महिला को समय-समय झेलना पड़ता है। यह उनके मानसिक संत्रस का एक बड़ा कारण है। उच्च शिक्षित व्यक्ति को अगर लगातार यह अहसास कराया जाए कि उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है तो उसका अवसाद में जाना निश्चित है और यही स्थिति भारतीय घरेलू महिलाओं की भी है। उनके श्रम को न तो सरकारें और न ही हमारा समाज मान्यता देता है। जबकि आक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं और लड़कियों के घरेलू काम का सालाना मूल्य कम से कम 19 लाख करोड़ रुपए के बराबर होगा। उनके काम को कम आंकना असंवेदनशीलता नहीं तो और क्या है? आत्महत्या पर किए गए विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि 80 प्रतिशत मामलों में पीड़ित महिलाएं अवसाद ग्रस्त थीं। दरअसल अल्पायु में विवाह और उसके तुरंत बाद मातृत्व का अनचाहा बोझ जब उन्हें बंधनों में जकड़ लेता है तो महिलाएं अवसाद का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि युवावस्था में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

शादी के बाद अपनों की उदासीनता

विवाहित महिलाओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी जुड़ा हुआ है कि विवाह के पश्चात उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में सहभागिता तो दूर निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भरता उनके भीतर हीनभावना भरती है। अवसाद का एक बड़ा कारण दो व्यक्तियों के मध्य तुलना भी है। ऐसी तुलना का सामना देश की हरेक घरेलू महिला को करना पड़ता है। उनकी तुलना उन्हीं के समकक्ष शिक्षित, परंतु कामकाजी महिलाओं से की जाती है और उन्हें कमतर सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है। निरंतर मिलने वाली उपेक्षाएं और अकेलापन उन्हें कई बार यह सोचने पर विवश कर देता है कि उनके परिवार को उनकी आवश्यकता नहीं है। यही भावनाएं आत्महत्या का कारण बनती हैं। घरेलू महिलाओं की सामाजिक भूमिका की अवहेलना समाज को घातक दिशा की ओर ले जा रही है। वे परिवार की धुरी हैं, लेकिन उनकी मुखिया नहीं, बल्कि उपेक्षित हैं।

जीवन संवारता है रामचरितमानस

श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो मानव के लोक और परलोक दोनों को संवारता है। जीवनकाल में मानस बेहतर जीवन व समाज की रचना के लिए प्रेरित करता है। रामचरितमानस में भगवान श्रीराम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखें।

नाथ दैव कर कवन भरोसा।
सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥
कादर मन कहुं एक अधारा।
दैव दैव आलसी पुकारा।।

रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय का प्रसंग बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मणजी ने तब भगवान रामजी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय-विनय क्यों? भगवान राम यह सब जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे।

बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ।
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ।

इस चौपाई में बालकांड का प्रसंग बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहां भगवान शिव कहते हैं- कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है, तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, जो अहंकार करते हैं। वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते।

काम, क्रोध, मद, लोभ, सब,
नाथ नरक के पंथ।
सब परिहरि रघुबीरहि,
भजहुं भजहिं जेहि संत।

विभीषणजी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्यागकर भगवान का नाम जपते हैं आप भी राम के हो जाएं। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख, शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए।

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी।
तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥
निज दुख गिरि सम रज करि जाना।
मित्रक दुख रज मेरु समाना॥

रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं।

बेहतर लिखने की बात हो, या बोलने की, आखिरकार भाषा ही हमारे काम आती है। भाषा को संवारने के लिए जरूरी है कि हमारे शब्द-भंडार ठीक-ठाक हों। इस लिहाज से देखें, तो 'रामचरितमानस' एकदम बेजोड़ साहित्य है। तुलसीदासजी की इस रचना को अगर हम धर्म, नैतिकता, मर्यादा, कथा- इन सभी से अलग रखकर देखें, फिर भी यह हिंदी सुधारने और संवारने के लिए एकदम सटीक रचना है। किसी तरफ से एकाध पेज पढ़कर भी आप 'बाबा' के भाषा ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। इस बात को एक उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है।

मान लें, किसी बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा करने के लिए आपसे 'समुद्र' के लिए कुछ पयार्यवाची शब्द (समान अर्थ रखने वाले शब्द) पूछ डाले, तो आप उसे क्या-क्या बताएंगे और उसे यह किस तरह रटाएंगे? अगर आप थोड़ा वक्त निकालकर मानस के पन्ने उलट-पलट करते रहेंगे, तो शब्दों की कमी कभी पास नहीं फटकेगी। लंकाकांड के सिर्फ एक दोहे में ही समुद्र के एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, सात नहीं, पूरे दस-दस पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। चूंकि ये गेय (गाने योग्य) हैं, इसलिए इन्हें याद रखना भी बेहद आसान है। देखिए वह चौपाई...

बांध्यो बननिधि नीरनिधि
जलधि सिंधु बारीस।
सत्य तोयनिधि कंपति
उदधि पयोधि नदीस।।

लंकापति रावण को जब यह खबर मिली कि समुद्र पर पुल बना दिया गया है, तो उसके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। इसी आश्चर्य में वह अपने दसों मुंह से कहने लगा कि क्या समुद्र को सचमुच बांध लिया गया है? ऊपर के दोहे में 'बांध्यो' और 'सत्य' को छोड़कर बाकी सभी शब्द समुद्र के लिए ही आए हैं। इस तरह अब आपके पास समुद्र के लिए हैं इतने सारे शब्द- वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ज्यों-ज्यों आप इसमें गोते लगाते जाएंगे, थोड़ा और गहराई में उतरने का आपका उत्साह दिनोंदिन बढ़ता जाएगा। इस ग्रंथ का पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप इसका वह संस्करण अपने पास रखें, जिसमें भावार्थ दिए गए हों।

● **ओम**

सूरज तेरे मुखड़े का अनुयाई है

तेरी लट से ही तो रात चुराई है।
सूरज तेरे मुखड़े का अनुयाई है।
मौसम तेरे सांसों से ही बनते हैं।
दिन और रात तेरे नयनों से चलते हैं।
फूल खिले हैं पत्तों की शहनाई है।
सूरज तेरे मुखड़े का अनुयाई है।
जब तू शबनम ऊपर रूक-रूक चलती है।
धूप सुनहरी कैसे-कैसे ढलती है।
शांत समुंदर में जितनी गहराई है।
सूरज तेरे मुखड़े का अनुयाई है।
मीठी बाणी तेरे लब की उल्फत है।
चांद सितारों की जग में शोहरत है।
कृतज्ञता में अम्बर की ऊंचाई है।
सूरज तेरे मुखड़े का अनुयाई है।
झील किनारे चन्द्रमा का मेला है।
खेवनहारा किश्ती साथ अकेला है।
हुस्न तिरे की ऐसी राहनुमाई है।
सूरज तेरे मुखड़े का अनुयाई है।
लेकर भव्य अलौकिक श्रृंगार खुदाने।
उस में डाला अंतरंग मनुहार खुदाने।
तेरी चाहत से ही प्रीत बनाई है।
सूरज तेरे मुखड़े का अनुयाई है।
चौरासी लाख जून में ऐसा होता है।
कोई हंसता है तो कोई रोता है।
'बालम' तेरी उल्फत का शौदाई है।
सूरज तेरे मुखड़े का अनुयाई है।

- बलविन्दर 'बालम' गुरदासपुर

मिर्ची लग गई

रमन का लंच के समय अचानक ही आज फोन आ गया और एकदम सकपकाते हुए बोले - कई दिन हो गए, सोच रहा था कि कैसे कहूं!! पर आज तो जुबान ही नहीं मानो आत्मा भी जल गई मेरी लक्षिता।'

'मन-ही-मन मैं मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि आखिर छटपटा ही गए जनाब! किन्तु चेहरे पर प्रश्नसूचक भाव लेकर अनभिज्ञ दृष्टि के साथ मैंने कहा कि क्या हुआ किससे जुबान जल गई तुम्हारी? बताओ तो सही!'

रमन- 'अरे लक्षिता तुमसे नाराज होकर मैं एक हफ्ते से बाहर से खाना मंगाकर खा रहा हूं, शो ऑफ के चक्कर में, पर आज इतनी मिर्च लग गई कि हारकर मुझे तुमसे बात करनी पड़ी।'

'अरे! तुम्हें पता तो है तीखे का चलन है। बाहर लोग खाते भी तीखा हैं और निभाते भी तीखा हैं। तुम्हें तो पहले ही अक्ल आ जानी चाहिए थी, अब लग गई मिर्ची तो आ गए वापिस।' - लक्षिता ने जवाब दिया।

'अरे बाबा! मैं जला जा रहा हूं भीतर से और तुम हो कि... कुछ तो उपाय करो' - रमन बोला

'चटपटा खाने-खिलाने का शौक है तो मिर्ची खुद को भी तो लग सकती है, उससे कैसे और कब तक बचोगे! मियां जी सहने की भी हिम्मत रखो। सादा जीवन जीकर, सादा भोजन खाकर तुम्हें तो कभी स्वाद ही न आता था, बस चल दिए लाग-लपेट वाले अनगिनत मसालों का स्वाद लेने। जिन्होने खिलाया उन्हें क्यों नहीं फोन लगाया तुमने!' - लक्षिता हंसते हुए बोली।

'अरे! भाई पहले ही तन-बदन आत्मा जल रही है, क्यों तुम भी इतनी मिर्ची उढ़ेल रही हो। कहीं तुम्हारी भी तो किसी तीखी मिर्च वालों से दोस्ती तो नहीं हो गई इतने दिनों में! सच-सच बताना! जल्दी

बोलो, कहीं तुमने भी तो नहीं खाया इसे!' - रमन ने घबराते हुए कहा।

लक्षिता तपाक से बोली - 'न बाबा न! भगवान बचाए। न हम ऐसा तीखा खाना खाते हैं और न ही हमें मिर्ची लगती हां!' हम तो सादे खाने में ही संतुष्टि रखते हैं। वैसे ये मिर्ची तो आजकल कॉमन है एक-न-एक दिन उन सभी को लगती है, जो तीखा खाने से परहेज नहीं करते, भले ही चोरी से खाएं, झूठ बोलकर खाएं, छिपकर खाएं, ये इतने आदी हो जाते हैं कि इन्हें होश ही नहीं कि दूसरों के हिस्से का भी खाए जा रहे हैं, शो ऑफ में मरते हैं फिर रोते हैं। जब तेज मिर्च लग जाती है बेतहाशा तो सीधा काम तमाम ही होता है।

अच्छा हुआ तुमने समय रहते मुझे फोन कर लिया। आज से ही शुरू कर दो सादा खाना, लंबा जिओगे और तुम्हारे जितने मित्रो को मिर्च लग रही है तीखे खाने से उन्हें भी समझाओ। वरना तो राम ही रखवाला है।'

- भावना अरोड़ा 'मिलन'

मूर्ति शिल्पकारी

एक थका-मांदा शिल्पकार लंबी यात्रा के बाद एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गया। अचानक उसको सामने पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, नवरात्रे आने वाले हैं, माता की मूर्तियां बना बाजार लगाऊंगा और अच्छी कमाई होगी। घर आकर उसने उस सुंदर पत्थर के टुकड़े को उठा सामने रखा और औजारों के थैले से छेनी-हथौड़ी निकालकर उसे तराशने के लिए जैसे ही पहली चोट की, पत्थर छुट कर दूर गिर गया। ये सब देख उसकी बेटी भी साहस बढ़ाने लगी। दोनों उस पत्थर पर बारी-बारी चोट करते रहे। आखिर उन्होंने उस पत्थर को बहुत ही खूबसूरत देवी का रूप दे दिया। पिता शिल्पकार हंसती हुई दुर्गा की प्रतिमा बनाना चाहता था। बेटी उसकी कालरात्रि रूप में बनाना चाहती थी। दोनों की इस बात पर बहस हो गई। पिता बोला, तूं जा मुझे काम करने दे काली, कुलक्ष्मी..जा दूर जा! और सिगरेट पीने

लगा। रात को दारू पीकर उसने फिर से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। बेटी पिता से लड़ पड़ी, लोग खरीद पूजा करेंगे, पिताजी आप मूर्ती नशे में लिपत हो रहे हो। पिता शिल्पकार, देवी भी पीती थी और अब मैं देवी मां के चेहरे पर अच्छे भाव ला सकूंगा। शिल्पकार की पत्नी दोनों को डांट कर बोली, दोनों झगड़ा करते मूर्ति बना रहे हो ऐसा ही भाव मूर्ति के चेहरे पर भी आएगा। जा बेटी अंदर से देवी माता की फोटो सामने रख फिर मूर्ति ठीक बनेगी। अब शिल्पकार का क्रोध सीमा ही पार कर बैठा। वो उठ खड़ा हुआ और पास पड़ी एक संटी फेंक मारी। जबान चलाती है? मूर्तिकार को क्रोधित देखकर उसकी पत्नी दूर हो गई और बेटी प्रेम भाव से सात्विक भावना लिए हृदय मूर्ति के माध्यम से रंग भर शिल्पकारी में मस्त सी थी।

- रेखा मोहन

विराट कोहली के बाद अब रोहित शर्मा को टी-20 की कप्तानी दी गई है। रोहित शर्मा एक बेहतर बल्लेबाज के साथ ही बेहतर कप्तान भी साबित हुए हैं। लेकिन भविष्य की तैयारियों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि रोहित शर्मा कुछ ही दिन के लिए कप्तान होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं।

रोहित शर्मा कुछ दिन के कप्तान

अच्छे दिन आते हैं और सबके आते हैं। बस जरूरी है कि जिसके आए हैं वो मेहनती तो हो ही साथ ही उसकी किस्मत भी बुलंद होनी चाहिए। यूं भी कहा यही गया है कि सफलता के दो ही मूलमंत्र हैं, पहला मेहनत। दूसरा भाग्य। बड़े बुजुर्गों का तो इस मामले में यहां तक कहना है कि मेहनत और किस्मत में से कोई भी एक तत्व घट जाए या बढ़ जाए तो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है लेकिन सफल हरगिज नहीं। इन बातों को ध्यान में रखिए और टीम इंडिया के दिग्गज ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा का रुख कीजिए। रोहित मेहनती तो हैं ही साथ ही उनकी किस्मत भी बुलंद है और शायद यही वो कारण है कि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ के फेवरेट रोहित शर्मा की पांचों उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में है। मौजूदा समय में रोहित टी-20 टीम के कप्तान हैं। ध्यान रहे अभी हाल ही में बीते टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शर्मनाक हार का ठीकरा कप्तान कोहली के सिर पर फोड़ा गया था। जिसके बाद उन्होंने टी-20 की कप्तानी छोड़ दी थी। रोहित अपनी मेहनत से खुद को सिद्ध कर चुके हैं साथ ही भाग्य भी उनके साथ था इसलिए टी-20 टीम की कप्तानी के लिए 34 साल के रोहित सबकी पहली पसंद बने। शेष हमारे सामने है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोहित बहुत ज्यादा दिनों तक क्रिकेट के इस फॉरमेट में कप्तानी नहीं कर पाएंगे।

हैरत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। है कोई जो उनकी जगह लेने को बेकरार है। दिलचस्प ये कि उस शख्स ने न केवल अपने गेम बल्कि अपनी निर्णायक क्षमता के कारण पहले ही सिलेक्टर्स के दिल में खास जगह बना रखी है। जैसा कि हम बता चुके हैं आज भले ही रोहित शर्मा टी-20 टीम के कप्तान है और बहुत ज्यादा दिनों तक कप्तानी उनके साथ नहीं रहेगी तो ये बातें यूं ही हवा में नहीं कही गई हैं। इनके पीछे मजबूत तर्क हैं। ध्यान रहे उम्र के लिहाज से रोहित 34 साल के हैं। जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट का इतिहास है 34 साल वो उम्र है जब अधिकांश खिलाड़ी गिरती फिटनेस का शिकार होते हैं और अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। चूंकि टी-20 फॉरमेट युवाओं या ये कहें कि कम उम्र के खिलाड़ियों का फॉरमेट है इसलिए प्रबल संभावना है कि जल्द ही रोहित या तो टी-20 कप्तान का पद छोड़ देंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा।

रोहित के साथ यदि किसी तरह की कोई भी अनहोनी होती है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये कि आखिर उनकी जगह लेगा कौन? ज्ञात हो कि टीम इंडिया के पास पहले से एक खिलाड़ी ऐसा मौजूद है, जो रोहित के बाद लंबे समय तक टी-20 फॉरमेट में कप्तान की जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकता है। जिस खिलाड़ी की बात हम कर रहे हैं वो टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं।

माना यही जा रहा है कि ऋषभ पंत का शुमार उन चुनिंदा लोगों में है जो रोहित के बाद टीम को संभाल सकते हैं। उम्र के लिहाज से पंत महज 24 साल के हैं। 24 साल की उम्र में जिस तरह पंत ने आईपीएल में कप्तानी की है वो काबिल-ए-तारीफ है। बहुत ही कम समय में टीम इंडिया में खास मुकाम हासिल कर चुके पंत युवा हैं। अभी बहुत सा क्रिकेट न केवल उन्हें खेलना है, बल्कि उनके अंदर बाकी भी है।

कहा तो यहां तक जा रहा है कि यदि मौका दिया जाए तो ऋषभ पंत टीम इंडिया को उस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जो आपकी और हमारी सोच और कल्पना दोनों से परे हैं। क्रिकेट जैसे खेल में फॉरमेट भले ही कोई हो लेकिन खिलाड़ी की टाइमिंग मायने रखती है। ऐसे में जब हम ऋषभ पंत के गेम और उनकी टाइमिंग को देखते हैं तो एक बार के लिए भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई 24 साल का खिलाड़ी मैदान में है और इस हद तक सधी हुई पारी खेल रहा है।

तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो मुखर होकर इस बात को कहते हैं कि बतौर कप्तान ऋषभ पंत एक बेहतरीन विकल्प हैं। बात ऋषभ पंत की चली है तो ये बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आईपीएल 2021 में ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी जिस अंदाज में की थी उसने सभी क्रिकेट फैंस का मन मोह लिया था। ये ऋषभ की कप्तानी का ही परिणाम था कि दिल्ली लीग मैचों के बाद अंक तालिका में टॉप पर रही। हालांकि क्वालीफायर के दोनों मैचों में इस टीम को हार झेलनी पड़ी। फिर भी पंत ने पहली ही बार में दिखा दिया कि वो कप्तानी कैसे कर सकते हैं। चाहे वो साथी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना हो या खुद का खेल, पूरे आईपीएल में अपनी रणनीति से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था।

बहरहाल बात रोहित शर्मा पर चली थी, उनकी कप्तानी पर चली थी, उनकी उम्र पर चली थी तो जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं को तरहजीह दी जा रही है साथ ही ऋषभ पंत जैसे युवा जिस तरह अपने गेम और फिटनेस पर काम कर रहे हैं अच्छे दिन आने के बावजूद रोहित के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। सवाल ये है कि इन चुनौतियों से कैसे रोहित खुद को पार लगाएंगे? बाकी आने वाला वक्त टीम इंडिया के मद्देनजर रोहित और ऋषभ पंत दोनों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। रोहित को जहां एक तरफ अपनी कप्तानी बचानी है तो वहीं ऋषभ के सामने चुनौती ये है कि वो कप्तानी पर कैसे कब्जा करें।

● **आशीष नेमा**

विक्की डोनर साइन करने के बाद पेरेंट्स ने यामी से पूछा था- किस बारे में है ये फिल्म?

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने 2012 में फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह आयुष्मान खुराना के अपोजिट नजर आई थीं। अपनी डेब्यू फिल्म में ही यामी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था क्योंकि इस फिल्म का सब्जेक्ट आम बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले थोड़ा अलग था। फिल्म इनफर्टिलिटी और स्पर्म डोनेशन जैसे सब्जेक्ट पर थी जिसे इंडियन सोसाइटी में टैबू माना जाता है। एक इंटरव्यू में यामी ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था, वो ऐसा दौर था जब मैं जबरदस्त तरीके से ऑडिशन दे रही थी। उस वक्त मेरे पर टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल की फिल्म से डेब्यू करने की चॉइस थी। मैंने सबकुछ अपने दम पर किया, उस समय मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था। जब मैंने विक्की डोनर के लिए ऑडिशन दिया तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा कि फिल्म किस बारे में है? कास्टिंग डायरेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दीं।

जब मुझे फिल्म मिली तब मुझे इसके सब्जेक्ट के बारे में मालूम चला। पेरेंट्स को यह बात बतानी जरूरी थी। मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि फिल्म किस बारे में हैं और मैंने उन्हें फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट थमा दी। जब मेरे पेरेंट्स ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनका रिएक्शन था-यह बहुत बेहतरीन है। फिल्म जबरदस्त सक्सेसफुल रही और इसने आयुष्मान और यामी के कैरियर को ऊंचाई दी। इसके बाद यामी ने बदलापुर, काबिल, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक और बाला जैसी फिल्मों में काम किया।

बिना शादी के ही पिता बन गए अर्जुन रामपाल

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर, 1972 को जबलपुर में हुआ था। वह मिलिट्री बैकग्राउंड की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके नाना ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने इंडियन आर्मी के लिए पहली आर्टिलरी गन बनाई थी।

बॉलीवुड में जगह बनाने से पहले अर्जुन सक्सेसफुल मॉडल थे। पॉपुलर फैशन डिजाइनर रोहित बल ने अर्जुन को एक पार्टी में देखा और उनके लुक्स देखकर काफी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने अर्जुन के मॉडलिंग कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद की।

2001 में अर्जुन ने फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए अर्जुन को कई डेब्यू अवॉर्ड्स मिले। 2008 में आई रॉक ऑन के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा गया। अर्जुन ने 1998 में सुपरमॉडल मेहर जेसिया से शादी की। दोनों की दो बेटियां है- महिका और मायरा। महिका का जन्म 2002 में जबकि मायरा का जन्म 2005 में हुआ था। अर्जुन-मेहर की शादी 21 साल चली, 2019 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अर्जुन साउथ अफ्रीकन मॉडल गैब्रिएला के साथ लिव इन रिलेशन में हैं। गैब्रिएला अर्जुन से 14 साल छोटी हैं। 18 जुलाई, 2019 को दोनों एक बेटे एरिक के माता-पिता बने हैं।

होंठ पर बॉल लगने से लेट हुई थी शाहिद की जर्सी

शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हाल ही में शाहिद ने एक वीडियो में खुलासा किया है कि इस फिल्म को उन्होंने अपना खून दिया है। दरअसल प्रैक्टिस सीजन के दौरान शाहिद के निचले होंठ पर बॉल लग गई थी। इसके चलते उन्हें 25 टांके लगे, साथ ही 2 महीने के लिए शूटिंग भी रोकनी पड़ी थी। क्रिकेट पर बनी यह फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज हो रही है।

इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान शाहिद ने खुलासा किया कि प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने अपना हेलमेट नहीं पहना था। चोट लगने के बाद शाहिद इस बात से इतने चिंतित थे कि उनके होंठ पर लगी चोट के कारण वे फिर कभी पहले जैसे न दिख सकेंगे। शाहिद ने आगे बताया कि उनके होंठ को सामान्य होने में तीन महीने लग गए लेकिन वो अभी भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। अल्लू अरविंद की जर्सी का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता गौतम तिन्ननुरी ने किया है, जिन्होंने फिल्म के ओरिजनल तेलुगु संस्करण के लिए पुरस्कार जीता था। अमन गिल, दिल राजू और एस नागा वामसी द्वारा निर्मित जर्सी 31 दिसंबर को रिलीज होगी।

उसका पसंदीदा देश

उसे वह देश बहुत ज्यादा पसंद था। वह इसे अपनी खुशकिस्मती मानता था कि वह उसी देश में पैदा हुआ था।

इसके पीछे बहुत सटीक कारण भी था। उस देश में पूरी आजादी थी और पूरा न्याय। खास कर के आजादी। हर चीज की आजादी और हर आदमी को आजादी। यहां तक कि हर संस्था, संगठन, इकाई को भी पूरी स्वतंत्रता। यानि कि जिसकी जो इच्छा हो वह बके। जिसे जो गरियाना हो गरियाए। जिसे जहां जिस रूप में बहकना हो बहके। इस तरह से आदमी के रूप में जन्म लेने पर जिस तरह की आजादी की संकल्पना कई बड़े-बड़े विद्वानों और मनीषियों ने की थी वह सारा का सारा उस देश में नजर आ जाता था।

फिर केवल बोलने की ही आजादी नहीं थी। सब कुछ करने की भी आजादी थी। जी हां, जो मन हो कीजिए। सरेआम कत्ले-आम। हां भाई, कोई रोक-टोक नहीं। अकेले में मारें या सरेआम में- यह आदमी की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर था। किस हथियार से मारे, किस जगह पर मारे, किस तरह से मारे इन सारी बातों की उसे पूरी आजादी थी।

एक और अच्छी बात जो वहां थी वह यह कि वहां की समस्त शासकीय व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से आजादी की भावना से अनुप्राणित थी। अधिकारी आजाद, कर्मचारी आजाद। आजाद हर रूप में- इच्छा हुई काम किया, नहीं इच्छा हुई, नहीं किया। इच्छा हुई तो फाईल रखा, इच्छा हुई फाईल उठाकर फेंक दिया। बड़ी आजाद व्यवस्था थी, बड़े आजाद ख्याल थे। मन हुआ देश की बातें की, मन हुआ तो आजादी का नारा देने लगे। और ऊपर से कहते थे यह सब सुदूर स्थित भारत देश की महान विभूति महात्मा गांधी के ही सिद्धांतों के अनुपालन में हो रहा है। उन लोगों का मानना था कि वे गांधी की रामराज्य की भावना से पूरी तरह प्रभावित और अनुप्राणित थे और वास्तव में उस महापुरुष के उपकृत थे जिन्होंने ऐसा दिव्य-दर्शन प्रदान किया जिसे हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से अपनी-अपनी समझ के अनुसार और अपनी-अपनी जरूरतों के अनुरूप उपयोग कर सकता था और लगातार करता भी रहता था।

एक अद्भुत देश जिसका मूल वाक्य था- देर है पर अंधेर नहीं। अत: लगातार जल्दीबाजी की कच-कच को उस देश में पसंद नहीं किया जाता था। बल्कि जो ज्यादा जल्दी में होता उसे जल्दी-जल्दी ऊपर भेज दिया जाता ताकि उसकी जल्दी की इच्छा एक ही बार में पूरी कर दी जाए।

एक और बात उस देश में बहुत अच्छी थी कि वहां के एक बड़े समुदाय को वहां की न्यायपालिका पर भीषण आस्था थी। इस आस्था के कारण भी थे। वहां की न्यायपालिका इस मत की थी कि उसके दरवाजे पर आना तो आने वाले

एक अद्भुत देश जिसका मूल वाक्य था- देर है पर अंधेर नहीं। अत: लगातार जल्दीबाजी की कच-कच को उस देश में पसंद नहीं किया जाता था। बल्कि जो ज्यादा जल्दी में होता उसे जल्दी-जल्दी ऊपर भेज दिया जाता ताकि उसकी जल्दी की इच्छा एक ही बार में पूरी कर दी जाए।

की मर्जी पर है, पर जाना पूरी तरह न्यायपालिका के हाथों में। बल्कि 'अतिथि देवो भव:' की भावना से अनुप्राणित वे लोग जल्दी किसी मुवक्किल को छोड़ते भी नहीं थे जब तक या तो वह स्वाभाविक रूप से दम तोड़ देते थे या किसी बहाने उसका विपक्षी ही हथियार डाल दे। हां, गुस्सा वहां की न्यायपालिका को जरूर बहुत आता था- जल्दी-जल्दी आता था, कई बार तो एक दिन में कई बार आता था। और एक बार जब वे क्रोधित हुए तो पुराने मनीषियों की तरह ताबड़-तोड़ उस देश के और विदेशों के धर्म-शास्त्रों, विधि-शास्त्रों, काम-शास्त्रों, दर्शन-शास्त्रों और ना जाने कहां-कहां से बातें खोज कर बस लिखने ही लग जाते जिससे मूल मुद्दा तो वहीं का वहीं रह जाता और बड़ी-बड़ी दार्शनिक विवेचनाएं शुरू हो जातीं। फिर जब मन हुआ अपने देश की कार्यपालिका को गरियाया, कभी विधायिका को फटकारा और कभी-कभी मूड में आ गया तो अपने नीचे की न्यायपालिका पर भी चढ़ बैठे।

लेकिन ये चढ़ने-उतरने की आदत उस देश में सबों की थी। सब सबसे नाराज थे। नेता अधिकारियों से, अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों से, नीचे के अधिकारी जनता से, जनता नेता से, मीडिया इन सबसे, ये सब लोग मीडिया से। न्यायपालिका मीडिया से भी और बाकी सबसे भी।

एक और बात जो उस देश को विशिष्टता देती थी वह थी उसकी त्वरित निर्णय-क्षमता। कोई बात हुई नहीं की जांच। तुरंत आदेश, आनन-फानन में आदेश। कभी-कभी तो इतनी तत्परता रहती कि गड़बड़ी बाद में होती, जांच के आदेश पहले हो जाते। इसके मूल में बस एक भावना रहती, रहीम की वह बानी जो एक सुदूर मुल्क से चलकर आई थी- 'काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी।'

बहुत ही अच्छा देश था वह, बहुत ही बेमिसाल। सभी आजाद, सभी स्वतंत्र। फिर यदि बाकी की चीजों का अभाव भी था तो क्या, जिंदगी चल ही तो रही थी। उस इंसान की एक ही तमन्ना थी कि यदि कई बार भी जन्म लेना पड़े तो वह उसी देश में जन्म ले। अब बाकी कहीं उसका गुजारा हो पाता भला।

● **अमिताभ ठाकुर**

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल

फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_0/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687